MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS — *Contd.*

SHRI R. S. BHARATHI (Tamil Nadu): Thank you very much, Sir, for allowing me to speak on this Motion of Thanks on the President's Address. Though I thank the President for the Address, I would also point out as to how the State of Tamil Nadu has been totally neglected. Due to paucity of time, I would like to shorten it and say certain words where Tamil Nadu has been totally neglected. In Tamil Nadu, the farmers of delta area are fighting to get water for decades together. Acres of land is dead in delta district for want of Cauvery water. Therefore, Sir, from time immemorial, the State Government as well as the opposition has been representing to the Central Government to take steps to ensure supply of Cauvery water to Tamil Nadu. In spite of the court interference, we are very sad to say that no concrete steps have been taken, and, the hon. President has also not mentioned about it.

Secondly, Sir, my learned friends from Tamil Nadu also spoke about the postponement of NEET examination or exemption from NEET examination for the State of Tamil Nadu. Here, I would like to bring to the notice of the House the history of social justice, which was followed in Tamil Nadu from Justice Party period. Till 1950, because of this reservation, so many people had been benefited, and, after the formation of Constitution in 1950, firstly, in the Chennai High Court, Champakam Dorairajan challenged the G.O. The Madras High Court as well as the Supreme Court said that there will be no communal reservation in Tamil Nadu. Here, I would like to say that since the people of Tamil Nadu were enjoying reservation, there was a movement in Tamil Nadu under the able leadership of Thanthai Periyar, Anna and Kamaraj, which made the Government of India Act. Here, I would like to mention, Sir, the first amendment to the Constitution was brought because of the agitation by the Tamil Nadu people against the cancellation of reservation and communal G.O.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

Since then, for the last 68 years, we have been enjoying reservations which have been now struck down in the NEET examination imposed by the Central Government. Here, I would like to mention that the State Government has passed a Resolution unanimously and sent the same to the President. Last year, there were so many representations. Under the leadership of our leader, Shri M. K. Stalin, we met the President and made a representation that the Resolution passed by the State Government should be immediately responded. There are no two opinions that all the people are for the Resolution. In spite of that, the President has not given his assent. My learned friend, Mr. T. K. Rangarajan, wrote a letter to the hon. President and he received a letter stating that the President's office had not received any such communication from the Central Government. Therefore, I blame the Central

[Shri R. S. Bharathi]
Government for not sending such a sensational Resolution to the President of India.

Last year, some Ministers came from the Centre telling the people of Tamil Nadu about this. This year, there is the NEET exam. We are relying upon that. People are being fooled. Last year we had been deprived. Now, since they are going to have the entrance exam on May 9th, through you, I would like to request the hon. President, at least, to call the records and sign it and let the people of Tamil Nadu enjoy the fruits of the Resolution which has been in existence for more than 70 years fought by our great Periyar, Arignar Anna, Kamaraj and leaders like them. Therefore, once again, I would like to say about this.

My learned friend, Mr. Navaneethakrishnan, pointed out the legal aspects. Since I do not have much time, I do not want to go into that. People are very much agitated about this, Sir. Likewise, the poor farmers were on the streets of Delhi for more than six months. The sorry state of affairs is that the Prime Minister, in spite of their begging, did not give them an appointment, did not even meet them. So, Sir, I would request the Central Government to kindly waive the farmer loans, bring water to delta areas and save the farmers.

Likewise, Sir, the President has mentioned about triple talaq. He says that the women folk are very much happy about it. But, unfortunately, the reality is not so. So many associations of the Muslim community are raising their voice and protesting against this. They are interested about the women of the Muslim community. What about the entire women community? This House has passed Bill for reservation to the women community. The Bill was unanimously passed in this House, but the Lok Sabha has still not passed it. What is the reason? There is no meaning in saying that we want to help the women. It is like, as was pointed out earlier, they are just shedding crocodile tears. They are not doing anything for them. If at all they wanted to do anything, they should have passed it in the Lok Sabha. They have got a very big majority in the Lok Sabha. Why are they hesitating? They don't have the will.

With this, Sir, I would like to conclude. I would like to thank the President for his speech, Sir. Thank you.

श्री अहमद पटेल (गुजरात): माननीय उपसभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावक ने एक बहुत ही गुलाबी चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की है और कहा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सलामत है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि सब कुछ ठीक नहीं है और सब कुछ सलामत

भी नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा असलामती की भावना, feeling of insecurity आज देश में है, चाहे वह सामाजिक ढांचे की बात हो, हमारे social fabric की बात हो, आर्थिक मामलों की बुनियादी बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो या हमारे गणतंत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक संस्थाओं की बात हो अथवा हमारे जो independent Constitutional institutions हैं, उनकी बात हो। जो उत्साह प्रस्तावक ने दिखाया है, मैं समझता हूँ कि वह उत्साह उनके जो सहयोगी हैं, उनकी तरफ से नहीं दिखाया गया है। महाराष्ट्र के उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार असत्य बोल रही है और 2019 का चुनाव हम साथ मिल कर नहीं लड़ेंगे। आंध्र के सहयोगी ने कहा कि आप अपनी बात से मुकर गये हैं। पंजाब के सहयोगी ने कहा कि अगले चुनाव में 272 का आंकड़ा पार करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार की ओर से जो बार-बार कहा गया है... जब प्रस्तावक बोल रहे थे, जब वे गुलाबी चित्रण प्रस्तुत कर रहे थे, तब उन्होंने तो बार-बार बीजेपी सरकार कहा, एक बार भी यह नहीं कहा कि मोदी सरकार है, मेरे ख्याल से एक या दो बार एनडीए सरकार की बात की। आप यह क्लीयर करें कि यह सरकार बीजेपी सरकार है या मोदी सरकार है या एनडीए सरकार है, तीनों में से कौन-सी सरकार है?

महोदय, उसके बाद उन्होंने यह बात की कि जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, वह तो हमारे लिए गड्ढे छोड़ कर गई थी और उनको अब हम भर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई, तब per capita income सिर्फ 24 हजार रुपए थी और जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, तब per capita income 70 हजार रुपए थी। जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी, तब जो हमारा ऋण था, debt था, कर्ज था, वह 50 लाख करोड़ रुपए था, वह आज 73 लाख करोड़ रुपए है यानी कि सिर्फ साढ़े तीन या पौने चार साल में यह 40-42 प्रतिशत बढ़ गया है।

भाजपा की सरकार बनने के तीन महीने के अंदर हमारा मंगलयान मंगल पर पहुंच गया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह गड्ढा था? हमने जो per capita income बढ़ाई, वह गड्ढा था? कौन गड्ढा भर रहा है और कौन गड्ढे खोद रहे हैं, इससे पता चलता है।

महोदय, गुजरात की बात करें। 12 साल तक प्रधान मंत्री जी वहां पर मुख्य मंत्री थे। जब वे वहां से आए, तब 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर आए, जो पहले 43 हजार करोड़ रुपए था तो उन्होंने गड्ढा खोदा या गड्ढा भरा? जब वे गड्ढे की बात कर रहे हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी की सरकार जो गड्ढे खोद कर गई है, उनको भरती है और जब ये आते हैं, तो ये गड्ढे खोदते हैं।

महोदय, जहां तक election के figures का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि साढ़े तीन साल हो गए, ये गिनवा रहे थे कि चुनाव के बाद हमने काफी सरकार बनाई, झारखंड की बनाई, महाराष्ट्र की बनाई, बीच में दिल्ली का जिक्र तो किया, लेकिन भूल गए कि वहां उनकी सिर्फ तीन ही सीटें आई थीं। उसके बाद उन्होंने बाकी सरकारों की बात की, मणिपुर की बात की, गोवा की बात की, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आने के साथ जिस तरह से आपने सरकारें तोड़ने की कोशिश की, चाहे हमारी अरुणाचल प्रदेश की सरकार हो या हमारी उत्तराखंड की सरकार हो। जहां तक मणिपुर का सवाल है, वहां तो बीजेपी के सिर्फ 21 एमएलएज़ आए थे और हमारे 28 एमएलएज़ आए थे। We were the single largest party. गोवा में इनके 13 एमएलएज़ आए

[श्री अहमद पटेल]

थे और हमारे 17 एमएलएज़ आए थे। We were the single largest party और वहां पर इन्होंने सरकारें बनाई। अध्यक्ष जी काफी काबिल हैं, वे बना सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं हैं। किस तरह से सरकार बनाई, किसके सहारे, किनके सहयोग से सरकार बनाई, वह बहुत ही important है। अरुणाचल प्रदेश में उनके सिर्फ 11 एमएलएज़ थे और पूरी की पूरी सरकार उन्होंने अपनी बना ली। क्या यह नैतिकता है? क्या यह morality है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ?

महोदय, जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, जब चुन कर आए, तब इनकी संख्या 282 थी और आज कितने रह गए हैं? आज 273 रह गए हैं और उसके बावजूद यूपी के कुछ by-elections होने हैं, बाकी स्टेट्स के, बिहार के byelections होने हैं, वे वहां अभी भी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। कांग्रेस की संख्या 44 थी, वह अब 48 हो गई है और लोक सभा के जो चुनाव लड़े गए हैं, उनमें सिर्फ एक by-election ही ये लोग जीत पाए हैं, उसके अलावा बाकी जो हैं, या तो कांग्रेस ने जीते हैं या दूसरे दलों ने जीते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देश के लोगों को गुमराह करके, गलत प्रचार करके 282 ले आना आसान है। आपने क्या गलत प्रचार किया था, वह हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं उनको कहना चाहूंगा कि सरकार बना लेना तो बहुत आसान है, लेकिन

"नजर-नजर में उतरना कमाल होता, नफस-नफस में बिखरना कमाल होता है,
बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, लेकिन बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है।"

2019 में इन्हें पता चलेगा कि वे बुलंदी पर हैं या बुलंदी से नीचे गिर चुके हैं। यहां बात की जा रही है simultaneous elections की और उस पर चर्चा भी हो रही है लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। कुछ चीजें जो वे बोलते हैं, जानते हैं कि ये impossible हैं, practicable हैं ही नहीं, उसके बाद भी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पब्लिसिटी करनी है। मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग States के simultaneous या बाई-इलेक्शन simultaneous नहीं करा सकते, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इलेक्शन एक साथ नहीं करा पाए, इसलिए नहीं करा पाए, क्योंकि प्रधान मंत्री जी को रो-रो फेरी का उद्घाटन करना था। notification से पहले उन्होंने यह काम किया। उससे पहले 20 बार प्रधान मंत्री जी वहां गए थे। जब किसानों को पानी की जरूरत नहीं थी, तब नहरें भर दी गईं। जब उन्हें सी-प्लेन उड़ाना था, एक किनारे से दूसरे किनारे तक साबरमती पूरी भर दी गई। गुजरात के चुनाव में इन्होंने क्या-क्या नहीं किया? जब भी चुनाव आता है तो इन्हें पाकिस्तान याद आता है या मुस्लिम चीफ मिनिस्टर याद आता है, ...**(व्यवधान)**... उसके बावजूद भी ये सिर्फ डबल डिजिट में आए, जबकि पहले ट्रिपल डिजिट की बात कर रहे थे कि हम गुजरात में 150 सीटें लेकर आएंगे। ऐसा आश्वासन प्रधान मंत्री जी को भी दिया, दूसरे लोगों को भी दिया, लेकिन उन्होंने तब कहा था कि मैं लिखकर देता हूं कि 150 सीटें आएंगी, आज की डेट एंड टाइम लिख लो। फिर आईं कितनी – केवल डबल डिजिट में। जितनी सीटें आईं, उनमें से सूरत, अहमदाबाद और राजकोट को अगर आप देखें तो इन तीन शहरों में 40-40, 50-50 या 60-60 हजार वोटों से सीट जीते हैं। इनके जीतने का तरीका क्या था, मुझे नहीं मालूम और मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जब गुलाम नबी जी बोले, उससे पहले वे कह रहे थे कि आप कहते हैं कि हम लोग विरोध नहीं करते, लेकिन आपका विरोध करने का जो तरीका है, वह विरोध करने के बराबर है। मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कहते हैं कि हम जीत गए, मैं मानता हूं कि आप जीत

गए, लेकिन जीतने का जो तरीका है, वह हारने के बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि गुजरात में आप जीतकर भी हार गए और हम हारकर भी जीत गए। आप किस तरह से जीते हैं, हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आनन्द शर्मा जी के लिए भी हमें कुछ टाइम रखना है। ...**(व्यवधान)**... अपने लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। ...**(व्यवधान)**...

इनके पास सिर्फ एक ही मंत्र है कि किस तरह से कांग्रेस और गांधी परिवार को गाली दी जाए, बदनाम किया जाए। इन्होंने और बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं यहां सरदार पटेल जी का quote आपके सामने रखना चाहूंगा। वैसे सरदार पटेल का नाम तो ये भूल ही गए, क्योंकि पटेल लोगों के प्रति इन्हें कुछ ज्यादा ही स्नेह है। ...**(व्यवधान)**... मेरा सरनेम भी पटेल है, इसलिए मेरे प्रति भी ज्यादा स्नेह है। ...**(व्यवधान)**... हार्दिक पटेल के प्रति भी ज्यादा स्नेह है और पूरी पटेल कम्युनिटी के लिए ज्यादा स्नेह है। सरदार पटेल ने कहा था कि – "Blaming others is the laziest thing to do. Working hard to make a difference is the toughest thing to do. The lazy ones normally choose the first option. I do not." ऐसा सरदार पटेल कहते हैं। ये उनका नाम तो इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, गांधी जी की भी बात करते हैं, लेकिन वे जो कहते हैं, उनकी बात सुननी नहीं। गुजरात के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्शन में कौन जीता, कौन हारा, कैसे जीता और कैसे हारा, ये पहले कहां थे और अब कहां आ गए — इसमें मैं ज्यादा पड़ना नहीं चाहता। आने वाले वक्त में गुजरात की जनता और पूरे देश की जनता अच्छी तरह से इन्हें बता देगी।

ये गुजरात की बात कर रहे थे कि हमें 41 परसेंट वोट मिले और उन्हें 49 परसेंट मिले, लेकिन पहले आपको कितने परसेंट वोट मिले थे, जो अब घटकर 49 परसेंट पर आ गए। ...**(व्यवधान)**... मैं उसी पर आ रहा हूं। गुजरात रूरल में 109 सीटें थीं। उन टोटल 109 सीटों में से हम 62 सीटें जीते, रूरल एरियाज़ में, जबकि बीजेपी 43 सीटें जीती है। इस तरह रूरल एरियाज़ में तो वे हार ही गए। आप देखें कि आज किसानों की क्या हालत है, रूरल एरियाज़ की क्या हालत है? नर्मदा रिवर सूखी पड़ी है – क्यों सूखी पड़ी है – इसलिए कि चुनाव के दौरान जब पानी की जरूरत किसानों को नहीं थी, तब साबरमती भर दी गई, नहरों का उद्घाटन किया गया और जब नहरों में दरार आ गई, पूरा पानी वेस्ट हो गया, तब किसानों का ख्याल नहीं आया। अभी गुजरात सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि यदि नर्मदा में पानी नहीं है तो किसान इस बार रबी क्रॉप न करें। उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि किसान इस बार रबी क्रॉप पैदा न करें। What a shame! जो पानी था, वह तो बह गया। उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया और बेचारे किसान अब suffer कर रहे हैं। तो बात क्या करनी है और सही मायने में क्या करना है, ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं।

अब ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत ही करप्ट थी। उसने भ्रष्टाचार किया, यह किया, वह किया। इसका जवाब तो इन्होंने दे दिया, लेकिन अगर आप बहुत ही ईमानदार हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, तो फिर आरटीआई को आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? आरटीआई का बजट 60 परसेंट घटा दिया गया और आरटीआई में जो अप्वाइंटमेंट होनी है, वह भी अभी नहीं हो रही है। उसमें अभी 60 परसेंट वैकेंसीज़ हैं। हमारे वक्त में भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। अगर आप बहुत ही ईमानदार हैं, तो लोकपाल लेकर क्यों नहीं आते? वह तो लाना नहीं है। ये लोकपाल भी नहीं ला रहे हैं। गुजरात में लोकायुक्त नियुक्त करने में कई साल लग गए। उसकी वजह यही थी कि

[श्री अहमद पटेल]

वहां पर यह कानून है कि छः साल के बाद आप लोकायुक्त में नहीं जा सकते। हमने भ्रष्टाचार के संबंध में जो भी मेमोरैंडम दिया था, उसकी चर्चा न हो, इसलिए वहां पर लोकायुक्त लेट अप्वाइंट किया। मेरे ख्याल से यहां जो लोकपाल नियुक्त करने की बात है, उसमें यही इनकी नीयत होगी।

"उज्ज्वला स्कीम" के बारे में बहुत कुछ कहा गया। उसमें अभी सिर्फ कनेक्शन दिया गया है। वे बताते हैं कि हमने कितने कनेक्शंस दिए। साढ़े तीन करोड़, पांच करोड़ और फिर आठ करोड़ पर जाएँगे, लेकिन उन कनेक्शंस को देने के बाद आपने कितने सिलेंडर प्रोवाइड किए और कितने लोग सिलेंडर ले रहे हैं? उसमें तो कमी हो रही है, क्योंकि आपकी स्कीम failure है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए और 800 रुपये हो गए, तो वह कहां से लाएगा? उसमें सिर्फ कनेक्शन दिया गया है। उसके लिए पैसे तो उस गरीब महिला को देने हैं। मैं जब रोड पर जाता हूँ, तो देखता हूँ कि वहां सिलेंडर के साथ महिला का और प्रधान मंत्री जी का फोटो लगा हुआ है। वह हरेक जगह लगा है, लेकिन सचमुच में इस बात का सर्वे करना चाहिए कि इन्होंने जो कनेक्शंस दिए हैं, उनमें से कितने लोग अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। They have again gone back to वही अपना चूल्हा और वही अपना तरीका। आप सर्वे कराकर कुछ figures तो निकालिए! वर्ष 2016 में सिलेंडर्स की संख्या में 16.2 परसेंट की वृद्धि हो गई, लेकिन अब वृद्धि की वह दर केवल 9.8 परसेंट है। हम जानते हैं कि उसके दाम बढ़ गए हैं, लेकिन उसके साथ-साथ यह सर्वे होना चाहिए कि इन्होंने जो कनेक्शंस दिए हैं, उसका इस्तेमाल अभी कितनी महिलाएं कर रही हैं। उससे पता चलेगा कि यह स्कीम सचमुच में सफल रही है या फेल हो गई है।

जो दो-तीन मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि उनकी performance बहुत ही अच्छी है। उनमें सबसे ज्यादा परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि हम 24 किलोमीटर सड़क हर रोज बना रहे हैं और हम 35-40 किलोमीटर तक बनाएँगे। उन्होंने 2015-16 में जो interview दिया था — हमारे गडकरी जी बोलने में बहुत ही माहिर हैं, उन्होंने कहा था—"The 'flyover man from Maharashtra' seems to know the way to take it to a new hight and his latest is linking Delhi with Thailand for an over 4,000-km road trip in 2016." 2016 चला गया। फिर उन्होंने कहा—"As he sought to implement a number of initiatives in the years passing by to expand the road network in the country and removing the bottlenecks, Gadkari said his target is now to take the road building capacity to 100 km a day." अब 34-35 के बाद यह हो नहीं रहा है। हमारे लिए ये लोग कह रहे थे कि सिर्फ दो किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। ठीक है, हम मानते हैं, तब कुछ problems थीं। जयराम जी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या problems थीं और 6-7 किलोमीटर्स की average थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 22-24 किलोमीटर्स सड़कें हर रोज बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नई सड़कें बना रहे हैं, 4-लेन को 6-लेन में कन्वर्ट किया गया है, वह कितने किलोमीटर है? इन्होंने स्टेड्स के जिन रोड्स को रिपेयर किया है – जो CRF से fund मिलता है, वह सरकार ने ले लिया, उस पर मैं बाद में आऊँगा – उनको थोड़ा-सा widen करके उन पर सिर्फ एक top black carpet लगा दिया गया है। आप ज़रा segregate करें कि जो रोड्स रिपेयर किए, वे कितने किलोमीटर्स हैं और जो नये बनाए गए हैं, वे कितने किलोमीटर्स हैं? उसके बाद average निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह 22-24 किलोमीटर्स है या 6-7 किलोमीटर्स से कम है। फिर अभी कह रहे हैं कि हम 34 किलोमीटर्स बनाएँगे। उन्होंने एक और बात कही—"A trilateral pact between

India-Myanmar-Thailand (IMT) is expected by March 2016." बस हो गया कि नहीं हो गया, मुझे नहीं मालूम। "Shri Gadkari said while adding that the landmark Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Pact has already been inked with identification of 14 routes for passenger services." बड़ी-बड़ी बातें की हैं उन्होंने। उसमें कितना implement हुआ है, वह देखने की जरूरत है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह claim कर रह हैं, जो दावा कर रहे हैं, असल में हकीकत कुछ और है और marketing के लिए कुछ और है। प्रधान मंत्री फसल योजना के बारे में तो बात कर ली और अभी जो करने जा रहे हैं नई Health Scheme, तो उसमें मैं सदन का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो insurance companies हैं, उन्हीं को ही फायदा है। उसमें न किसानों को कोई फायदा होगा और बेचारे जो हमारे मरीज हैं, patients हैं, उनको भी कुछ फायदा नहीं होने वाला।

महोदय, मैं figures देना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, जो डा. मनमोहन सिंह जी के टाइम पर शुरू हुई थी, UPA-II ने first year में 60,117 किलोमीटर सड़क बनाई और बीजेपी के फर्स्ट ईयर में 36,337 किलोमीटर बनी। UPA-II के सेकंड ईयर में 45,109 किलोमीटर बनी थी और बीजेपी के सेकंड ईयर में 36,449 किलोमीटर बनी थी। In case of National Highways, in 2015-16, the target was 10,098 Kms. But the Government could only build 606 Kms. In 2016-17, the target was 16,271 Kms, लेकिन उन्होंने 8,231 किलोमीटर रोड बनायी। तो जो बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, इन्होंने यह किया, उन्होंने यह किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन यह जो सरकार है, मेरे ख्याल से बहुत ही कटु शब्द होगा, लेकिन उससे कम मैं कह भी नहीं सकता, जिसे कहते हैं अहंकार से भरी हुई, arrogant सरकार। इसमें tolerance बिल्कुल भी नहीं है। यह अभिमान वाली सरकार है, जिसमें सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए जावेद अख्तर जी की पोइट्री मैं कल सुन रहा था, पढ़ रहा था और उस पोइट्री में जो कहा गया है, वह बिल्कुल आज का जो माहौल है, उसके संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठता है। इसमें सिर्फ तीन मिनट लगेंगे। "किसी का हुकम है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है,

"किसी का हुक्म है, सारी हवाएं,

हमेशा चलने से पहले बताएं,

कि उनकी सम्त क्या है,"

उनकी दिशा क्या है, डॉयरेक्शन क्या है।

"हवाओं को बताना ये भी होगा,

चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी,

कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है,

हमारी रेत की ये सब फ़सीलें,

ये कागज़ के महल जो बन रहे हैं,

[श्री अहमद पटेल]

हिफ़ाज़त इनकी करना है ज़रूरी,

और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन,

ये सभी जानते हैं।

किसी का हुक्म है दरिया की लहरें,

ज़रा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें,

उभरना, फिर बिखरना और बिखरकर फिर उभरना,

गलत है उनका ये हंगामा करना।

ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत,

fear का symbol कीजिए, वह है अलामत।

बगावत की अलामत,

बगावत तो नहीं बरदाश्त होगी,

ये वहशत तो नहीं बरदाश्त होगी,

अगर लहरों को है दरिया में रहना,

तो उनको होगा अब चुपचाप बहना।

Just one voice. There should not be another voice. और अगर किसी ने कुछ कह भी दिया इन्कम टैक्स की रेड कर दी, ई.डी. वालों को भेज दो, सीबीआई वालों को भेज दो, इससे डरने वाले हम नहीं हैं।

"बातिलों से डरने वाले नहीं हैं ए आसमां हम,

सौ बार ले चुका है तू इम्तेहां हमारा।"

किसी का हुक्म है, इस गुलिस्तां में,

बस एक रंग के ही फूल होंगे।

कुछ अफसर होंगे जो यह तय करेंगे,

गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का,

यकीनन फूल तो यकरंगी होंगे

मगर ये रंग होगा कितना गहरा,

और कितना हल्का, ये अफ़सर तय करेंगे।

किसी को कोई ये कैसे बताए,

गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते,

कभी हो ही नहीं सकते।...

"कि हरेक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं,

जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे,

उनको ज़रा देखो,

कि जब एक रंग में सौ रंग ज़ाहिर हो गए हैं तो,

वो अब कितने परेशां हैं, वो कितने तंग रहते हैं।

किसी को अब कोई कैसे बताए,

हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं।

हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में,

हथकड़ी में, कैदखानों में नहीं रुकतीं,

ये लहरें रोकी जाती हैं, तो दरिया कितना भी हो पुरसुकूं,

बेताब होता है

और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है।

किसी को ये कोई कैसे बताए,

आग देखी है, धुआं देखा है,

दोस्तो हमने जहां देखा है,

हमने दरियाओं को थमते देखा है,

हमने सेहरा को रवा देखा है।

पासा पलटे तो पलट जाते हैं लोग..."

जो हैं, कब कहां चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है।

"पासा पलटे तो पलट जाते हैं लोग,

कौन कब क्यूं है कहां, देखा है।

वो जो वाइज़ हैं, उन्हें कल हमने क्या बताएं

कि कहां देखा है।"

[श्री अहमद पटेल]

महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्पीकर्स हैं, उन्होंने काफी मुद्दे यहां पर उपस्थित किए हैं। मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता कि आज किसानों की क्या हालत है, मज़दूरों की क्या हालत है, labour laws किस तरह से dilute किए जा रहे हैं। यहां पर हरेक इंसान परेशान है और जब 2019 आएगा तो मैं समझता हूं कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त होगी।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): 2018 में चुनाव होंगे।

श्री अहमद पटेल: हो सकता है, पहले भी कर लें, लेकिन उससे पहले अगर चुनाव जीतना है तो कहीं न कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। अभी तो हालत यह है कि हारेंगे, लेकिन अगर जीतना है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो वे अभी से लगे हुए हैं कि क्या किया जाए। जो last weapon है, जो हथियार है, उसी में लगे हुए हैं क्योंकि वे समझ रहे थे कि जो बजट है, वह populist बजट होगा, बहुत ही popular हो जाएगा, लेकिन वह तो flop हो गया तो अभी फिर से चिंता में हैं। राजस्थान के बाद उस दिन शाम को ही मीटिंग बुला ली कि अब क्या करें — राजस्थान में तो हार गए, बाकी जगह में भी हार गए, गुजरात में भी यह रिज़ल्ट आया। आप यूपी में by-election क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या हालत है? आप क्यों डरते हैं? आप 282 से 273 पर तो आ गए – वे नहीं चाहते हैं कि फिर से ये लोग आ जाएं। इसी प्रकार कश्मीर का by-elections करा दिया और दूसरा टाल दिया क्योंकि हारने वाले थे। तो वे नहीं चाहते कि 272 से कम हो जाएं और यह गवर्नमेंट minority गवर्नमेंट हो जाए। इसीलिए byelection नहीं करवा रहे हैं, simultaneous election की बात कर रहे हैं।

सर, मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मेरे ख्याल से जो मेरे कुछ प्वाइंट्स थे, बिन्दु थे, उन पर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरह प्रस्तावक ने गुलाबी चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की है और कहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सलामत है – मैं फिर से दोहराऊंगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ सलामत नहीं है। जिस उत्साह से वे यह धन्यवाद का प्रस्ताव लेकर आए थे, वह उत्साह मैंने कहीं इनके सहयोगियों में नहीं देखा। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ahmed Patelji, thank you. Now, Shri Jayant Sinhaji, your name is there but it is in the party list. Only three minutes remaining. I think, you speak in the end. ...(*Interruptions*)... Only three minutes are remaining. It is in the party quota. So, I would suggest that you speak in the end. I will see that you get some more time. You being a Minister, I can't ask you to stop after three minutes. So, you speak in the end. I will see that you get some more time.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): You have grounded him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, I am giving due consideration to the hon. Minister.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, for the benefit of the Chair and for all the Members, I want to say that our understanding is that the time is allocated as per the hon. Chairman's decision to the political parties, and he has informed the House before the debate has started. The Ruling Party and the other parties, as per their strength, are given the time. The Government always has the advantage because when the Prime Minister or the Leader of the House comes, he speaks. In fact, that is not available to the Opposition. We have no objection to the Minister's speaking. We don't have the intention to ground the Minister. So, you extend the time, and that is the only way out, because under the rules, there is no provision in such a debate or discussion that the Ministers of the Government will be given time, separate from the allotted time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I have said.

SHRI ANAND SHARMA: That is what I am saying.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I also said the same thing that the time for him, his party time, is only three minutes, and being the Minister, I don't want to stop him at three minutes. So, I said, don't speak now. After everybody has spoken... (*Interruptions*):

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, now is the time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then okay. Let him speak.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): सर, आप दो तीन speakers को बुला लीजिए, फिर मंत्री जी बोल लेंगे।

SHRI DEREK O'BRIEN: What is this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; it is his turn. You can speak. That is the sense of the House. But, your limit is five, seven minutes, not more than that. See, being a Minister, I give him an extra allowance of three, four minutes. Okay.

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): माननीय उपसभापति जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस Motion of Thanks पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। हम लोग राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जो अभी माननीय सदस्य साहब ने कहा, उन्होंने अपनी सरकार के बारे में कहा और उन्होंने तुलना की कि उनकी सरकार में क्या काम हुआ है और हमारी सरकार में क्या काम हुआ है।

उपसभापति जी, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास की ओर भी देखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारी सरकार में क्या काम हुआ है और उनकी सरकार में क्या काम हुआ है। अगर

[श्री जयंत सिन्हा]

हम लोग इतिहास की तरफ देखें, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे, वे प्रणब मुखर्जी जी थे। उन्होंने जो राष्ट्रपति अभिभाषण में कहा था, उसे मैं quote करना चाहता हूं and I will quote. माननीय राष्ट्रपति जी ने उस समय कहा, "We are also burdened by gathering anxieties about economic slowdown, job security and employment prospects. People are concerned about the security of our women and children." उस समय के राष्ट्रपति जी कह रहे हैं, "They are also anxious about timely delivery of their entitlements, and about persisting social and economic inequality. It has been a difficult year for India." यह फरवरी, 2013 में उस समय के राष्ट्रपति जी ने कहा था। वे उस समय की परिस्थितियां थीं। जब माननीय राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण 29 जनवरी को दिया, तो उन्होंने तब कहा, "The architect of our Constitution, Baba Saheb, Dr. Bhim Rao Ambedkar, used to say that political democracy cannot survive without social and economic democracy. Guided by this fundamental spirit of the Constitution, and committed to the welfare of the weaker sections, my Government is working towards strengthening social justice and economic democracy, and ease of living for the common man." तब उस जमाने की जो परिस्थितियां थी, तब उस समय के राष्ट्रपति जी ने कहा और इस समय जो परिस्थितियां हैं, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वह वर्तमान राष्ट्रपति जी ने 29 जनवरी को कही है और ease of living for the common man, सामान्य व्यक्ति, जो आप लोग कह रहे हैं कि यह एक जुमला है, यह हकीकत नहीं है। उपसभापति जी, आज के समय में जो ease of living for the common man हो रहा है, उसके बारे में, मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं। पहली बात जैसे अभी माननीय सदस्य जी ने कही है कि पकोड़े वालों के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। अगर हम वास्तविकता की बात करें, तो मुझे पकोड़े वालों से कुछ विशेष स्नेह भी है। क्योंकि हमारे हज़ारीबाग में झंडा चौक जो है, वहां बड़े सारे बढ़िया से बढ़िया उम्दा से उम्दा पकोड़े बेचे जाते हैं और सिर्फ पकोड़े ही नहीं ...**(व्यवधान)**... चाय तो मिलती ही है, बहुत ही अच्छी चाय मिलती है। आप जरूर वहां आएं, मैं आपको न्यौता देता हूं। लेकिन हम वहां इसे सिर्फ पकोड़ा ही नहीं कहते, हम उसे बर्रा कहते हैं। वहां जो लोग बर्रा बेच रहे हैं, जो झंडा चौक पर बर्रा बेच रहे हैं, उनको हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे उनको बहुत ease of living मिला है। पहला, इसमें मुद्रा योजना है, क्योंकि पहले आपकी सरकार के समय जो पकोड़े वाले थे, वे 25-30 प्रतिशत ब्याज की दर पर उधार लिया करते थे, आज के समय मुद्रा योजना के तहत उनको 8-10 प्रतिशत में रुपए मिल रहे हैं। इसलिए उनका उत्पादन बढ़ रहा है और पकौड़े बिक रहे हैं। आपकी सरकार में जो हजारीबाग के बाजार में आठ-दस घंटे की load shedding चल रही थी, वह अब नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों के पास बिजली सरप्लस में है। जो लोग पकौड़े बेचते हैं, जो लोग उस बाजार में आते हैं, आज उनको बिजली मिल रही है और वे आकर्षित होकर बाजार में आ रहे हैं और इसलिए उनकी बिक्री बढ़ रही है। ...**(व्यवधान)**... जिन पकौड़े वालों को पहले अफोर्डेबल हाउस के लिए लोन नहीं मिल रहा था, उनको आज के समय में लोन मिल गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजीव कुमार (झारखण्ड): सर, मैं भी वहीं से आता हूं। वहां पर लोग भूख से मर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयंत सिन्हाः वे पक्का घर बना रहे हैं। वे सिर्फ पक्का घर ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनको शौचालय बनाने के लिए भी सुविधाएं मिल रही हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजीव कुमारः सर, मैं भी झारखंड से आता हूं। वहां पर लोग भूख से मर रहे हैं। यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयंत सिन्हाः उनको शौचालय की सुविधा मिल गयी है। ...**(व्यवधान)**... इस प्रकार से आज तक छह-सात करोड़ शौचालय बन गये हैं और हजारीबाग शहर को ODF बना दिया गया है। हमने यह काम हकीकत में करके दिखाया है। ...**(व्यवधान)**... उसी पकौड़े वाले को ...**(व्यवधान)**... उनकी जो सुरक्षा बीमा योजना है, उसके तहत उन लोगों को हमने इंश्योरेंस कवर भी दिया है। हम लोगों ने उस पकौड़े वाले को दो लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर भी दिया है। इस प्रकार से उनको जो साधन दिए गए हैं, जो प्रोत्साहन दिए गए हैं ...**(व्यवधान)**... उपसभापति जी, मुझे पूरा भरोसा है कि हम उनको सिर्फ पकौड़े वाले तक सीमित न समझें, मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में जो गोलगप्पा बेचते हैं, बड़ा-पाव बेचते हैं, पकौड़ा बेचते हैं, चाट बेचते हैं, वह एक स्टार्टअप इंडिया के तहत एक देशी मेकडोनाल्ड खोल कर रखेंगे। ये प्रोत्साहन हम उनको दे रहे हैं।

Mr. Deputy Chairman, Sir, there has been a lot of discussion recently about the Budget. Many observers and commentators have said that it is the middle-class that is not getting the benefits of the Government's programmes. There have been many people who argue that the middle-class is getting the benefits of the programmes. I would like to speak about a professional woman working in Gurugram. What are the benefits that have accrued to her in her daily life over the last few years? The same lady, Mr. Deputy Chairman, Sir, during the time of the UPA Government was getting the maternity leave of only 12 weeks. That same working lady is now getting a benefit of 26 weeks for maternity purposes. When we consider her commute in Gurugram, Mr. Deputy Chairman, Sir, it was a disastrous commute when it rained. I myself — I am sure, many hon. Members here — have been stuck in Gurugram when it rained. They spent two-three hours on the road because of the flyovers that we built, because of the national highways that we built; that same working lady can get there in thirty minutes. And she is working for a financial services company. Because of the digitization and the formalization of the economy, that financial services company is growing dramatically; it is flourishing. Her professional career is also flourishing.

Importantly for the middle-class, hon. Members, please consider that during the time of the previous Government, inflation was running at 8 or 10 per cent a year which was impoverishing the middle-class. Now, the same middle-class is benefiting from inflation rates running at three or four per cent and real interest rates that are positive in the banks. When they put money in the bank, that money becomes more valuable rather than depreciating every day. That is the benefit we provided to the middle-class.

[श्री जयंत सिन्हा]

If you look at taxes, if you ask about what are the benefits we provided to the middle-class, the slab has gone from ₹ 2 lakhs to 2.5 lakhs; the home loan deduction has gone to ₹ 2 lakhs. The lowest tax rate has gone from 10 per cent to five per cent. That same professional lady, when she goes in the evening for a nice meal at the cyber hub, instead of paying 16 per cent GST, hon. Members, she is just paying five per cent in indirect taxes. Those are the real benefits that are accruing to the middle-class.

Therefore, because of what we are doing to ensure the formalization and the digitalization of the economy, to end the use of the black economy as well, we have learnt that if we, as a country, want to be number one, hon. Members, we have to end number two. To be number one, we have to end number two. We have to end the black economy.

So, these are the benefits that are accruing to the middle-class.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI JAYANT SINHA: Sir, I have several other points. Just give me a few more minutes, Sir. ...(*Interruptions*)...

श्री देरेक ओब्राईनः सर, उनको बोलने दीजिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The whole programme will get upset, that is the problem. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAYANT SINHA: Sir, Mr. Chairman said that the House should be in order ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, ...(*Interruptions*)...

श्रीमती रूपा गांगुली (नाम निर्देशित)ः सर, हम काफी समय से चुपचाप सुन रहे थे, अब जब हमारे मिनिस्टर बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं सुन सकते?

SHRI JAYANT SINHA: I am summing up.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you need support like this for a Minister? ...(*Interruptions*)... Listen, I have no problem, I am only constrained by the fact that the hon. P.M. wants to speak at 3.00 p.m. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAYANT SINHA: I am summing up. ...(*Interruptions*)... I need only two minutes. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is why I am saying it. ...(*Interruptions*)... I have to make it clear that because the hon. Chairman has said that each party should be

given its time, from where I am taking your time, I don't know. ...(*Interruptions*)... Who knows it? ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Let him speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot say this. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAYANT SINHA: I am summing up in two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Where do you get time from? ...(*Interruptions*)... All right. ...(*Interruptions*)...

श्री जयंत सिन्हाः सर, summing up से पहले दूर-दराज के एक आदिवासी गांव की वृद्ध महिला के जीवन में आए परिवर्तन के बारे में भी सोचने की बहुत जरूरत है। देखिए, आज हमने उस वृद्ध महिला को जन-धन योजना के तहत बैंक खाता दिया है, उसमें उसे वृद्धाओं की पेंशन सीधे मिल रही है, गैस सिलिंडर उन्हें सीधे मिल रहा है। **..(व्यवधान)...** Sir, how can I sum up if the hon. Members are not giving me the chance? ...(*Interruptions*)... इसी तरह उन दूर-दराज के गांवों में जहां बिजली नहीं थी, वहां हमने बिजली दी है। आज के समय प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो सिर्फ 56 परसेंट गांवों में पहुंची थी, आज 82 परसेंट गांवों तक पहुंच चुकी है। सर, मिशन इंद्रधनुष द्वारा हमें जहां immunization करना था, वह भी हम ने पूर्ण किया है। सर, दूर-दराज के गांवों के संबंध में मैं एक और अहम बात आप को बताना चाहता हूं। देखिए 14 वें वित्त आयोग द्वारा हम लोगों ने पंचायतों को खुद खर्च करने के लिए राशि दी है। जहां पहले झारखंड में किसी एक मुखिया को एक या दो लाख रुपए सालाना मिला करते थे और गांवों में छोटे-छोटे काम करने वालों के पास कोई साधन नहीं थे, 14वें वित्त आयोग द्वारा हमने हर मुखिया को 15 से 20 लाख रुपए सालाना दिया है और **...(व्यवधान)...** माननीय सदस्य आज जहां पीसीसी सड़क बनानी होती है, सामुदायिक भवन बनाना होता है **...(व्यवधान)...** चापाकल बनाना होता है, वह आज उन गांवों में खुद पंचायत समिति बैठकर तय कर ये काम कर सकती है। **...(व्यवधान)...** अंत में, उपसभापति जी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारी सरकार का मूल मंत्र **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What are you doing? ...(*Interruptions*)... Mr. Hariprasad, ask him to sit down. ...(*Interruptions*)... Please. What are you doing? Sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री जयंत सिन्हाः आप मुझे खत्म करने दीजिए **...(व्यवधान)...** कुछ सभ्यता का प्रदर्शन कीजिए। उपसभापति जी, हमारी सरकार का मूल मंत्र, "सब का साथ, सब का विकास" है। इस मूल मंत्र के संबंध में **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...(*Interruptions*)... ...(*Time-bell rings*)...

श्री जयंत सिन्हाः रहीम का लिखा एक दोहा सुनाना चाहता हूं

"तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान,
कहि रहीम परकाज हित, संपति संचहि सुजान।"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Minister, sit down, please. Now Prof. Ram Gopal Yadav; you have fourteen minutes.

श्री जयंत सिन्हाः हम लोग सब को साथ लेकर सब का निरंतर विकास कर रहे हैं और यही हमारी सरकार का मूल मंत्र है, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः प्रो. राम गोपाल यादव।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)**:** सर, मेरे लिए कितना टाइम है?

SHRI NARESH AGRAWAL: Twenty-five. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can I? ...(*Interruptions*)...Your party time is 14 minutes and you can take two-three minutes extra.

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, आप मेरे प्रति बहुत उदार रहे हैं, इसलिए मैं आप से कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर दो दिन से चर्चा चल रही है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, there is no Cabinet Minister.

श्री विजय गोयलः अभी कह कर गए हैं। ...**(व्यवधान)**... अभी कह कर गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to bring him.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it shows how serious the Government is. Sir, I have another point. Besides that, neither the mover of the motion nor the seconder of the Motion nor a Cabinet Minister is present here. This shows how serious they are about this Motion. It is a provoking thing. It is disrespect to the sentiments... ...(*Interruptions*)... It is disrespect to the House and disrespect to the President. ...(*Interruptions*)... ये गंभीरता से नहीं लेते हैं। .... **(व्यवधान)**....

SHRI VIJAY GOEL: This is not right. He has just left and you are raising the issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Goelji, a Cabinet Minister should be here. So, you arrange it. He should be here. Propriety demands that the mover and the seconder should also be here. You have so many Cabinet Ministers. Why is no one coming? ...(*Interruptions*)... Okay; he will come now. Please sit down.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, you can adjourn the House till he comes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; they are noting it down. No need to adjourn the House.

SHRI JAIRAM RAMESH: But you have done it in the past.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Goel, get a Cabinet Minister as soon as

possible. Please proceed.

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, ये भले ही सीरियस न हों, लेकिन हम लोग सीरियस हैं, इसलिए मैं चर्चा ...**(व्यवधान)**... को प्रारम्भ कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... प्रभु जी आ गए हैं, प्रभु जी की कृपा हो गई है।

सर, दो दिन से राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा के दौरान तरह-तरह की बातें आई हैं और कुछ नए किस्म के जुमले भी आए हैं, जिनकी मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। अभिभाषण में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया और न ही इसके बारे में कोई जिक्र किया गया है, मैं यहीं से अपनी बात प्रारम्भ करूंगा।

श्रीमन्, इस देश के प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं। महामहिम राष्ट्रपति स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं, देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद भी उस राज्य के बारे में कुछ न कहा जाए, तो यह चिंता की बात है। यह इसलिए भी चिंता की बात है कि यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर इसकी निरंतर उपेक्षा की जाएगी, तो आप देश के कुछ हिस्सों को तो सम्पन्न बना सकते हैं, लेकिन पूरे राष्ट्र को सम्पन्न नहीं बना सकते। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में किसानों ने पहली बार बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की हैं। उनकी आलू की फसल पूरी तरह से बरबाद हो गई है अर्थात् कोई आलू को खरीदने वाला ही नहीं था। इस नोटबंदी ने यह किया कि आदमी के पास कोई पैसा नहीं रहा। आप जानते हैं कि बिना कैश के कोई दुकान चल नहीं सकती है, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे देश के वित्त मंत्री प्लास्टिक करेंसी की बात करने लगे! गांव में जो दुकान चलाता है – क्या आप जानते हैं कि इस गांव में कितनी दुकानें हैं? करोड़ों लोगों के परिवार उन दुकानों से पलते हैं। आपने रिटेल में एफडीआई को हंड्रेड परसेंट अनुमति दे दी है, इसलिए वे सब बंद होने जा रही हैं। सर, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश की हमारी जो किसान यूनियन है, उसके दो ग्रुप हैं। एक राकेश टिकैत का ग्रुप है और दूसरा ग्रुप भानु प्रताप सिंह का है। भानु प्रताप सिंह जी हमारे फिरोजाबाद के हैं। उनके पुत्र ने पंद्रह दिन पहले इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि दो साल से आलू के लगातार घाटे की वजह से लगभग सात, आठ करोड़ रुपये का घाटा हो गया था। उसकी वजह से उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं आपको यह एक उदाहरण दे रहा हूं। जो सामान्य नहीं थे, बल्कि संपन्न व्यक्ति थे, वे विपन्न हो गए, इसमें उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है।

महोदय, अभी जयंत सिन्हा जी बिजली की बात कर रहे थे कि इतने घरों में, इतनी जगहों पर बिजली पहुंच गई है। क्या आपको मालूम है कि आज भी बिहार के 85 परसेंट हाउसहोल्ड में बिजली नहीं है, उत्तर प्रदेश के 71 परसेंट घरों में बिजली नहीं है। आप कनेक्शन्स देते रहिए। बिजली का जनरेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं, तब बिजली कहां से पहुंच जाएगी? आप पता कीजिए। आप अपनी पावर कारपोरेशन से पता कीजिए कि कितने परसेंट हाउसहोल्ड में बिजली है। मैं कह रहा हूं कि बिहार में 85 परसेंट और उत्तर प्रदेश में 71 परसेंट बिजली नहीं है। यह हालत है।

महोदय, जब प्रधान मंत्री जी बनारस गए थे, तब उन्होंने यह कहा था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। एक मंत्री ने हाथ खड़े कर दिए, उसी के लिए एक विभाग बनाया गया था, "नमामि गंगे"। वे बहुत बड़ी पुजारी और साध्वी हैं, मंत्री हैं। अब उस विभाग का कोई और मंत्री बन गया है। ...**(व्यवधान)**...

1.00 P.M.

एक माननीय सदस्यः गडकरी जी।

प्रो. राम गोपाल यादवः कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि करोड़ों, अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी गंगा पहले से ज्यादा मैली हो गई। क्या यह गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार है कि जो पैसा इस पर खर्च किया गया है, उसकी पूरी तरह से जांच करवाएगी? यह मैलापन बढ़ता ही जा रहा है। यदि चंबल नदी वगैरह का ठीक पानी न पहुंचे, तो इलाहाबाद में संगम स्थल पर भी नहाने लायक पानी कतई नहीं रह सकता है। चंबल और बेतवा कुछ ऐसी नदियां हैं, जो ऐसी जगहों से निकलती हैं, जो शहरों के पास नहीं हैं। ये पहाड़ों से आती हैं, इनका पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। बस इनकी वजह से ही पानी कुछ ठीक है। इटावा में, चंबल यमुना में मिल जाती है और वहां से यमुना में इसका पानी शुरू हो जाता है। आप कभी यहां से, यमुना के पुल के पास से निकलिएगा... इसका क्या नाम है? ...इस रोड से निकलते हैं, आप अब, जब गरमी में निकलेंगे, तो महसूस करेंगे कि वहां से बदबू आती है, नाक बंद करनी पड़ती है। यहां ऊपर से आने वाला कोई पानी नहीं है, सारा दिल्ली के नालों का पानी है, सारा गंदा पानी है। सफाई के नाम पर कुछ भी कर दीजिए। एक मंत्रालय बना दिया गया, पर कोई काम नहीं हुआ। मैं अभी बनारस के घाटों पर गया था, हमारे एक मित्र हैं, उनके फादर की डेथ हो गई थी, मैं मणिकर्णिका घाट पर गया था, दशाश्वमेध घाट पर गया था, वहां स्थिति यह हो गई है कि एक तरफ पूरी तरह से, गंगा का जो दूसरा साथ है, वह ऊपर तक पूरा बालू से भर गया है। बाढ़ के दिनों में जब पानी आता है, तो वह पानी सीधे आपके घाट से टकराता है। उसकी वजह से उधर घाट के नीचे दस-दस, बीस-बीस फुट खोखली जगह बन गई है। अब यदि उसमें कोई आदमी चला जाता है, तो वह जिंदा नहीं निकल पाता है। डा. लोहिया कहा करते थे कि नदियों को साफ करो, जो अब मेरी समझ में आया है कि नदियों को साफ करना कितना जरूरी है। अगर कोई जरा सी मिट्टी उठा लेगा, तो खनन हो रहा है। अगर इन नदियों में खनन नहीं होगा, तो ये नदियां सूख जाएंगी। आप देखिएगा, गंगा ऊपर आ गई है, बिल्कुल खेतों के किनारे लेवल पर आ गई है। इधर से जिप्सी को डालिए और उधर से गंगा में निकाल ले जाइए, यह हालत हो गई है। सफाई के नाम पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अगर केवल उसको खोद ही देते, उसके खनन का पट्टा दे देते कि इतना तुम करो, इतना तुम करो, तो भी गंगा साफ हो जाती और सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू भी मिल जाता। न जाने कौन योजना बनाने वाले हैं, कौन क्या करने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आता।

महोदय, यह बात मुझे मजबूरन कहनी पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर, अभी एक दिन में 23 एनकाउंटर हुए। एक निर्दोष व्यक्ति तो नोएडा में मारा गया, मगर 23 जगह बताया गया कि एनकाउंटर हुए। नए डीजीपी ने जिस दिन चार्ज लिया, उसके अगले दिन ये एनकाउंटर हुए। ये क्यों हुए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधान सभा के अंदर और पब्लिक मीटिंग में कहते हैं कि ठोक देंगे। आप बताइए, पूरा सदन बैठा हुआ है, सभी भले हैं, इस सदन के लोगों के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी है, दूसरे सदन में और अन्य सदनों में हो सकता है कि उनमें इधर-उधर के लोग आ जाएं, लेकिन इस सदन में अच्छे ही लोग हैं, जो अगर इस शब्द का प्रयोग किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकले, तो कोई भी किसी भी दल का व्यक्ति या कोई व्यक्ति इसको जस्टिफाई कर सकता है? कोई इस बात को जस्टिफाई करेगा कि एक मुख्यमंत्री कहे — ठोक देंगे? यह भी कह सकते थे कि एनकाउंटर हो जाएगा, जो बदमाश हैं, उनका एनकाउंटर कर

दिया जाएगा, बदमाशों के एनकाउंटर कर दिए जाएंगे। शब्द का जो अर्थ है या जो कहने का तरीका है, उससे भी आदमी के चरित्र का पता चल जाता है। कोई व्यक्ति कहता है कि ठोक देंगे, यह शब्द तो मैंने केवल बदमाशों के मुंह से सुना है, किसी भले आदमी के मुंह से कभी यह शब्द नहीं सुना है। अब जब मुख्य मंत्री कहेंगे कि ठोक देंगे, तो यहां ठोक दिया। एक जिम ट्रेनर लड़का जा रहा था, उसको गोली मार दी, जबकि उसके खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस की रपट, एक भी 323 की एनसीआर की रपट कभी नहीं हुई। यह स्थिति है। दूसरी तरफ क्या है? पंजाब के लोग जानते होंगे, हरियाणा के भी जानते होंगे और दिल्ली के भी जानते होंगे, एक बहुत बड़ा अपराधी रविंद्र काली, जो रोपड़, पंजाब में एक बहुत बड़े अपराधी को पुलिस कस्टडी से छुड़ा कर भागा था, वह चार महीने से फिरोजाबाद जिले में बीजेपी के एक नेता के यहां, जो एमएलए का चुनाव लड़ा था, जो पहले मिनिस्टर रह चुका था, उसके यहां हमारे एक एमएलए की हत्या करने के लिए रह रहा था। अभी तीन-चार दिन पहले वह पकड़ा गया, तो बिना पंजाब को पूछे, हरियाणा को पूछे, जबकि उस पर पंजाब और हरियाणा से एक-एक लाख रुपए का इनाम था, बिना किसी प्रदेश की पुलिस को सूचना दिए हुए धीरे से बिना किसी पूछताछ के उसको जेल में भेज दिया। न उसको पुलिस ने remand पर लिया। अब पंजाब पुलिस remand पर लेगी, तो अलग बात है। जिन पर लाखों रुपए का इनाम है, जो पुलिस को गोली मार कर अपराधियों को छुड़ा कर भागने के दोषी हैं, तमाम अपहरण और लोगों की हत्या करने के दोषी हैं, वे बीजेपी के किसी नेता के घर पर 4-4 महीने रहें, उनकी फोटो है, ऐसा नहीं कि मैं यूँ ही कह रहा हूँ। वह फिरोजाबाद में पकड़ा गया, लेकिन एक गोली नहीं चली, लेकिन सहारनपुर से लेकर बलिया तक 23 लोगों को गोलियां मारी गईं। किसी के पैर में मार दी, एक आदमी तो यहां मर ही गया और 3 लोग घायल हैं। यह स्थिति है। पूरी तरह से जंगल राज हो गया है। कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है। अधिकारी इतने डरे हुए हैं कि अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति कह देता है, any Tom, Dick or Harry, तो उसकी बात सुनी जाएगी, चाहे वह कितनी ही नाजायज़ हो, लेकिन और लोगों की सौ फीसदी जायज़ बात को भी नहीं सुना जा सकता है। उत्तर प्रदेश के हमारे और दूसरे दलों के एमपीज़ यहां पर बैठे हैं, they all will support my statement. मैं कभी झूठा आरोप नहीं लगाता हूँ और बिना तथ्यों के बात नहीं कहता हूँ। ...**(समय की घंटी)**... लेकिन यह सत्य है, इसलिए मैं मजबूरी में कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति, उसकी गरिमा को देखते हुए मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन जब मुख्यमंत्री बार-बार इस शब्द को repeat करें, तो मजबूरी में मुझे यह कहना पड़ा। यहां से बाहर मैं खुद भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि वे आखिर हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लोगों को पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Ramgopalji, please conclude.

श्री नरेश अग्रवालः सर, आप सदन की राय ले लीजिए और प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। इससे बड़ी राय कोई नहीं है।

प्रो. राम गोपाल यादवः अभी तो मैं उत्तर प्रदेश से बाहर ही नहीं निकल पाया हूँ। ...**(व्यवधान)**... अभी तो मैं उत्तर प्रदेश से बाहर ही नहीं निकल पाया हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What to do? Your time is over. What can I do?

SHRI DEREK O'BRIEN: No, no, Sir. Let him speak.

प्रो. राम गोपाल यादवः अब मैं 2-4 मिनट ही और बोलूँगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

प्रो. राम गोपाल यादवः महोदय, मैं बेरोजगारी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अब मैं उत्तर प्रदेश से बाहर निकल आया हूँ, हालांकि वहां भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी की स्थिति यह है कि इंजीनियरिंग, एमबीए और पीएचडी किए हुए लोग सफाई कर्मचारी के पद के लिए apply कर रहे हैं। जब हमारे डाक्टर साहब प्रधान मंत्री थे, तब 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने Reserved और General Category में 1 लाख 13 हजार नियुक्तियां की थीं। आप 2015 में जाइए, तो जो सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देना चाहती थी, केवल 8 हजार appointments हुई हैं। डा. मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2013 में 1 लाख 13 हजार नियुक्तियां और 2015 में केवल 8 हजार नियुक्तियां इस सरकार के जमाने में! इन्होंने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये रोजगार नहीं दे रहे हैं और सातवें वेतन आयोग में ये सिफारिशें कर दी गईं कि अब Class-III और Class-IV में कोई और नियुक्ति नहीं की जाएगी और जो खाली पद हैं, वे समाप्त किए जाएँगे। मंत्री जी, आपके सब ड्राइवर्स भी contract पर होंगे। अब कोई regular नहीं है। अगर वह आपकी फाइल चुरा कर ले जाए और गाड़ी लेकर चला जाए, तो पता चलेगा कि वह चला गया। गवर्नमेंट का employee पक्का employee होता था, तब उस पर भरोसा रहता था। खास तौर से defence, telecommunication और जो sensitive विभाग हैं, उनके लोगों को सावधान रहना होगा कि जब वे अपनी अटैची में फाइल ले कर अपने घर जाते हैं, तो वे कभी उसको छोड़ें नहीं, क्योंकि ड्राइवर contract पर है, पता नहीं कब गाड़ी सहित चला जाए। NPA को लेकर एक बड़ा खतरा और पैदा हो गया है, देश में लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि अगर बैंकों में पैसा रखोगे, तो उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर वह बैंक डूबने लगेगा तो वह आपका सारा पैसा ले लेगा। आप लोग इस पर बिल ला रहे थे, लेकिन नहीं लाए। ...**(व्यवधान)**... अगर बैंक पूरा पैसा नहीं लेगा, तो एक लाख छोड़ कर तो सब ले लेगा। यह चीज़ तो अभी भी है। सिन्हा साहब यह जानते हैं, ये वित्त मंत्री रहे हैं। इनके पिता जी बहुत काबिल थे, मैं अभी उनको क्वोट करने जा रहा हूं। वे अब भी हैं और हमारे नेता रहे हैं। जब मैं पहली बार 1992 में राज्य सभा में आया था, he was my leader. 130 नं. कमरे में वे बैठते थे, उनकी नेम प्लेट वहां लगी थी। उन्होंने जीडीपी के बारे में यह कहा था कि इन लोगों ने यह जो नया फॉर्मूला लगाया है, उसकी वजह से जीडीपी 5.7% था, वरना यह 2% और 3% के बीच में ही रहना चाहिए था, जो डाक्टर साहब ने भी कहा था। सिन्हा साहब, आपको उनकी बात का खंडन नहीं करना चाहिए था। इन्होंने वह फॉर्मूला चेंज कर दिया। ...**(समय की घंटी)**... मैं एक मिनट और लूंगा। इन्होंने यह कहा था कि हम MSP का डेढ़ गुना देंगे। क्या आपको मालूम है कि इन्होंने क्या * किया है? हम आपके माध्यम से देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि जो CACP है, उन्होंने इसका फॉर्मूला बदल दिया है। 2004 से लेकर 2008 मैं Agriculture Committee का चेयरमैन था और 2006-2007 में स्वामीनाथन साहब भी उस कमेटी में आ गए थे। उस वक्त हमने CACP के चेयरमैन को बुलाया और पूछा कि ईमानदारी से बताइए कि आप किस तरह से MSP निकालते हैं? उन्होंने बताया कि यह लोगों को मालूम नहीं चलना चाहिए, उसके बाद उन्होंने सारी बात बताई। आप आश्चर्य करेंगे कि उस वक्त गेहूं और धान की जो कॉस्ट थी, वह उस वक्त की MSP से ज्यादा थी, यानी लागत मूल्य MSP से

*Expunged as ordered by the Chair.

ज्यादा था। ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब इन्होंने क्या किया है कि जो C-2 है, उसमें irrigation, electricity, pesticides, fertilizers, परिवार के लोगों की लेबर, रेंट इत्यादि सब कुछ माइनस कर दिया है और उसको माइनस करके लागत मूल्य को कम कर दिया और कह दिया कि हमने MSP को डेढ़ गुना कर दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Ram Gopalji, please conclude. ...(*Interruptions*)... What can I do?

प्रो. राम गोपाल यादवः आप देश के लोगों के साथ यह सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं?

श्री उपसभापतिः राम गोपाल जी, आपका टाइम खत्म हो गया है। ...**(व्यवधान)**... मैं क्या कर सकता हूं?

प्रो. राम गोपाल यादवः अभी आपका जो सर्वे आया है, उसके हिसाब से आज भी इस देश के लोगों को 49 प्रतिशत रोज़गार खेती ही देती है। आप उन किसानों को * देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?

श्री उपसभापतिः अब समाप्त कर दीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादवः मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। राय देने के लिए या ईमानदारी से राय देने के लिए मंत्री लोगों के पास सचिव होते हैं। जब वे सचिव डरते हैं तो सही राय नहीं देते हैं। इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है:–

"सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस।
राज धर्म तन नीति कर होई बेगिहीं नास।।"

अगर आपका सचिव सही राय नहीं दे रहा या आप सचिव की राय को सही से नहीं मानते हैं, सही तरीके से लागू नहीं करते हैं, तो शीघ्र ही राज्य का नाश होगा। आप तो मानस की बहुत बात करने वाले लोग हैं, यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पहले कह गए थे। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप ठीक तरीके से जनता के हित में काम कीजिए और लोगों को * देने की बात मत कीजिए। जब बजट के बारे में चर्चा होगी, तो पूरी बात सामने आएगी कि देश को बहुत बड़े पैमाने पर * दिया गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Hon. Members, unless you speak within the allotted time, what can the Chair do? The Chair can only request you. The Budget discussion is also there. So, you need not complete all your points in this speech. You can reserve something for the Budget also. So, I request everybody, it is my humble request, to ...

श्री नरेश अग्रवालः सैशन की डेट एक दिन और बढ़ा दीजिए, सोमवार तक कर दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the decision of the House is to have the reply at 3.00 p.m. and therefore accordingly the time is allotted. My humble request is to speak within your time. Now, Shri Derek O'Brien. Your time is 11 minutes.

---

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I stand here to speak on the Motion of Thanks on the President's Address on behalf of my party, the All India Trinamool Congress.

Sir, the hon. President, *Rashtrapatiji*, made two speeches, one in the Central Hall of Parliament and one, on Republic Day, which many of us may have missed, and, as we know, the speech made in Central Hall is the Government-approved speech.

Sir, I wish to first dwell on two of the points that he raised on Republic Day. This is what the hon. *Rashtrapatiji* said: "Institutions should be disciplined and morally upright and they are always more important than individuals in office." I only wish this was also said in the Central Hall. That would have been a strong message at the right place. The second thing that he said in his Republic Day speech was, "Institutions are more important than individuals." I want to pass this message on from the *Rashtrapatiji* and all of us in this House to the people concerned here. These are the two important sentences.

Sir, after hearing the BJP President who made the maiden speech here, I thought he was making a maiden speech and he would rise above politics, but he ended up doing another election *maidan* speech. I will restrain myself from doing that, but I hope that after this if anybody from the BJP speaks in this House, they will respond to the five suggestions that I give them to run this country better, on schemes, and to the one or two suggestions that the Trinamool Congress gives them to run this country better overall, beyond the schemes. No rhetoric, no *pakora* talk! This is all very well. We all like *pakoras*, but the *pakora* has nobody to defend himself or herself. So, let us leave the *pakora* out.

Sir, I would talk about five schemes. My colleague who spoke before me touched upon a few very important issues; I will not repeat them: simultaneous elections – they can't happen; it is unconstitutional – on black money, we want a White Paper, institutions and tolerance. So, I would not speak on any of these issues, but I would speak on five points first – women, health, agriculture, jobs, *Swachch Bharat* and federalism.

First, on women, I would talk pointedly about the scheme *Beti Bachao Beti Padhao*. Here are the numbers. The numbers on *Beti Bachao Beti Padhao* scheme are very interesting. For the scheme, ₹ 280 crores have been allotted this year for the whole country. If you add it up for the last few years, it comes to about ₹ 1,200 crores. Use the example which has worked. Don't do politics. Use the example of *Kanyashree*. For one State, over the last four-and-a-half years, the budget is ₹ 5,000 crores. Number two: How many lives has *Beti Bachao Beti Padhao* touched?

There are no numbers. Maybe it is 50,000 to one lakh. Here is the number for this scheme – the lives of 45 lakh girls and women have been changed. Their marriage age has gone up and the infant mortality rate has, in fact, dropped. These are the real numbers of the real schemes. Look at the scheme. The United Nations has acknowledged the scheme. Don't do politics by putting one *Beti Bachao Beti Padhao* scheme and giving it ₹ 280 crores. That is the first example, Sir. They didn't learn from this scheme but maybe they can learn from another scheme, the *Rupashree*, which is another scheme which Bengal has just started, without the politics.

Sir, I would make one more quick point on women and then I would move on to health. About 70,000 to one lakh women die every year because of cervical cancer. Why hasn't this Government addressed this issue? I will tell you why. It is because the RSS's economic wing wrote to the Health Ministry – please check the letter – saying that this should not be done. Let us rise above this kind of thinking; put in the signs and let the doctors do their work.

Sir, from women, I am moving on to health. I would just briefly touch upon the Insurance Scheme. I am giving you the points and I hope, whoever speaks from the BJP would answer these five points. You have announced ₹ 2,000 crore for the NHPS. I will give you the benefit of doubt and, I will say, you also add RSBY, which they will probably do, and make it together you will get ₹ 4,000 crore. Sir, the annual premium will work out to ₹ 1,200 crore. This is a flawed scheme. It hasn't been thought out; it has just been announced. Rather you look at the States like my State or some other States, we offer a premium of ₹ 1,200 per family and, worse still, you made the grand announcement and then you say, without discussing with anybody, 40 paise to a rupee has to be paid by the States. These schemes don't work; they are just announcements.

Sir, two quick points on agriculture. It is very nice to go to an election rally in Karnataka and talk about tomato, onion or potato. Sir, it is from the Prime Minister of the country! This is not a college debate. Come to the hard numbers. The BJP Manifesto said in 2014 that they would double farmers' income. The Trinamool Manifesto in 2011 said that we would double farmers' income. The BJP will make it happen in 2022; the Trinamool made it happen in six years, from 2011 to 2016. I am giving you two numbers. ₹ 94,000 per annum was left with the farmer. Now that number has gone up to ₹ 2,20,000 in six years; no promises, without keeping promises.

Now, I come to the President's Address and irrigation. You look at the President's Address and you look at the Budget together and you look at the numbers. Water is a very major issue. Forty-five per cent of the farm land is not irrigated and yet

[Shri Derek O'Brien]

what we do we put ₹ 300 crore for irrigation. If you calculate, it will take you 96 years beyond 2022 to reach your target. Sir, if anybody says I am not correct what I am speaking, the Prime Minister is speaking next, I challenge the Prime Minister to challenge my figures.

Sir, come to jobs. On jobs, a lot of people have spoken. I just want to add one more point on jobs. As per the National Career Services Portal launched by the Prime Minister, correct my figure, two in hundred people, who have registered, had got jobs. Only two!

Now, I come to *Swachh Bharat*. My colleague, Shri Manish Gupta, made a very nice point today about the manual scavengers. Sir, besides the manual scavengers, there is a story in Odisha of Chotu Rautia from Odisha, a 50-year old daily wage worker, a tribal. After he applied for PM's Awaas Yojana, the officials finally turned his *Swachh Bharat* toilet into his home. This is the reality of this programme. I am not speaking big talk here. Even when this entire *Swachh Bharat* was done, yes, which district was number one? You won't have to guess. Yes, it is from Bengal. It is Nadia. Sir, now come to federalism – operative federalism, cooperative federalism. I have a few points on federalism. Federalism! We made an issue yesterday about a high constitutional authority who is running States because the headquarters are coming and giving the messages. I don't want to dwell more on this; we have spoken enough on this yesterday. Sir, come to federalism. Since we discuss the Railway Budget, we have enough time to discuss the Railway Budget. But in the limited time, I want to make one point about railways because the BJP would give us big talk: No Railway Budget; it is all politicized. I would like to give some numbers – which I was up, still very late calculating – about BJP's States in the Railway Budget and that is why there is no Budget Speech. Uttarakhand's increase in budget is 160 per cent; dispute these numbers. Rajasthan got an increase of 30 per cent; Gujarat got an increase of 20 per cent and Madhya Pradesh 18 per cent. These are plus, plus, plus. Now you contrast that with Delhi, Kerala and West Bengal. They didn't only get plus; they got minus 40, minus 30 and minus 15. What are you talking about federalism?

The first speaker of BJP, Mr. Amit Shah, gave us a lecture on Police modernization. When it is Police and modernization, it is BJP. What was he talking about? I will tell you Police modernization numbers. Someone from the BJP should come back and contradict these numbers that I am giving. In 2014, modernization of Police force got ₹ 1,600 crore, then, in 2015, got ₹ 1,400 crore. This year it is zero. I know my friend, Shri Jayant Sinha, who is here, was trying to dispute some of

the figures. We also heard the speech. But, there is an old saying about ...पापा कहते हैं... but we will come back to that later. Sir, besides that speech, besides those numbers, ...(*Interruptions*)... I will take three minutes, Sir, not more. Sir, BRGF is one. Sir, this Government talks about federalism. They advertise about federalism. Here are two numbers. Thirty-nine major schemes, Centrally-funded schemes have been withdrawn. In 658 important schemes, the State contribution has been increased and that of the Central Government has gone down. And what is the BJP doing herein, in their proposal on the Motion, they are blaming somebody ... 55 साल आपने किया, तो हम लोगों ने किया, 48 परसेंट गुजरात में हम लोग... These are the poll numbers. Rise above politics. Rise above politics, come to Parliament, make suggestions, whether you are in Opposition or in Government. That's why I have stayed above all politics and only stayed on these numbers. Sir, I always don't like to take more time. I never like to take more time, Sir, but I just have a few more points and then I will summarize. The Prime Minister was in Davos. He said, "Whoever controls data is the most powerful and can shape the world". Remember Aadhaar. This is a dangerous line. Think about it and think about Aadhaar. Sir, I don't want to say anything about false claims because we can write a book now on false claims. The first seaplane ride, the first Ro-Ro ride and so on. I don't want to go there. But I am very interested in the year 2022. Everything will happen in 2022. There is a scientist who predicted that a man will go into Mars by 2022. I believe this scientist. ...(*Time-bell rings*)... Sir, two minutes. But, for all the criticisms we, the Opposition, make against this BJP Government, we should also congratulate them once in a way. And, I want to congratulate them because by 2022, the Oxford English Dictionary will have a new word and that word will be defined as 'make a promise', make a lot of hype around the promise, don't deliver the promise and India has given many good words to the Oxford English Dictionary – *hartal, tamasha, khushi,* and so many words... *shampoo* is also one. The new word will come in 2022. We must all work towards it. It is *Jumla.* ...(*Time-bell rings*)... Sir, in one minute, I will end. But I see hope in all these and I will tell you where I see the hope. I see hope when I study the character of *Mahishasura. Mahishasura* was all evil. He was all negative. Completely evil and completely negative.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

SHRI DEREK O'BRIEN: He also felt that no man could ever defeat him. So he kept changing his form and he forgot what he was. Finally, Sir, it took all the good forces to come together in the shape of a woman to finish *Mahishasura*, once and forever. Sir, that is my hope in this country. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K. K. Ragesh. Your time is four minutes.

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, at the very outset, with due respect to the hon. President, I would like to say that this is the same rhetoric. The President's speech has the same rhetoric that is being repeated by the hon. Prime Minister and his team during the last few years.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA) *in the Chair*]

SHRI K. K. RAGESH: Sir, they are offering a lot many things but they are delivering nothing. They have already offered a garden for you but they are not ready to deliver even a single flower. Sir, this Government is about to complete four years in office. It is the right time to review the promises that they had made, what they could deliver and the promises that they have fulfilled. They could have reviewed that. But, they are still thinking that they are contesting the elections. They are still on the verge, thinking that they are again contesting the elections. That hangover of election is not leaving them.

Sir, as we all know, the UPA Government got defeated because of its policies, its neo-liberal policies that resulted in price hike, agrarian distress, selling out of public sector enterprises, huge corruption, etc. All these issues were the outcome of neo-liberal policies.

Sir, this NDA Government had promised 'good days' for the people. They always used to say, 'सबका साथ, सबका विकास'. But, Sir, has the President's Speech addressed that issue? Have they brought 'good days' for the people? Do they still stand by that slogan of 'सबका साथ, सबका विकास'? Those things are missing in the President's Address. Why? It is true that they have come to power as the single party majority, but they must remember that they have got only 31 percentage of the total vote share. That means, 69 percentage of the total vote share was in opposition to them. They must understand that point.

Sir, after coming to power, did this Government make any policy change? They have got a lot many *yojanas* with prefix of Prime Minister - PM Yojanas. Hon. LoP mentioned about those schemes. These are nothing but old wine in new bottle. These *yojanas* are nothing more than that. What is the new thing that this NDA Government has delivered? They are talking so much about the Ujjwala Scheme. It is good if they are providing eight crore LPG connections to the poor, but, at the same time, please see the other side of the story. The oil marketing companies were asked to increase the prices of LPG every month, and during the last 17 months, the price of LPG cylinder has already been increased by ₹ 77, and all the subsidies are going to be taken back. In such circumstances, how can the poor afford to purchase the LPG cylinder? They should tell us. And, Sir, in 2014, a subsidy of

₹ 42,000 crores was provided for LPG. Now, that has been slashed to less than ₹ 10,000 crores. The Government is taking ₹ 42,000 crores from one pocket and putting ₹ 1,200 crores in another pocket and saying that it has provided ₹ 1,200 crores. What does it mean? It is nothing but the * of the people. Please tell us the amount of black money that you have already unearthed. Please tell us the names of the Swiss bank account holders. ...(*Time-bell rings*)... Why are they not talking about Panama Papers? Why are they not talking about the names that have appeared in Panama Papers and Paradise Papers? It is because their own people's names appear in those papers. So, they are not talking about that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude. Your time is over.

SHRI K. K. RAGESH: Sir, I will take only three more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude. Please, say your last sentence.

SHRI K. K. RAGESH: Sir, they said that after demonetization, they would find ₹ 4 lakh crore of black money. But, 99 per cent of the total demonetized currency has come back. What does it mean? They allowed the black-money holders to convert the black money into white. This is what happened. ...(*Time-bell rings*)... Again, Sir, who is responsible for the misery that was caused to the common man? Who is responsible for the utter destruction of the MSME sector, which has collapsed? Sir, they are answerable for that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Thank you.

SHRI K. K. RAGESH: They always talk about promoting digital transactions. Then, why are they levying user charges on digital transactions, which are cheaper than printing currency? They are allowing certain companies, like *Paytm*, to make super profits through these transactions. That is why, they are asking the people to deposit their money in the banks.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Nothing more will go on record. Please conclude.

SHRI K. K. RAGESH: Sir, please.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Okay, just the last sentence; only one minute.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI K.K. RAGESH: Again, you are talking about agriculture as the engine of growth; as the largest employer, and you are talking about giving priority to that sector but what is happening now? You said that you were going to double the income of the farmers, but, Sir, unfortunately, the income has not doubled but the number of suicides has doubled. The farmers' suicide has increased by 47 per cent. Who is responsible for that?

Now, you are coming up with a gimmick of fifty per cent profit over and above the cost of production as MSP.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): You have exceeded your time. …(*Interruptions*)…

SHRI K. K. RAGESH: Sir, what is the budgetary allocation that you have provided? …(*Interruptions*)…

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please. ...(*Interruptions*)... Now, Shri Satish Chandra Misra. ...(*Interruptions*)... Please, please, please. ...(*Interruptions*)... You have taken more than two minutes. …(*Interruptions*)… Please. …(*Interruptions*)… You have concluded it. Very good. आप बैठ जाइए।

SHRI K. K. RAGESH: Sir, they are talking about employment generation. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please allow him to speak. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. …(*Interruptions*)… Now, Satish ji. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH: What are you providing to the professional graduates? …(*Interruptions*)… Peanut selling! …(*Interruptions*)…

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Okay. Now, Satish ji. …(*Interruptions*)… Mike please.

SHRI K. K. RAGESH: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Nothing is going on record. …(*Interruptions*)… Nothing is going on record. …(*Interruptions*)… Nothing is going on record. …(*Interruptions*)… Please sit down. Thank you.

श्री सतीश चंद्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने Presidential Address पर लाए गए Motion of Thanks पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं माननीय प्रेजिडेंट साहब की स्पीच को देख रहा था। उसको कई बार पढ़ने के बाद, उसकी शुरुआत में

---

* Not recorded.

यह देखने को मिला कि कांस्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट थे, जो कांस्टिट्यूशन को बनाने वाले थे– बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर, उनका जिक्र किया गया।

उनका नाम लेने के बाद यह भी कहा गया कि democracy cannot survive without social and economic democracy. लेकिन आज क्या इस देश में सोशल डेमोक्रेसी बची है? खासतौर से, जब से यह सरकार आई है, तो सोशल डेमोक्रेसी कहां गई? इस पूरे भाषण में, जो कि सरकार का डॉक्युमेंट होता है, उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि दलितों के लिए और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए वे क्या करने जा रहे हैं या सरकार क्या कर रही है या क्या सोच रही है। पूरे डॉक्युमेंट में कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं है। इस पूरे डॉक्युमेंट को कई बार पढ़ने के लिए यही मिला कि उन्होंने शायद यह नाम भी लेना उचित नहीं समझा, जबकि वे खुद भी उसी कास्ट से आते हैं। माननीय प्रेजिडेंट साहब की मजबूरी है, हम समझते हैं। कैबिनेट ने जो बनाकर दे दिया, उस पर उनको दस्तखत करना है और उसको ही बोलना भी है। इसलिए यह डॉक्युमेंट सरकार की जो मंशा है, दलितों के बारे में जो सोच है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो सोच है, वही चीज़ इसमें परिलक्षित होकर उनकी स्पीच में भी आई। इसीलिए हम लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा कि अगर इस देश में हम एक दलित व्यक्ति को प्रेजिडेंट बना देते हैं, तो दलितों के उद्धार के लिए शायद इतना ही काफी है। इससे नहीं होने वाला है। जब तक आप उनके बारे में अपनी योजनाएँ नहीं लाएँगे, उनके साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ जो दुराचार कर रहे हैं, उसको बन्द नहीं करेंगे, तब तक उनका उद्धार होने वाला नहीं है। वह तभी हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी यह नहीं चाहेगी कि इस देश का प्रधान मंत्री कोई दलित हो, क्योंकि सत्ता की चाबी प्रधान मंत्री के पास होती है। वे केवल प्रेजिडेंट बनाकर दलितों में सिर्फ यह एक संदेश देना चाहते थे कि देखिए, हमने एक दलित को प्रेजिडेंट बना दिया। आज चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या देश में देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसी का हो रहा है, तो इन्हीं लोगों का हो रहा है।

इतना ही नहीं, आज पूरे देश में unemployment फैला हुआ है। इस पर सभी लोगों ने अपनी बातें कहीं, आँकड़े भी दिए, सब कुछ दिया। हम उन आँकड़ों पर जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि समय कम है। सालाना दो करोड़ लोगों को employment देने की बात कही गई थी, लेकिन हुआ क्या, निकला क्या है? जिन लोगों को already employment मिलता था, जिनके लिए रोज़गार का कोई ज़रिया था, वह भी खत्म कर दिया गया। पोस्टें खत्म की जा रही हैं। जहां कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा पोस्टें खाली हैं तो उनको हम खत्म कर देंगे। क्यों खाली हैं? आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आपको उन पोस्टों को भरना था, आपने क्यों नहीं भरा? अगर आप नहीं भरते हैं और कहते हैं कि अब ये पोस्टें 5 साल नहीं भरी गई हैं, इसलिए हम इनको खत्म कर देंगे। इसके पीछे मंशा क्या है? जितने भी पीएसयूज़ हैं, जितने भी पब्लिक सैक्टर आर्गनाइजेशंस हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनको धीरे-धीरे आपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ कर दिया और प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। बड़े-बड़े उद्योगपति जिनके लिए सरकार चलती है, कुछ चुनिंदा, उन्हीं के लिए सरकार चलती है। गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार नहीं चल रही है। उसको प्राइवेटाइजेशन इसलिए आपने किया क्योंकि उसमें रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन एक ऐसा इश्यू है, जिसके तहत जो दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जो थे, वे एक

[श्री सतीश चंद्र मिश्रा]

एम्प्लॉयमेंट पाते थे। उस एम्प्लॉयमेंट को आपने कई तरह से खत्म करने की कोशिश की। आपने प्राइवेटाइजेशन करके ठेकेदारों को दे दिया। ठेकेदारों के ऊपर कोई गारंटी नहीं, कोई कंडीशन नहीं है कि वे इनको एम्प्लॉय करेंगे और इनको रिजर्वेशन देंगे। जो ठेकेदार होता है, वह अपनी मरजी से appointment देता है। उसका नतीजा क्या हुआ कि धीरे-धीरे रिजर्वेशन खत्म हो रहा है और जहां पर सरकारी पोस्टें थीं, उनको आपने भरना बंद कर दिया। लाखों-लाखों की संख्या में पूरे देश में बैकलॉग है। जब उत्तर प्रदेश में सुश्री बहन मायावती जी की सरकार थी, जब वे मुख्य मंत्री थीं, तो उन्होंने जो पिछले कई वर्षों से बैकलॉग था, कई लाखों की संख्या में था, उन्होंने भरने का काम किया था। वह कांस्टीट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है, उसमें है कि कोई भी बैकलॉग आप नहीं रखेंगे, लेकिन बैकलॉग भरने की जगह आप पोस्टें खत्म करने का काम कर रहे हैं। यह इस सरकार की मंशा है। इतना ही नहीं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट दे तो रहे हैं, पकौड़ा बेचना या अगर कोई चाट बेचता है तो कोई वैसी चीज नहीं है कि ठीक है, पकौड़े वाले की अपनी प्राइवेसी होती है, वह खराब चीज नहीं, लेकिन जब आप उसकी तुलना करने लगते हैं, जब आपको यह कहा जाता है कि आप इस कन्ट्री के यूथ को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, जो करोड़ों की संख्या में अनएम्प्लॉइड है, पढ़ाई करके पोस्ट ग्रेजुएट होकर और एक्सपर्टीज़ लेकर अपनी फील्ड में बैठा हुआ है, आप उस कम्प्यूटर ऑपरेटर से कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए। आज तो जयंत सिन्हा जी ने कह दिया कि चाट बेचिए, गोलगप्पे बेचिए। तो फिर इस यूथ को गोलगप्पे और चाट और पकौड़ा बेचने की एजुकेशन दीजिए। उसको फिर आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आप क्यों पढ़ाई की बात करते हैं और आप इसके साथ-साथ यह भी तो सोचिए कि आज आप देश को कहां ले जा रहे हैं। इस देश में जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, उसको आप फोर्स कर रहे हैं कि आपको हम appointment नहीं दे सकते हैं तो आप पकौड़ा बेचिए। उसकी एजुकेशन खत्म कर दीजिए। तो आप उसकी एजुकेशन में उसको पकौड़ा बनाना सिखाइए और चाट बनाना सिखाइए, बताशे बनाना सिखाइए, क्योंकि आपकी जो मंशा है कि हम इनको इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो आप इनको क्यों आईआईटी में पढ़ा रहे हैं, क्यों एनआईटी में पढ़ा रहे हैं, क्यों आईआईएम में पढ़ा रहे हैं? आईआईएम पढ़ने के बाद अगर उसको यही काम करना है तो यही काम शुरू से कहिए कि अपने-अपने बच्चों को अब आप इन स्कूलों में मत भेजिए। मैं पूछता हूं, क्या जयंत सिन्हा साहब अपने बच्चे को भेजेंगे या अपने ग्रैंडसन को या इनके जो भाई-भतीजे होंगे, उनको पकौड़े बनाने की दुकान पर भेजेंगे? वे तो कहेंगे कि नहीं, आप जाइए, विदेश में जाकर पढ़कर आइए और अच्छा काम करिए। तो इसलिए अगर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो इस चीज को स्वीकारना चाहिए और यह कहना चाहिए कि हां, हमने इस देश के नौजवान लोगों को * दिया, उनको असत्य बोला, उनको बरगलाया, उनसे वोट असत्य बोलकर के लिया। आपने उनको बरगलाने का काम किया और कहा कि आप हमको वोट दे दो और हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। तो इस बात को आपको स्वीकारने में क्या दिक्कत है, इसको स्वीकार लीजिए, लेकिन यह मत कहिए कि जो बाहर पकौड़ा बेच रहा है, यह एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप इसी को एम्प्लॉयमेंट मानते हैं तो आप महिलाओं के बारे में सोचिए, आप लड़कियों के बारे में सोचिए। वे क्या करेंगी? आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट तो इस चीज से मिल रहा है। आज इस देश की जो लड़कियां हैं, वे लड़कों से ज्यादा अच्छे नम्बर ला रही हैं, अच्छा पढ़ रही

---

*Expunged as ordered by the Chair.

हैं, अच्छा आगे बढ़ रही हैं। आप कह रहे हैं कि "बेटी पढ़ाओ", तो बेटी पढ़ाकर के आप उसको कहां ले जाएंगे, किस दुकान पर बिठाएंगे और क्या कहेंगे कि पकौड़े की दुकान पर बैठो? या आप इसको बताशे की दुकान में बैठाएंगे, जैसाकि आज सिन्हा साहब ने कहा। एक मंत्री जी ने कहा था कि ड्राइवर बन रहे हैं, बीस हज़ार गाड़ियां चल रही हैं, टैक्सियां चल रही हैं, उनमें भी तो employed हो गए हैं। सर, जो प्राइवेट टैक्सियां चल रही हैं, यहीं पर आप इस देश को ले आना चाहते हैं! जहां एक ओर बाहर के लोग चांद-सितारों और सूरज तक जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम इसको कहां ले जा रहे हैं – हम इसे पुरातत्व की ओर ले जा रहे हैं। जब इस country और बाहर की countries के बीच comparison होगा तो यहां के नौजवानों का और वहां के नौजवानों का भविष्य देखने को मिलेगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): मिश्रा जी, आपके पास पांच मिनट हैं।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: आज देश में जो women हैं, उनके बारे में कहा गया कि देखिए, हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक की बात करके उनके हक की बात की है। आप women की बात करने के हकदार हैं ही नहीं, उनके benefits की बात करने के हकदार हैं ही नहीं। आप तो वे लोग हैं, जिन्होंने जब यहां पर Women's Reservation Bill आया था तो उसको रोकने का काम किया था। जिस तरीके से आपने Reservation in Promotion को रोकने का काम किया, आपने Constitutional Amendment को किया, जिसे आप आज तक लोक सभा में नहीं लाए हैं, उसी तरीके से आपने Women's Reservation Bill को भी रोकने का काम किया और आप कहते हैं कि हम उनके बड़े ही खुदाई-खिदमतगार हैं! इस प्रकार इनका चेहरा अलग है, बोलने की चीज़ अलग है। सर, इसमें जन-धन योजना की बात कही गयी है। उधर से यह बात कही गयी कि इस देश के 32 करोड़ लोगों ने, गरीबों ने अपने अकाउंट खोले, जिन्होंने कभी अकाउंट देखे नहीं थे और 32 करोड़ लोगों ने जो अकाउंट खोले, उसमें 72 हज़ार करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। आप यह भी तो देखिए कि ये 32 करोड़ लोग वे लोग हैं, जिन्हें आपने कहा था कि हम 15 से 20 लाख रुपए आपके खाते में जमा करा देंगे, इसलिए लाइन लगाकर उन्होंने खाते खुलवाए और आज उनके खाते में सिर्फ दो रुपए रह गए हैं। तभी तो 32 करोड़ के 72 हज़ार करोड़ हुए। इस प्रकार दो रुपए अगर उसके खाते में हैं तो इसे आप अपनी बड़ी भारी उपलब्धता बता रहे हैं! आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया! आपके बैंक वालों ने खुद कहा, आपके स्टेट बैंक की जो तत्कालीन चेयरमैन थीं, उन्होंने खुद मीडिया में स्टेटमेंट में कहा कि हम तो इनके रुपए काट रहे हैं। जिसके खाते में हज़ार रुपए से कम हैं, उसके खाते से हर महीने हम रुपए काट लेते हैं क्योंकि वे हमारे बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप तो उनसे रुपए छीनने का काम कर रहे हैं।

आज इस देश में किसानों की जो हालत है, वह बद से बदतर है। आज आपने उत्तर प्रदेश में देखा, हम सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र या कहीं भी ले लीजिए, चाहे वह आलू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे प्याज़ हो, उसे उन्हें सड़कों पर फेंकना पड़ा है। उन्हें मुख्य मंत्री जी के घर के सामने यह दिखाने के लिए अपना आलू फेंकना पड़ा कि हमारी हालत क्या है और हमें इस आलू की क्या value मिल रही है। Cold storage में जो किराया था, वह ज्यादा था और आलू की कीमत उससे बहुत कम थी कि वे उसका किराया भी नहीं दे सकते थे इसलिए उन्होंने कहा कि इसे cold storage में ही छोड़ दो और cold storage वालों ने उसे

[श्री सतीश चंद्र मिश्रा]

सड़कों पर फेंका, किसानों ने फेंका – आज उनकी ऐसी हालत हो गयी है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल चल रहा है? वहां पर सिर्फ एक ही काम चल रहा है कि मारो, ठोको। जैसा कि उन्होंने कहा कि आप encounter कर दो। आज महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। अगर कोई प्रदर्शन करता है, तो उसको मारने की धमकी दी जाती है, ठोकने की धमकी दी जाती है। इतना ही नहीं, वहां सिर्फ "डंडा और झंडा" के बल पर सब कुछ चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय डंडे और झंडे के बल पर आपस में समुदायों को लड़ाकर, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्यवाही करने, दलितों के खिलाफ कार्यवाही करने, उत्पीड़न करने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्हें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम आज सरकार में बैठे हैं। अब आपके चार साल हो गए हैं। कल सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमारा यह आखिरी बजट है। सही बात है। आपने बहुत सही कहा। कभी-कभी सही निकल आता है, ज़ुबां पर सरस्वती बैठ जाती है। यह वाकई आपका आखिरी बजट है, आपको अगला बजट पेश करने का मौका नहीं मिलेगा, इस देश की जनता आपको अगला बजट पेश करने का मौका नहीं देने वाली है क्योंकि आपने हर वर्ग के लोगों को बरबाद करने का काम किया है। Real Estate, जहां पर लोग काम करते थे, मज़दूर काम करते थे, उसकी बुरी हालत हो गयी है। इस देश के मज़दूर, किसान, टीचर्स सब परेशान हैं क्योंकि सब jobless हो गए हैं, सब घरों में बैठ गए हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। आज उन्हें मजबूर होकर सड़कों पर आंदोलित होकर या तो आपके डंडे खाने पड़ते हैं या मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ती है। इस देश में आज यह सब हो रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब यह पूरा देश, इस देश के सभी लोग, इस देश के 85 प्रतिशत लोग - Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities, खास तौर से मुस्लिम और Backward Class के लोग आज आपका असली चेहरा देख चुके हैं, उसको पहचान चुके हैं और पहचानने के बाद उन्होंने यह मन बना लिया है, उसका अंदेशा आपको हो भी गया है कि अब ये इकट्ठा होकर आपको आपकी इस गद्दी से बाहर करके इस बजट को बनाने और दुबारा भाषण बनाने की परेशानी से हमेशा-हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I seek your protection. ...(*Interruptions*)... Sir, I seek your protection. ...(*Interruptions*)... Sir, please protect me. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Under which rule?

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I will tell you. ...(*Interruptions*)... It is a very serious issue. ...(*Interruptions*)... I spoke today in Rajya Sabha. The first four to six minutes of my speech were blacked out. It was not shown on Rajya Sabha TV. ...(*Interruptions*)... There is no rule. ...(*Interruptions*)... It was not shown on Rajya Sabha TV. ...(*Interruptions*).... It is the first five minutes of my speech. ...(*Interruptions*)... I am a Member of the Opposition. ...(*Interruptions*)... यह कैसे हुआ? सर, इसके बारे में पता कीजिए। Sir, please protect me. ...(*Interruptions*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): जरूर इसके बारे में पता करेंगे। Please sit down.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the first five minutes of my speech were not shown on Rajya Sabha TV. ...(*Interruptions*).... No, no, Sir. ...(*Interruptions*)... The TV started after six minutes. ...(*Interruptions*)... Sir, we are getting Wi-Fi. ...(*Interruptions*)... Sir, please! ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): So, we will enquire about it and let you know what had happened. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, Sir. ...(*Interruptions*)... Not just let me know...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, give me a chance. ...(*Interruptions*)...

श्री सतीश चंद्र मिश्राः सर, यह तो ब्लैक आउट है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Without asking for enquiry, how can we? ...(*Interruptions*)... देरेक जी, इसका यहां से तो पता नहीं लगाया जा सकता है। यहां से तो पता नहीं लगा सकते।

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत serious issue है कि राज्य सभा का टेलिविजन, लाइव टेलिकास्ट हो या उसकी न्यूज़ में प्रोसीडिंग्ज़ हों, उसमें सभी पार्टीज़ को equally time मिलना चाहिए। आज इसका लाइव टेलिकास्ट नहीं किया। परसों जब यहां बहस हो रही थी, मैं भी उसमें बोला। रात की आठ बजे की न्यूज़ मैंने देखी, उसमें 98 परसेंट न्यूज़ पूरे सदन की बीजेपी के अध्यक्ष को थी और आठ सेकंड मुझे और आठ सेकंड दूसरे विपक्ष के सदस्यों को थीं, टोटल 16 सेकंड थे पूरे विपक्ष को और रूलिंग पार्टी के बीजेपी प्रेजिडेंट को 99.5 परसेंट था। राज्य सभा के टेलिविजन को बीजेपी के टेलिविजन में कन्वर्ट मत करो। यह राज्य सभा का टेलिविजन है।

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد):** اپ سبھا ادھیکش مہودے، یہ بہت سیریس ایشو ہے کہ راجیہ سبھا کا ٹیلی ویژن، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو یا اس کی نیوز میں پروسیڈنگ ہوں، اس میں سبھی پارٹیز کو ایکولی ٹائم ملنا چاہئے۔ آج اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا۔ پرسوں جب یہاں بحث ہو رہی تھی، میں بھی اس میں بولا۔ رات کے آٹھ بجے کی نیوز میں نے دیکھی، اس میں 98 فیصد نیوز پورے سدن کی بی۔جے۔پی۔ کے ادھیکش کی تھی اور آٹھ سیکنڈ مجھے اور آٹھ سیکنڈ دوسرے وپکش کے سدسیوں کو تھیں، ٹوٹل 16 سیکنڈ تھے پورے وپکش کو اور رولنگ پارٹی کے بی۔جے۔پی۔ پریزیڈینٹ کو 99.5 فیصد تھا۔ راجیہ سبھا کو ٹیلی ویژن کو بی۔جے۔پی۔ کے ٹیلی ویژن میں کنورٹ مت کرو۔ یہ راجیہ سبھا کا ٹیلی ویژن ہے۔

† Transliteration in Urdu script.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please assure me after the LoP has spoken. How come these five minutes ...(*Interruptions*)... इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री गुलाम नबी आज़ादः सर, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... हमें परसों वाली भी इन्क्वायरी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... यह इन्क्वायरी ऑल पार्टीज़ कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्ज के द्वारा होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام نبی آزاد:** سر، اس کی انکوائری ہونی چاہئے ---(**مداخلت**)--- اس کی انکوائری ہونی چاہئے ---(**مداخلت**)--- ہمیں پرسوں والی بھی انکوائری چاہئے ---(**مداخلت**)--- یہ انکوائری آل پارٹیز کمیٹی کے ری-پریزینٹیٹو کے ذریعے ہونی چاہئے ---(**مداخلت**)---

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है। ...(**व्यवधान**)... जब तक हम चेयरमैन साहब से बात नहीं करेंगे, तब तक इसका हल यहां पर नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम नबी आज़ादः दूसरा, मीडिया को आपने अपनी पार्टी का मीडिया बनाया, लेकिन लोक सभा और राज्य सभा के चैनल को अपनी पार्टी का मीडिया मत बनाइए। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام نبی آزاد:** دوسرا، میڈیا کو آپ نے اپنی پارٹی کا میڈیا بنایا، لیکن لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے چینل کو اپنی پارٹی کا میڈیا مت بنائیے ---(مداخلت)---

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): हो गया। ...(**व्यवधान**)... श्री के. टी. एस. तुलसी। अच्छा, तुलसी जी नहीं है, श्री डी. राजा। यदि कोई बात है, तो राज्य सभा में हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, इन सारी बातों के बारे में सभापति जी से चर्चा करके निदान किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं। हम सब सीनियर लोग हैं। काफी लम्बे समय से हम लोग यहां पर हैं। इसके बारे में चैम्बर में बात की जा सकती है, उसको यहां करने से कोई लाभ नहीं है। ...(**व्यवधान**)... श्री डी. राजा। आपका अब बोलने का समय शुरू होता है। आपके पास आठ मिनट का टाइम है। आप अच्छी तरह से बोलिए।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, with great agony, I rise to speak on this Motion. Sir, the Address of the President begins with the paragraph, I quote, "The architect of our Constitution, Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar, used to say that political democracy cannot survive without social and economic democracy. Guided by this fundamental spirit of the Constitution and committed to the welfare of weaker sections, my Government is working towards strengthening social justice and economic democracy and to usher ease of living for the common man."

Sir, the sad part is that this Government has been working against political democracy in our country. You may say that Shri Jawaharlal Nehru has not contributed anything for democracy in this country. Now, we have listened what Mr. Derek

† Transliteration in Urdu script.

O'Brien has been saying. What is the democracy that we practice? We should think over that. The sad part is that – with all seriousness, I make this statement, this Government has been working against the political democracy. It has already deepened the social and economic inequalities. Political democracy enshrined in the Constitution and the statutes are shrinking day by day, and with all responsibility I am saying, shrinking day by day due to Government's policy of divide and misrule. Emergence of a surveillance State is threatening the rights of people. This is very dangerous. I appeal to all political parties to think over it.

Sir, quoting Dr. Ambedkar and acting contrary to his vision has been practice of this Government, the present Government. The Government quotes Dr. Ambedkar and at the same time quotes Shri Deen Dayal Upadhyay who opposed the Constitution because it did not allow creating a *Hindu Rashtra*. Sir, it sounds offensive to the very vision of Constitution and the legacy of Dr. Ambedkar. Seventy years after Independence, we cannot afford to invoke those who opposed the very Constitution of the country.

Sir, today, the nation is passing through a very critical period. Ever since we won the Independence, I think, this is the first time the country is passing through such a critical period. There is a crisis, all pervasive crisis. There is a crisis in economic life, there is a crisis in political, social and cultural life. There is crisis in all the organs of State. There is crisis in Judiciary, there is crisis in governance and the Parliament is also facing grave threat. Parliament is there and Parliament's powers are being curtailed. The Government has weakened the Parliament by not referring Bills to the Department-related Parliamentary Standing Committees. Even the Money Bill route is being increasingly taken to negate discussion in the very same House – Rajya Sabha. The entire Opposition wanted the Triple Talaq Bill to be referred to the Select Committee. What is wrong in that? As though the Opposition does not want Triple Talaq. You are making that issue as a big issue. The Opposition wants a legislation but a legislation of this kind will have far-reaching implications on our social life, on our women, their empowerment irrespective of the religions which they belong to. That is why the Parliament should have a closer scrutiny, legislative scrutiny of the legislation. This is what we said. Parliament is undermined by not referring Bills to the Standing Committees. This President, Sir, has given the first Address. But earlier we had one President, Mr. K.R. Narayanan; he had also served as Vice-President and Chairman. Mr. Narayanan emphasized the need for having the Committee system in order to strengthen the parliamentary democracy. The present Prime Minister goes on saying 'Maximum governance, minimum Government.' Now, what is happening in reality? It is 'Maximum Government, minimum Parliament.' That is what is happening. Sir, this is what I would like to appeal to all the parties

[Shri D. Raja]

2.00 P.M.

to think over. The situation is very challenging. It is not good for the country and its future. I am happy that the head of the ruling party has come back and is present in the House. He made a speech, opening speech, as though he is the head of the Government. I keenly listened to his speech. Now, I am raising the issue. He talked about poverty. I will not claim as he claimed. He has seen poverty but I was born in poverty; I was grown in poverty; I lived in poverty and I represent people who live in abject poverty. Why is this happening in our country? What is the share of the working people in the wealth of the nation? I am asking this from all the political parties. Touch your conscience and tell me, what is the share of the working people in the nation's wealth which they create? Who build the industries? Who work in industries? Who cultivate land? Who produce the paddy or wheat or anything? Who produce all that? It is all by the working people. What is their share in the country's wealth? I am asking you as to what is their share. They are demanding a fair share. I am asking, after this Government came, while the number of billionaires has increased, the number of people living below the poverty line is increasing. According to the official figures, I am quoting, "29.9 per cent of Indian people live below the poverty line. The latest Oxfam Report has pointed out that in India 1 per cent of rich corner 73 per cent of annual income of the country. This share was 58 per cent in 2013 and it means during the four years of this Government, the present Government, the cornering of wealth by rich has increased by 15 per cent." "सबका साथ, सबका विकास", what is the meaning of "सबका साथ, सबका विकास" if the working people do not have their fair share in the wealth they create? ...(*Time-bell rings*)... That is exactly what the Government should think over. Even the head of the ruling party has mentioned that this Government is working....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Rajaji, Please conclude. ...(*Time-bell rings*)...

SHRI D. RAJA: Sir, allow me a couple of minutes. He mentioned how this Government is working in the interest of *Dalits*. I would like to ask, is it not a fact that the attacks on *Dalits* is increasing in this country; also the attacks on *Adivasis* and Minorities in this country. Let us be truthful to the Parliament. Let us be truthful to the nation and to the people outside. Is it not a fact that there is an increase in the attacks on *Dalits*? Sir, I take the example of Gujarat. I don't get into Una, as to what happened in Una. But, there are reports that a *Dalit* boy cannot grow moustache and he is being lynched if he does so. What kind of country are we building? Is this the 'New India', I am asking. A *Dalit* boy cannot ride on a

horse at the time of his marriage. It happened in Rajasthan and he was lynched, and we talk of New India! What is this New India? What is this civilization are we talking about? ...(*Time-bell rings*)... A *Dalit* family cannot take water from the common well. What sort of India are we building? We will have to think over. And, the Government can make tall claims but, finally, what happens to....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Conclude now. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, allow me, I am completing.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): वह समय पार्टी के सारे लोगों का है, केवल इन का नहीं है। इन के दो मिनट ज्यादा हो गए हैं।

SHRI D. RAJA: Sir, you increase the time. We had agreed. Every party has got more time.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): No; we have no powers. ...(*Interruptions*)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: सर, मेरा एक मिनट इन्हें दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): वह तो आपको भी दे दिया और इन्हें भी दे दिया। श्री बी. के. हरिप्रसाद। ...**(व्यवधान)**... He spoke well, but please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: But, Sir,... ...(*Interruptions*)... Sir, there are problems.

श्री आनन्द शर्मा: अगर वह है, तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please, please. ...(*Interruptions*)... आनन्द शर्मा जी, आपका नंबर आने वाला है।

श्री आनन्द शर्मा: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया कर उसे सुन लें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कुछ समय पहले सरकार की तरफ से एक माननीय मंत्री बोले। पीठ की तरफ से कहा गया कि आप के दल के 3 मिनट बाकी हैं। महोदय, सदन में जब धन्यवाद प्रस्ताव आता है तो उसकी प्रस्तावना सत्ताधारी दल करता है। उसे सेकंड भी सत्ताधारी दल का सदस्य करता है और जब माननीय प्रधान मंत्री जी बोलते हैं, वह तो जितना चाहें बोलें, उन पर कोई समय-सीमा नहीं है। लेकिन उस समय 3 मिनट बढ़ाकर 12 मिनट किए गए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): इनके भी हो गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: राजा साहब अच्छा बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**... इसलिए वही मापदंड इन पर भी लागू करें। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): राजा साहब अच्छा बोल रहे हैं, तो इनके भी तीन मिनट ज्यादा हो गए हैं। Please conclude in one sentence. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, he is concluding. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, the other issue which I tried to bring to the notice of this House ...(*Interruptions*)...

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: दलित के मामले में ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): सतीश जी, आपका भाषण अच्छा हो गया है।

श्री सतीश चंद्र मिश्रा: ये दलित एट्रोसिटी के बारे में बोल रहे हैं...**(व्यवधान)**... इनको बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**.... यह पूरे देश के दलितों का दर्द है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): समय पर बोलना है ...**(व्यवधान)**... समयबद्ध बोलना है, यह उनकी कला में है ...**(व्यवधान)**... वे जानते हैं।

SHRI D. RAJA: Sir, I have two points. Even though I can speak on many points, I will have to speak on two points and finish.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): You spoke well.

SHRI D. RAJA: Now, the point here is, there is increasing attack on intellectuals and artistes in the country. We cannot forget the way Dabholkar was killed, Govind Pansare was killed, Kalburgi was killed, Gauri Lankesh was killed. Sedition charges are slapped on student activists and universities are tense in our country. On the one side, Parliament's powers are curtailed, while on the other side, there is attack on intellectuals, artistes, journalists and those who question the Government and criticize the Government. This is the surest way of creating conditions for fascism in this country. Can we allow fascism to emerge in this country? And this is what I say, unprecedented and extraordinary situation, we are confronting today after Independence. And this has to be understood. The President's Address does not recognize this reality and political parties must recognize this reality. Sir, this Government claims this Government is pro-working class.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please be brief. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Let me take this one point and conclude, Sir. This Government claims it is pro-working class. Even somebody said, the left has nothing to complain against the President's Address or Budget and the right is satisfied with this. Left or right, I am raising the question regarding National Minimum Wage in spite of the

recommendations of Indian Labour Conference and decisions of the Supreme Court. ₹ 18,000 is the common demand of all Central Trade Unions. What is the decision of the Government? Then, disinvestment of strategic public sector undertakings and you are inviting FDI in trade, FDI in retail trade and FDI in defence production. ...(*Interruptions*)... I am asking: Is it in the interest of the country? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): No, please do not elaborate. ...(*Interruptions*)... You make your point. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, I am asking...(*Interruptions*)... Sir, if I am raising any irrelevant issue, you point out to me. I am asking you also, whether inviting FDI in defence production is the way to protect our country and save the country. This is where I am saying, this Government has been breaking all the strong fundamentals of our economy, all the strong fundamentals of our democracy. And this is where I do not think the President's Address recognises the prevailing reality, the prevailing crisis in our country. And this is where...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Okay; you have taken five minutes more. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: I think all political parties must realize how to save the country, how to take the country forward. Now, the country needs our collective efforts. ...(*Interruptions*)... This is what I am saying. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Nothing more is going on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shri B. K. Hariprasad. ...(*Interruptions*)...

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Thank you Vice-Chairman, Sir. I rise to speak on the resolution moved to thank the President for his Address to the Joint Session of Parliament. Sir, I have got all three earlier speeches of the President. One common thing that we are seeing is, quoting of Pandit Deendayal Upadhyay. Fortunately, this time, as rightly pointed out by Shri D. Raja, they have brought in the name of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar also. If you just go through the contrast between Deendayal Upadhyay and Dr. Bhim Rao Ambedkar, as my hon. friend, Shri D. Raja has mentioned about it, well may be, for the people who wear black caps and khaki knickers, Deendayal Uapadhyaya may be everything, but the country still wants to know what great contribution he has made to the Constitution

* Not recorded.

[Shri B. K. Hariprasad]
and the freedom struggle. I do not know from where he has been mentioned. That is the only thing which is common in almost all the speeches of the hon. President.

Sir, Dr. Bhim Rao Ambedkar who is the architect of the Constitution strongly believes in the geographical territory of the nation, not the religious territory what was preached by Deendayal Upadhyaya. Dr. Bhim Rao Ambedkar strongly believed in the Constitution, I would like to know whether Deendayal Upadhyaya had got the same confidence or belief in the Constitution. I think the hon. Member who moved the Motion of Thanks to the President Address failed to address this issue.

Sir, what Deendayal Upadhyaya said was, एकात्म मानववाद। Integrate humanism. There are some slogans which are catchy slogans of the Bharatiya Janata Party and the NDA. When they came to power in 2014 it was अच्छे दिन, भ्रष्टाचार का खात्मा। All slogans were there. Then, सबका साथ-सबका विकास. Then, they said "minimum Government maximum governance." After four years, I want to say where is the Governance. There is only Government, there is no governance at all. Right from wherever the Bharatiya Janata Party was ruling in the States there is no governance. I do not want to elaborate. The world would have appreciated, if in the President's Address to the joint session of Parliament he would have mentioned about the mass rapes that are taking place in some of the States which are barbaric and uncivilized. But unfortunately there is no mention in the President's Address.

Sir, majority of the people in this country would have felt happy if the hon. President would not have compared Deendayal Upadhyaya with Dr. Bhim Rao Ambedkar.

Sir, hon. Member, Amit Shah initiating the discussion on the Address, said that we have opposed the National Commission for the Backward Classes Bill. Suppose, they have brought the Bill to strengthen the National Commission for Backward Classes, I want to submit that I have introduced a Private Member's Bill on this subject in this House in 2016. They have not brought anything new in the Bill. If at all they are serious about the Backward Classes Bill, they should have moved an amendment to the Bill in this House, to include five members from the OBC, one woman member from the OBC, one member from the religious minority community, either Christians or Muslims or Sikh or Budhha or Jain. Any of these religious minorities we wanted in it. But they opposed the spirit of reservation. They opposed the spirit of representation in the Commission. On the contrary, they are accusing us that we are opposing the Bill, which they have brought to give strength to the NCBC.

They are talking of the latest *jumla*. The President of the Bharatiya Janata Party proudly defends it. They are glorifying the habit of begging. He has defended the

pakoda economics. Sir, every mother in the country wants that her daughter or son to become a doctor or an engineer. But the BJP Government has made the engineers and doctors to sell *pakodas*. It is a shameful act on this earth. This is the kind of vision that they have for the people who are educated. Sir, in Para 15 of the President's Address, the President has mentioned about the irrigation projects. Sir, let me talk about my State of Karnataka. When it was formed way back in 1956, it was sandwitched between the major States, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana, and even smaller States like Puducherry and Goa. Sir, they have mentioned that 99 irrigation projects are in progress. The people of northern Karnataka have been demanding the Central Government and the Goa Government for drinking water from the State. The Prime Minister has failed to call the meeting of the Chief Ministers of three States, Maharashtra, Goa and Karnataka to sort out this problem. On the contrary, they say that the Congress should speak to their counterparts in Goa and Maharashtra. Sir, it is ridiculous. The river Mahanadi or Cauvery or Krishna does not belong to the BJP or the Congress. It belongs to the people of this country. Whenever there is a problem, whenever there is a serious issue, it is the duty of the Prime Minister to call the meeting of the Chief Ministers and sort out the issue. Instead of that, they are talking like panchayat members. This is not fair. People of northern Karnataka are seriously affected; they are facing serious drinking water problem. If they believe in *sab ka saath, sab ka vikas*, the Prime Minister should immediately intervene and get the due share of water from Goa to Karnataka.

Sir, as far as the Governmental plan of the Bhartiya Janata Party is concerned, we have been seeing quite often that a lot of BJP people say that it is Narendra Modi's model which has developed Gujarat. Recently, the Bhartiya Janata Party President and the Prime Minister went to Karnataka. Let me talk where we stand and where their model stands. Sir, I have grown with Karnataka. When I started visiting Delhi way back in 1979, I had one aeroplane which used to reach Delhi *via* Hyderabad. Now, Sir, over a period of forty years, we have, to and fro, almost sixty flights from Bangalore to Delhi, and if it is a hopping flight, it is 100 flights from Bangalore to other parts of the country. Sir, for your kind information, Bangalore has got a third largest air traffic in the country, and it is a third largest airport. Is it a model of Mr. Narendra Modi in Gujarat? If you talk of the healthcare, if you talk of education, the position is like this. On the 4th, there was my question in the Rajya Sabha. My question was on the education of the girl child in the country. Whether with 74.4 per cent of girls between 15 and 17 years in schools, Gujarat ranks twentieth among 21 major States? मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूँ कि the answer from Mr. Prakash Javadekar is: "Yes, Sir, as per the sample survey registration system, based on survey-2014 of the office of the

[Shri B. K. Hariprasad]

Registrar General of India, Gujarat has 73.4 per cent of girls between 15 and 17 years in school, and ranked twentieth out of the 21 major States." Sir, in terms of education, if you compare Shri Narendra Modi's model in Gujarat and the Congress model in Karnataka, we have got thirty districts; twenty-seven districts have got a medical college, with full-fledged hospital with 300 beds, and so far as private medical colleges are concerned, we have six major medical colleges. If you take example of the engineering, about two lakh people pass out of these engineering colleges from Karnataka. What is the status of Mr. Narendra Modi's model in Gujarat?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Please conclude. Your time is over.

SHRI B. K. HARIPARASAD: Sir, my time is not over ...(*Interruptions*)... I am still here. I have got two more years, Sir. My time is not over. My party has got more time. Let me speak ...(*Interruptions*)... महोदय, अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं बोलना है, तो मैं नहीं बोलूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): मैं तो यही चाहता हूँ कि आप बोलें, मगर समय चाहता है कि आप उसका ध्यान रखें।

श्री बी. के. हरिप्रसाद: आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इतना लंबा-चौड़ा बोलने देते हैं, हमें नहीं बोलने देंगे, तो यह कैसे होगा? मैं एक ही बात बोल कर खत्म करना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): बोलिए, आपकी पार्टी का टाइम कम हो जाएगा।

श्री बी. के. हरिप्रसाद: महोदय, मैं एक मिनट बोल कर अपनी बात खत्म करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): हां, खत्म करिए।

श्री बी. के. हरिप्रसाद: आप सुन लीजिए, महोदय। प्रधान मंत्री ने परसों बेंगलुरु में जाकर कहा कि कांग्रेस की सरकार 10 परसेंट कमीशन लेती है। सर, राफेल का कमीशन कितना है, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं मानूँगा और 10 या 20 परसेंट क्या है, मैं बता दूँगा। अगर इनके पास 10 परसेंट का सबूत है, तो इसकी जाँच करा लीजिए। अगर मुख्य मंत्री के खिलाफ एक भी सबूत बाहर आ गया, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। सत्य से दूर ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। वे प्रधान मंत्री हैं, पंचायत मेम्बर नहीं हैं। वे स्वयं को प्रधान सेवक बोलते हैं। उनको चुनाव के लिए सत्य से दूर ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। We, the south Indian people are peace-loving. Let them not go and disturb the State. They will be taught a lesson this time. Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak.

SHRI K.T.S. TULSI (Nominated): Sir, thank you and I want to speak about the feasibility of simultaneous elections. We, in our country, have adopted Parliamentary democracy. Parliamentary democracy does not only give the fixed term to the Houses

of Parliament and to the State Legislatures; Parliamentary democracy also makes the Government accountable to these elected Houses for every minute of their stay in the Government. To say that in the interest of stability, the accountability should be sacrificed, is to launch a lethal attack on the basic structure of the Constitution. The basic structure of the Constitution is where our Houses are elected but the Government remains answerable to them and the minute they lose the confidence of the House, they are required to go. I believe that this an idea which is incapable of being upheld because the Parliament does not have even the right to alter the basic structure of the Constitution. Accountability in Parliamentary democracy has been held in *Keshavanand Bharati* case to be a part of the basic structure of the Constitution. I fail to understand as to how such a blatantly unconstitutional idea is gaining currency.

I would also like to submit that it is my view that such a structure is also destructive of the federal fabric of India. We have 30 States now. Apart from that, it is completely impractical. How will it function in a federal structure where every State has a fixed term? But there is accountability. The moment they lose power, they are dissolved and fresh elections have to be held. Does the Government want to say that there will be no accountability so far as the States are concerned? Are the States going to give up their Parliamentary model? It is just not possible. I think, the Government is prioritizing stability over democratic principles which is not a good thing because, after all, we can't expect that simultaneous elections are only being propagated for the fact that there will be dominance of the Central leadership in the election process. But, what about the local issues? The local issues will not be given due importance because in this case where the national leadership has huge amounts of funds at their disposal, the States will lose out on being able to present the local issues in front of the people. Also, there are instances of this even in the recent past that there is one party voted in the Centre, but within months it loses the elections in States, like in Delhi and in Bihar. That is because of the federal structure of our Constitution. If you don't want to give space to States, I am sorry to say that it will amount to a completely unconstitutional exercise. This is a danger to democracy. I believe this is destructive of the concept that Union and States are equal. They cannot be subjugated in this fashion through the subterfuge. This is an idea which is mindlessly brought in for the purpose of greed to stay in power and it tantamounts to sacrificing the democratic polity. It will also end up only in multiplying the influence of money power and neither of this is good for the nation. Thank you.

SHRI JOY ABRAHAM (Kerala): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I am thoroughly disappointed with the Address of the President. It is not

[Shri Joy Abraham]

his fault. It is a Constitutional obligation and at the same time, it is ceremonial. But, the President's Address should reflect the realities in the country. Here the President should have spelt out Government's policies and programmes, at least, for one year. Amit Shahji has pointed out the so-called great achievements and our LoP, Ghulam Nabi Azadji gave a befitting reply that all those programmes are repacked ones. But, there is one thing in the Address, there is a passing reference to Government's commitment to double farmers' incomes by 2022. The year 2022 has an importance because it is the 75th Anniversary of our Independence. The Government should at least do justice to the President, to the office of the President. The President is the Supreme Commander of the Armed Forces. There is no reference to our relations with Pakistan and China. The standoff on Doklam, there is no reference. There is no reference to daily casualties of our Armed Forces suffered at Line of Actual Control or International Border. The soldiers are bleeding, the civilians are also bleeding, and Jammu and Kashmir is bleeding. There is no reference to the alarming situation in Jammu and Kashmir. Of course, there is a reference to the presence of ten Heads of States in our Republic Day celebrations. It is well and good. This is part of geopolitics, we can understand. But, there is a danger. The Free Trade Agreement we have signed with these ten ASEAN countries is actually ruining our domestic cultivators and cash crops. There is no remunerative price for our domestic products. Further there is a proposal for a new treaty, RCEP, involving Japan, China, Australia, South Korea, New Zealand and India. Ten ASEAN countries, plus these six countries, with these sixteen, negotiations are going on. For a new treaty, we have to be very cautious because that may ruin our agriculture and the cultivators. They are not getting remunerative prices. Of course, there is a slogan put forward by the Prime Minister, 'Make in India'. It is good. But there should have been another slogan, “Grow in India”. All agriculturists are deserting cultivation because it is not profitable. The recent cyclone, Ockhi devastated three States- Kerala, Tamil Nadu and Lakshadweep. So many casualties were there. Many fishermen were missing. There is no trace about them. Our searches have not succeeded. Of course, the Central Government helped in searching. Our Armed Forces have done a good job, but rehabilitation of Ockhi victims is a must. The Central Government has to come with a package to help these poor fishermen. This is actually a national calamity. There is no hindrance in declaring Ockhi as a national calamity and help the victims. The Government must come forward. There is no reference in the President’s Speech regarding the prevailing atmosphere in the country. Shri D. Raja was saying that there is violence, there is intolerance, there is hatred, there is mistrust and also atrocities against *Dalits*, minorities and lynching incidents by *gau rakshaks*, lynching of migrant workers, communal violence in various parts of the country, including the latest

Kasganj in UP, growing attacks on freedom of speech and expression as manifested in the heinous killings of Gauri Lankesh, Kalburgi, Narendra Dabholkar, Govind Pansare. The atrocities were especially on women and children. The Government has to put down this violence and intolerance with an iron hand. There is nothing in the Address about these things. Amit Shahji was boasting about the mandate the BJP got, and ironically he mentioned Manipur and Goa. Ahmed Patelji gave a befitting reply. Actually, democracy was killed brutally in Manipur and Goa. Sir, I will conclude my speech with a few more points. Democracy should be preserved in this country at any cost. The BJP came to power with absolute majority, but that absolute majority is now coming down and I think, you still have got absolute majority. Together with the allies you have got a thumping majority. So, your obligation is also great. You have to lead the country. Democracy should be preserved at any cost and federalism should be preserved. The State should be given its due. I have some more points to say. I will say it during the Budget discussion. Regarding the state of affairs of Kerala's cultivators, especially the rubber cultivators, all the cash crop growers are in distress in Kerala because of the wrong import policy of this Government. Nothing was done. Only lip service was given to save the agriculturists and cultivators and that is why I have said that cultivators are deserting agriculture. There should be "Grow in India" to balance "Make in India." Thank you.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र): महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहला अभिभाषण संसद में हुआ, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं यहां पर खड़ी हूँ। मैं सिर्फ तीन-चार मुद्दों को स्पर्श करूंगी, क्योंकि बाकी सभी सदस्यों ने बहुत सारे मुद्दों पर यहां बोल दिया है।

महोदय, मैं ये चार लाइनें बताकर शुरुआत करूँगी, कि:—

"हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
तस्वीर बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही,
जो कहीं हो आग, वह सुलगनी चाहिए।"

महोदय, हंगामा खड़ा करना, हमारा, विपक्ष का मकसद कभी भी नहीं था। जो तस्वीर बदलने की बात हम करते हैं, उस तस्वीर को बदलने का काम अगर किसी ने शुरू किया, तो वह हमारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। मैं यहां पर बताना चाहती हूँ कि ...**(व्यवधान)**... मैं यहां पर बताना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता आन्दोलन के दरम्यान ...**(व्यवधान)**... दादा, आप सुन लीजिए। मुझे गर्व है कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती हूँ। मेरे नाना जी 1916 में गदर मूवमेंट में फांसी पर चढ़ाये गये थे। मैं उस परिवार से आती हूँ, इसलिए मुझे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति ज्यादा ममत्व है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जिसने स्वतंत्रता आन्दोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है, यह बात मैं यहां बताना चाहती हूँ। तिलक, गोखले, जो महाराष्ट्र से थे,

[श्रीमती रजनी पाटिल]

गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद जी, सरदार पटेल जी, कितने नाम हम गिनायें, जो कांग्रेस से जुड़ कर स्वतंत्रता आन्दोलन चलाते रहे! जो सरदार पटेल जी का नाम लेकर आज ये लोग डंका बजा रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि सरदार पटेल जी ने ही गोलवलकर गुरु जी को एक चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि समाज का एक समूह, एक विचारधारा गांधी जी की हत्या हो, इसका वातावरण तैयार करने में लगा है। वह कौन सा समूह है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इन लोगों को अच्छे से मालूम है।

महोदय, नेहरू जी ने इस देश में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की शुरुआत की, उसे मज़बूत करने की कोशिश की। मुझे यह कहने में कतई भी हिचक नहीं है। मैं यहां पर यह बताना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया शैड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की तरफ से कांस्टीट्युएंट एसेम्बली के लिए हमारे दो कैंडिडेट्स चुनाव के लिए खड़े थे, जिनमें से एक बी.आर. अम्बेडकर थे और दूसरे मंडल थे। उसमें मंडल जी चुन कर आ गये, लेकिन जब हिन्दुस्तान का विभाजन हो गया, तो वे सुहरावर्दी की गवर्नमेंट में पाकिस्तान चले गये और हमारे अम्बेडकर जी को वहां पराभूत होना पड़ा। अम्बेडकर जी जब पराभूत हुए, ...**(व्यवधान)**... आप आगे सुनिए। आप सुनने की क्षमता रखिए। जब अम्बेडकर जी पराभूत हो गये, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी ने एक लेटर तब के हमारे महाराष्ट्र के, मुम्बई प्रान्त के सीएम श्री बी.जी. खेर को लिखा कि अगर हमें अम्बेडकर जी को कांस्टीट्युएंट एसेम्बली में लाना है, तो वहां पर जगह बना दीजिए। मैं बहुत अभिमान के साथ कहना चाहूँगी कि हमारे ही मुम्बई प्रान्त के, हमारे ही महाराष्ट्र के मिस्टर एम.आर. जयकर ने रेजिग्नेशन दिया, ताकि उनकी जगह पर वे चुन कर आयें और आखिर उनकी जगह पर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर चुन कर आ गये और उन्होंने संसद में कांस्टीट्युएंट एसेम्बली के तहत संविधान लिखने का काम किया।

महोदय, इन लोगों की तो यह अपेक्षा थी, उनका तो यह माहौल बनाने का काम चल रहा था कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास शिक्षा है, सिर्फ वही लोग वोटिंग करें, लेकिन पहली बार हमारे पंडित नेहरू जी ने और उनके सभी साथियों ने उसका विरोध किया। सर, मैं रिकॉर्ड पर बताना चाहती हूँ कि 1937 में जब हिन्दुस्तान में पहली बार चुनाव हुए, उसमें मेरे पिता जी भी सतारा कांस्टीट्युएंसी से चुन कर आये थे। तब मतदान कौन करते थे– सिर्फ टैक्स भरने वाले व्यक्ति। जो आदमी सारे टैक्सेज़ भरता था, वही मतदान करता था। जब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाना शुरू किया, तब उन्होंने सभी लोगों को, महिला सहित सभी लोगों को वहां पर मतदान करने का अधिकार दिया। मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहती हूँ। ...**(व्यवधान)**...

सर, लोकशाही का मन्दिर जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हमारे नेहरू जी ने बोला। जब भाखड़ा-नांगल का बांध बनाया गया, तब उन्होंने बोला कि अगर लोकशाही का मंदिर कोई है, तो यह बाँध है। इसकी शुरुआत, हिन्दुस्तान की नींव अगर किसी ने रखी है, तो पंडित नेहरू ने रखी है। इसमें किसी को भी शक नहीं है। IIT हो या IIM हो, रशिया ने भी हमारा साथ दिया। यहां पर IIT, IIM, नवरत्न कम्पनीज़, ये सब लगाने की कोशिश और हिन्दुस्तान का नविनर्माण करने की कोशिश पंडित नेहरू जी ने की। उनके बाद शास्त्री जी आये। शास्त्री जी ने यहां पर "जय जवान, जय किसान" का नारा लगाया। इंदिरा गांधी आयीं, तो इंदिरा जी आंधी की तरह एक के बाद

एक डिसीज़न लेती गईं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सर्वसामान्य लोगों के लिए, गांव-गरीबों के लिए, जिन्हें बैंकों में खड़ा नहीं होने दिया जाता था, वहां पर आम जनता को सम्मिलित करने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह इंदिरा गांधी जी ने किया है। राजीव गांधी जी के बारे में बताना मेरे लिए तो अहम भाग्य का क्षण है, क्योंकि राजीव गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी वजह से 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण दिया गया। आज हमारी जैसी जिला परिषद से आई हुई महिलाएं भी यहां पर राज्य सभा में अगर बात कर रही है, तो इसके लिए हमें सिर्फ राजीव गांधी जी की दूरदृष्टि को श्रेय देना चाहिए। Twenty-first century, जिसको 21वीं शताब्दी बोलते हैं, हमें उसमें ले जाने का काम राजीव गांधी जी ने किया। 18 साल के बच्चों को मतदान देने का अधिकार भी राजीव गांधी जी ने हमें दिया।

सर, डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन दस सालों में जितने निर्णय हुए, उनको ये खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन आरटीआई एक्ट, जिसका बजट उन्होंने कम कर दिया है, फूड सेक्युरिटी एक्ट, मनरेगा, 33 परसेंट रिजर्वेशन, ये सब मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ है और सोनिया गांधी जी के आग्रह से राज्य सभा में महिलाओं को 33 परसेंट रिजर्वेशन से संबंधित बिल पारित कर दिया, लेकिन मैं आज सुबह भी इस पर बोली हूँ कि अगर इनकी राष्ट्रीय इच्छा-शक्ति हो, उनके मन में खोट न हो, उनके इरादों में खोट न हो, तो लोक सभा में इनके जो बहुत सारे लोग चुन कर आए हैं, वे हमेशा बोलते हैं कि हमारे लोग चुन कर आए हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है, इसलिए महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन कर देना चाहिए।

सर, मैं यहां पर बताना चाहती हूँ कि ये हमेशा बोलते रहते हैं कि 60 सालों में कुछ नहीं किया। चूंकि समय की पाबंदी है, इसलिए दो-तीन मिनट्स में ही मैंने गिनवा दिया कि हमने यानी इस गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया है, लेकिन मुझे याद है कि जम्मू-कश्मीर का एक बड़ा टनल, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा टनल, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया। वह टनल यूपीए सरकार में बना और उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, लेकिन मोदी जी ने भाषण किया कि 60 साल में हिन्दुस्तान में कुछ नहीं हुआ है। वे जहां पर खड़े होकर टनल का उद्घाटन कर रहे थे, उसी टनल के बाजू में खड़े होकर वे बोलते हैं कि 60 साल में कुछ नहीं किया। मैं मोदी जी के मन से जरूर सहमत हूँ कि अगर 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो साढ़े तीन सालों में आप जो कर सके, वह हम नहीं कर पाए। आपने लोगों को आपस में लड़ाया, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या लिखना है, क्या देखना है, इन सबके ऊपर पाबंदी और restriction लगाने का जो काम मोदी जी ने किया, वह हमने 60 सालों में बिल्कुल कभी नहीं किया।

सर, चूंकि मैं एक किसान परिवार से आती हूँ, इसलिए मैं किसानों के बारे में बोलना चाहती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किसानों के बारे में यह बोला कि किसानों को डेढ़ गुना एमएसपी देने का निर्णय कर लिया है। इस संबंध में डा. स्वामीनाथन जी की जो एक रिपोर्ट है, उसको आज लागू करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, पवार साहब यहां बैठे हैं, वहां पर साढ़े तीन सालों में 13 हजार लोगों ने आत्महत्या की है। परसों ही हमारे धूलिया के धरमा पाटिल नामक एक किसान है, जिसने मंत्रालय में मुख्य मंत्री के दालन में जाकर विषपान कर लिया और आत्महत्या कर ली।

(**श्री उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

मुझे लगता है कि अगर आपकी सही मंशा है कि किसानों को राहत दी जाए, तो किसानों की आमदनी दुगुना करने के लिए एक तो कर्जा मुक्ति होनी चाहिए और दूसरी, उसके लिए आवश्यक प्रावधान करने चाहिए।

सर, 2020 में हमारा हिन्दुस्तान सबसे युवा देश होने वाला है, सबसे ज्यादा युवा हमारे हिन्दुस्तान में होने वाले हैं। प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन साढ़े तीन सालों में उन्होंने 2 लाख लोगों को भी रोजगार देने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे बच्चों को उलटा बोल रहे हैं कि आप यह बेचो, वह बेचो। मुझे लगता है कि हमारे देश का आदमी, देश का तरुण गरीब जरूर है, लेकिन वह अपना आत्मसम्मान कभी नहीं बेचेगा।

सर, मैं अंत में इतना ही बोलूंगी कि राष्ट्रपति जी ने बोला, "वसुधैव कुटुंबकम"। उन्होंने ''वसुधैव कुटुंबकम'' करके शुरुआत की, लेकिन आज देश में जात के ऊपर, मजहब के ऊपर, हर प्रदेश के ऊपर, लिहाज के ऊपर, खान-पान के ऊपर हर चीज के ऊपर झगड़े चलते हैं। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. Rajaniji, your time is over.

श्रीमती रजनी पाटिलः सर, मैं आधा मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूँ। महाराष्ट्र में हाल ही में भीमाकोरे गांव की घटना हुई और यह घटना यह रेखांकित करती है कि लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, 'When I crossed my street, they asked my caste; when I crossed my district, they asked my religion; when I crossed my State, they asked my language. I became an Indian only after when I crossed my country.' इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Sanjay Singh. I know it is your maiden speech. That's why you can take a maximum of 15 minutes.

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)ः उपसभापति महोदय, सदन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अनेक विषयों पर चर्चा की, विपक्ष ने यहां उस पर कई मुद्दे भी उठाए, कई बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है, वह देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। यह बात हम सांकेतिक नहीं कह रहे हैं, इस सदन का कोई सदस्य ऐसा नहीं कह रहा है, बल्कि हिन्दुस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के चार प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने, आजादी के बाद पहली बार देश में यह घटना हुई, जब चार न्यायाधीशों ने एक साथ कहा कि हिन्दुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान के लोकतंत्र पर आज जिस प्रकार से एक-के -बाद दूसरा हमला हो रहा है – यह लोकतंत्र हमें आसानी से हासिल नहीं हुआ है, आजादी हमें आसानी से हासिल नहीं हुई है, यह

संविधान हमें बहुत आसानी से हासिल नहीं हुआ। इस देश के संविधान और आजादी को पाने के लिए शहीदे आजम भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरू ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्लाह ने, राजेंद्र लिहड़ी ने, खुदीराम बोस ने अपनी कुर्बानी दी। जब देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, उनके त्याग और बलिदान से यह देश आजाद हुआ है। किसी फर्जी राष्ट्रवादी के त्याग और बलिदान से यह देश आजाद नहीं हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से देश में हालात पैदा किए जा रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को, ऐसी सरकार को जिसे प्रचंड बहुमत से देश की जनता ने चुना, उस सरकार को चलने नहीं दिया जाता – चाहे वह वेस्ट बंगाल की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो – एक निर्वाचित सरकार, जिसे 70 में से 67 विधायकों का बहुमत मिला, हमसे इस देश की सरकार की क्या दुश्मनी है, मुझे समझ नहीं आता।

चुनावों में हमारे प्रधान सेवक ने, देश के प्रधान मंत्री जी ने, वे देश के प्रधान अभिभावक भी हैं, मुझे तकलीफ है, कष्ट है, इस बात की पीड़ा है कि जब देश के प्रधान सेवक ने रामलीला मैदान से कहा कि अरविंद केजरीवाल एक नक्सलवादी है, इसे जंगल में भेज देना चाहिए। मुझे इस बात की तकलीफ है, पीड़ा है कि इस देश का प्रधान सेवक एक व्यक्ति को नक्सलवादी कहकर सम्बोधित करता है। मैंने उसी दिन कहा था कि प्रधान मंत्री जी, यह लोकतंत्र है, जम्हूरियत है, डेमोक्रेसी है, जहां जनता मालिक होती है। जिसे जनता चाहती है वह जंगल में जाता है और जनता जिसे चाहती है, वह विधान सभा में जाता है। देश की जनता ने 67 विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधान सभा में भेजा है और तीन विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जंगल में भेजने का काम किया है।

मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, ...**(व्यवधान)**... नफरत की बुनियाद पर हिन्दुस्तान नहीं चलेगा। ...**(व्यवधान)**... मोहब्बत की बुनियाद पर हिन्दुस्तान चलेगा। ...**(व्यवधान)**... आम आदमी की आवाज़ को दबाने की कोशिश मत करिए। ...**(व्यवधान)**... सही सुनने की क्षमता रखिए। ...**(व्यवधान)**... मैं कहना चाहता हूं कि ये वे लोग हैं ...**(व्यवधान)**... जो इस देश को बरबाद करना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो ताजमहल को तोड़ना चाहते हैं। जब हम यहां आए तो आपने हमें सौगंध दिलाई कि इस देश के संविधान की रक्षा करूंगा, इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, लेकिन मुझे जरा बताइए, जब इनका एक चुना हुआ विधायक कहता है कि ताजमहल इसलिए तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसे मुगलों ने बनाया है। मैं कहना चाहता हूं कि आप कुतुब मीनार भी तोड़ डालो क्योंकि उसे भी मुगलों ने बनाया। ...**(व्यवधान)**... पार्लियामेंट भी तोड़ डालो, देश का राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, ...**(व्यवधान)**... मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान किसी नक्सलवाद की बुनियाद पर नहीं बनेगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Don't make such comments sitting there. Don't do that. You are in the Treasury Benches. You should be more responsible.

श्री संजय सिंहः अगर सही मायने में हिन्दुस्तान को बनाना है, हिन्दुस्तान को आगे ले जाना है, ...**(व्यवधान)**... ये कहते हैं कि मारो, काटो, लोगों को बरबाद करो और हम कहते हैं कि बेघर लोगों को आबाद करो। यह हमारा राजनीति का हिस्सा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should be more responsible.

श्री संजय सिंहः यह गंगा-जमुनी तहज़ीब का देश है। यह वह देश है जहां बिस्मिल्ला खां की शहनाई संकट-मोचन के मंदिर में गूंजती है। यह वह देश है जहां मलिक मुहम्मद जायसी पदमावत लिखते हैं। यह वह देश है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं – 'मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतरयामी, मैं तुझसे क्या मांगूं?' अगर इस देश के अंदर नफरत की बात की जाएगी, भाई से भाई को बांटने की बात की जाएगी, हिन्दू से मुसलमान को लड़ाने की बात की जाएगी, अगड़ा-पिछड़ा और दलित-स्वर्ण की बात की जाएगी, तो मुझे बहुत अफसोस है कि इस देश के लोकतंत्र को आज इस प्रकार से कुचलने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के अंदर एक निर्वाचित सरकार है। उस निर्वाचित सरकार के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल हैं। क्या गुनाह है उस केजरीवाल की सरकार का? क्या उसका यह गुनाह है कि वह बिजली आधे दाम पर देती है? क्या यह गुनाह है कि वह पानी मुफ्त देती है? क्या यह गुनाह है कि हमने किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया? क्या यह गुनाह है कि हमने "मोहल्ला क्लीनिक" खोला? मान्यवर, क्या हमारा यह गुनाह है कि शिक्षा के स्तर को हमने हिन्दुस्तान में सबसे बेहतर बनाने का काम किया? हमारा गुनाह क्या है? हमारा अपराध क्या यह है कि हम एक चुनी हुई सरकार को अच्छे ढंग से संचालित करना चाहते हैं? केजरीवाल की सरकार को लाट साहब के डंडे से आप चलाना चाहते हैं। लाट साहब के डंडे को बंगाल से दिल्ली तक आप चला रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है। इसको बरबाद करने की कोशिश मत कीजिए। उत्तराखंड में आपने निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। गोवा के अंदर आपने तिकड़म से सरकार बना ली, आपने मणिपुर में तिकड़म से सरकार बना ली और अब उसको अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार को, आज एक चुनी हुई सरकार को, 70 में से 67 विधायकों वाली सरकार को अगर ये सरकार नहीं चलने दे रही है, तो इसका मतलब लोकतंत्र में हमारी कोई आस्था नहीं है। ...**(व्यवधान)**... लोकतंत्र में हमारी कोई आस्था नहीं है। एक मिनट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप जब बोल रहे थे, तो हम सुन रहे थे।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में बड़े-बड़े वादे किए थे। घोषणा-पत्र जनता के साथ आपका करार होता है। देश के प्रधान मंत्री ने चुनावी रैलियों में बड़े-बड़े वादे किए थे, वह आपका इस देश की जनता के साथ करार है, उस वादे को आपको पूरा करना चाहिए। आपने कहा था, इतना काला धन लाएँगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपये जमा हो जाएँगे। आज तक 15 रुपया भी किसी आदमी के खाते में नहीं पहुँचा। ...**(व्यवधान)**... मैं उम्मीद करता था कि अध्यक्ष जी यहां रहेंगे। आपने चुनाव में कहा कि दो करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार का वादा आपने पूरा नहीं किया। आपके कार्यकाल में 84 प्रतिशत रोजगार घटा है। आपने किसानों से कहा, कर्जा माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधान मंत्री जी ने चुनावी रैलियों में कहा, हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ क्रूर मजाक करने का काम किया है। आपने एक पैसे का कर्जा माफ किया, दो रुपये का कर्जा माफ किया, तीन रुपये का कर्जा माफ किया। आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ एक क्रूर मजाक करने का काम किया। अगर हम व्यापारियों की बात करें, तो जिस व्यापारी ने आपको अपने कंधे पर उठा कर देश की सरकार बना दी, जिस व्यापारी ने लाइन में लग कर आपको इतने वोट्स दिए, उन देश के व्यापारियों से आपकी

क्या दुश्मनी है, ज़रा हमको बताइए। पहले नोटबंदी लाते हैं, फिर जीएसटी लाते हैं, फिर रिटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई लेकर आते हैं, अब उनकी जो बची-खुची दुकानें हैं, उनकी सीलिंग करके पूरी दिल्ली में उनको उजाड़ने का काम करते हैं। आपने 7 लाख व्यापारियों को बरबाद किया। आपने किसानों को * दिया, आपने नौजवानों को * दिया, आपने व्यापारियों को * दिया, आपने इस देश के आम आदमी को * दिया और आप कहते हैं कि आप इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं, आप इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा रहे हैं।

मान्यवर, आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को इस सरकार ने एक के बाद दूसरी, जिस तरह से उत्पीड़न करने का काम किया है कि हमारे 15 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। विधायकों को तो जेल में डालना दूर की बात है, हमारे एक विधायक श्री सोमनाथ भारती हैं, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के 40 जवान पहुँचे थे, 40 जवान! यह है आपकी सरकार। इस प्रकार से आप विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनका गला घोंटने की, उनकी लोकतंत्र की हत्या करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आपने दिल्ली के मुख्य मंत्री के कार्यालय पर सीबीआई का छापा डलवा दिया, आपने शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर छापा डलवा दिया, आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री के घर पर छापा डलवा दिया। आप दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देना चाहते। संसदीय सचिव बनाने के नाम पर आपने हमारे 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करवा दी। वही संसदीय सचिव की हरियाणा में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव की हिमाचल प्रदेश में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव की पंजाब में सदस्यता रद्द नहीं होती, वही संसदीय सचिव की असम और मिजोरम में सदस्यता रद्द नहीं होती, लेकिन दिल्ली में 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करके आपने लोकतंत्र की हत्या की है। ...**(व्यवधान)**... लोकतांत्रिक संस्थाओं को आप कुचलने का काम कर रहे हैं। आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**... मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को लाट साहब के डंडे से चलाने की कोशिश मत करो, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे।

"चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी,
यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का,
मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से,
वही दावा करता है इस चमन की रहनुमाई का।"

आप इस चमन की रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। आप इस मुल्क के गरीब के दर्द को समझने की कोशिश करिए। यह लोहिया का देश है, यह गांधी का देश है, यह जे.पी. का देश है। डा. लोहिया ने नारा दिया था, "राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान" और डा. लोहिया ने यह भी नारा दिया था कि "जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा"। झारखंड के अंदर कोयला देवी की 11 साल की बच्ची संतोषी, भात-भात कह कर मर जाती है। 70 साल के बाद आज भी इंसान भूख से मर रहा है और आपकी सरकार को, यह * की सरकार है, जिसको * नहीं आती। भूख से, गरीबी से लोग देश के अंदर मर रहे हैं और आप यहां बैठकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

3.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you comment? Let him speak. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंहः एक बात के लिए मैं इस सरकार से सहमत हूं, एक बात के लिए मैं इस सरकार की तारीफ करूंगा। मेरे विपक्ष के मित्र, हो सकता है मुझसे सहमत न हों। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a shortage of time. Please don't provoke. …(*Interruptions*)…

श्री संजय सिंहः लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो नम्बर एक पर यह सरकार आएगी, दो नम्बर पर नहीं आएगी। मान्यवर, यह मैं कह सकता हूं। मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है इस सरकार के ऊपर। साथियो, किस प्रकार का हिन्दुस्तान आप बना रहे हो? आप 40 हजार रुपए का कर्जा नौजवानों को देकर बार-बार मुद्रा-मुद्रा-मुद्रा करते हैं। आपने कितनी मुद्राएं देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दी हैं, उनको क्या आप सुनना चाहेंगे? रिलाएंस ग्रुप पर एक लाख पच्चीस हजार करोड़ का कर्जा, वेदान्ता ग्रुप पर एक लाख तीन हजार करोड़ का कर्जा, एस्सार ग्रुप पर एक लाख एक हजार करोड़ का कर्जा, अदानी ग्रुप पर 96 हजार करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पर 75 हजार करोड़ का कर्जा, जे.एस.डब्ल्यू ग्रुप पर 58 हजार करोड़ का कर्जा, जी.एम.आर. ग्रुप पर 47 हजार करोड़ का कर्जा, लेंटे ग्रुप पर 47 हजार करोड़ का कर्जा, विडियोकॉन ग्रुप पर 45 हजार करोड़ का कर्जा, वी.जी. ग्रुप पर 33 हजार करोड़ का कर्जा, कुल 8 लाख 55 हजार करोड़ का कर्जा बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। मान्यवर, मोदी जी की सरकार कहती है कि 9 हजार का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार कहती है कि 9 हजार करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बिठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। मान्यवर, ये यह काम करना चाहते हैं। मान्यवर, ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की गंगा-जमुनी तहज़ीब को बरबाद करना चाहते हैं। आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। हो सकता है कल को कोई पार्टी सत्ता में रहे, फिर दूसरी पार्टी सत्ता में रहे, आज आप हमारी आवाज को दबा सकते हैं और मुझे आपका दर्द भी समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के तीन सांसद आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के इतने मित्र मिलकर किस प्रकार से एक आदमी की स्पीच नहीं होने दे रहे हैं। यह आपकी बौखलाहट का नतीजा है। परेशान मत होना, मैं 6 साल यहां रहूंगा और एक-एक दिन आपके लिए मुश्किल का दिन होगा। घोटाले कर रहे हो राफेल में, उसको भी उजागर करेंगे, भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसको भी उज़ागर करेंगे, lynching करा रहे हो, उसको भी उजागर करेंगे। आम आदमी की आवाज को खामोश नहीं रहने देंगे। सीलिंग से व्यापारियों को उज़ाड़ रहे हो। उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, देश के अंदर तानाशाही ला रहे हो, उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; time over. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंहः आम आदमी की आवाज़ को इस देश के अंदर दबाया नहीं जा सकता है। आपका हिन्दुस्तान की आज़ादी में क्या इतिहास है? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, your time is over. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंहः आपका हिन्दुस्तान की आज़ादी में क्या इतिहास है? आप दूसरों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं! आप सबको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं! ...**(व्यवधान)**... सर, एक मिनट। मैं अंतिम एक मिनट लेना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

कुछ माननीय सदस्यः सर, यह इनकी maiden speech है, इन्हें बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is for me to decide. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंहः ये सबको पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। ये सबको राष्ट्रवाद का प्रमाण-पत्र बांटते हैं! ..**(व्यवधान)**.. इनकी जो मातृ संस्था है, आरएसएस, उसने अपने कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं! ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sanjay Singh, your time is over. ...(*Interruptions*)... Now sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंहः ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं! जिन्होंने पठानकोट में आईएसआई को बुलाकर हमारे शहीदों की जांच कराई, वे हमसे राष्ट्रवाद का प्रमाण-पत्र मांगते हैं! जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आपका टाइम समाप्त हो गया है। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Please sit down. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंहः सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पर पकड़ा गया, वे हमसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट मांगते हैं!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; Shri Abdul Wahab. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंहः जो अफज़ल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ जम्मू-कश्मीर में सरकार चलाते हैं ...**(व्यवधान)**... वे हमसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट मांगते हैं! मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**... मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि तानाशाही को इस देश में रोकिए। ...**(व्यवधान)**... तानाशाही से देश नहीं चलेगा। ...**(व्यवधान)**... यह देश तानाशाही से नहीं चलेगा, उजाड़ने से यह देश नहीं चलेगा ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not going on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश)**:** यह ठीक नहीं है। ..**(व्यवधान)**..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order? संजय सिंह जी, बैठिए। Your time is over. ...(*Interruptions*)... What is your point of order? ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: It is under Rule 235, sub-rule (ii). It says, "Whilst the Council is sitting, a Member shall not interrupt any Member while speaking by disorderly expression or noises." And this House has a convention when

[Shri Sukhendu Sekhar Ray]

a new Member speaks, when it is his maiden speech, nobody should interrupt. But the Treasury Benches all along disturbed him. ...(*Interruptions*)... That should be condemned by each and everybody present in this House. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen to me. ...(*Interruptions*)... I uphold the point of order. I agree that the convention in this House is that maiden speech is never interrupted. I told the interrupters many a time, yet interruption came. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: They should be named. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवालः आप रूल 255 देखिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... I have already said that I don't approve of that interruption, especially when it is against the Member making his maiden speech. ...(*Interruptions*)... However, the one who makes his maiden speech also, he is expected to obey the Chair. ...(*Interruptions*)... Time allotted to him is fifteen minutes. That is over. You should now take your seat. ...(*Interruptions*)... Listen to me. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः अगर उनकी पार्टी के सदस्य एक घंटा बोल सकते हैं तो ये क्यों नहीं बोल सकते? **...(व्यवधान)...**

श्री संजय सिंहः सर, मैं केवल दो मिनट का समय और लूंगा। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती विप्लव ठाकुरः अगर वे एक घंटा बोल सकते हैं तो ये क्यों नहीं बोल सकते? **...(व्यवधान)...**

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Let him speak. ...(*Interruptions*)... He spoke for one hour. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापतिः मिस्त्री जी, आप बैठिए। **...(व्यवधान)...** Mistryji, sit down. ...(*Interruptions*)... Listen to me also. ...(*Interruptions*)... Please listen to me. ...(*Interruptions*)... Already my throat is not good. So, have some sympathy on me. Before he started, I told him that his time is fifteen minutes. He spoke for seventeen minutes. I have noted it. ...(*Interruptions*).. There is a tendency of some Members that when the speech is palatable they want it to continue. But when the speech is not palatable, they want the Chair to stop it. ...(*Interruptions*)... This cannot be allowed. The Chair cannot act according to the whims and fancies of Members. So, you sit down ...(*Interruptions*)... Mr. Wahab. Nothing else will go on record...(*Interruptions*)... Mr. Wahab will speak.

श्री संजय सिंहः सर, मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. Mr. Sanjay Singh, you sit down ...(*Interruptions*)...

श्री संजय सिंहः *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Wahab, you speak. Your time is only five minutes.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. First of all, after Shri Sanjay Singh's speech, it is very difficult to speak here. I appreciate Mr. Sanjay Singh. In his maiden speech, he was doing this. I hope, I had been like that 10 years back. When I was to make my maiden speech, I could not speak one word. But now he is taking his fifteen minutes plus. Anyway thank you. With all the differences amongst the Opposition Bench, I appreciate the Government of Modiji! I appreciate because they are taking great care in Muslim women's case! As a Muslim, I am appreciating the efforts taken by the Government to protect the rights of Muslim women. Sending them to streets, and their husbands to jail and you see, I am very much appreciating! And more than that ...(*Interruptions*)... about the Triple Talaq Bill ...(*Interruptions*)... There were some efforts made by the Ministry of External Affairs. There was the initiative for changing the passport colour to orange instead of blue for classifying the Indians under different category – working class, business class and all. That was also under pipeline. I don't know what happened. It was there in the newspapers. I appreciate these sort of activities because 2019 election is coming up. So, the people can take a decision now itself. I hope that these sorts of actions will continue. And under the leadership of Mukhtar Abbas Naqviji, the Minorities have got a lot of hope on Abbasji about looking after the minority issues and all. And especially in the case of Haj, they are taking good steps by reducing whatever subsidy we have. They have already taken it back. The Supreme Court had given ten years, but now the Government has taken it back in 8 years itself. So, they are taking good steps. So, these aspects, as member of IUML, I appreciate! And, it should continue just like this! This sort of Muslim appeasement should be continued, so that we can come in more numbers to this House! So, this is my sincere submission. I am not taking much of the time. Everything has been told by Sanjay Singhji. I don't want to say the same again and again. Almost everything has been talked about. Whatever our President had given – not this one, the first promise on the Republic Day – about the Central law, that was his Address. This Address was given to him by the Government. This is the normal ceremonial speech. He has to speak whatever is written.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No reference to Governor of Kerala. That is expunged.

---

* Not recorded.
**Expunged as ordered by the Chair.

SHRI ABDUL WAHAB: Okay. So, these are the things happening in this country.

श्री नरेश अग्रवालः श्रीमन्, गवर्नर पर तो बहस हो चुकी है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; he mentioned about the action of the Governor in Kerala.

श्री नरेश अग्रवालः श्रीमन्, गवर्नर पर तो इस सदन में बहस हो चुकी है। गवर्नर अनपार्लियामेंटरी नहीं है। गवर्नर पर तो पूरे दिन सदन में बहस हुई है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He was mentioning about the action of the Governor.

श्री नरेश अग्रवालः आज ही पश्चिमी बंगाल के गवर्नर पर बहस हुई, कल भी हुई और आज भी हुई है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not the issue.

श्री नरेश अग्रवालः अगर इन्होंने केरल गवर्नर कह दिया, तो क्या गलत कह दिया। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He was mentioning about the action of the Governor and criticizing the action of the Governor in the Assembly.

SHRI NARESH AGRAWAL: It is my right. ...(*Interruptions*)... हम किसलिए आए हैं? हम गवर्नर के लिए ताली बजाने के लिए थोड़े ही आए हैं। ..**(व्यवधान)**...

SHRI ABDUL WAHAB: I was praising him. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He can criticise the Government, not the Governor. ...(*Interruptions*)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): Sir, he was praising the Governor. ...(*Interruptions*)...

SHRI ABDUL WAHAB: * So, I am praising. ...(*Interruptions*)... It was not happening in the case of our hon. President. ...(*Interruptions*)... Sir, you had given me some minutes. I am not speaking much. I want to give my spare time to Mr. Sanjay Singh. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Sanjeev Kumar can speak for two minutes. You gave the name only now.

श्री संजीव कुमारः महोदय, झारखंड को tribal homeland कहा जाता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह जिक्र किया गया था कि जिस-जिस राज्य में ट्राइबल क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, वहां पर म्यूज़ियम बनाया जाएगा और झारखंड में भी एक म्यूज़ियम बनाने की बात राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कही गयी है। महोदय, झारखंड में सब से पहले

*Expunged as ordered by the Chair.

क्रांतिकारी तिलका मांझी हुए थे, जिन्होंने 1700 के दशक में उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी के कलेक्टर को तीर मारा था और उन्हें भागलपुर में जिस जगह फांसी दी गयी थी, उसे तिलका मांझी चौक कहा जाता है। उसके बाद 1800 के दशक में सीधो कानो, चांद भैरव ने आंदोलन किया था, जिसमें 25 हजार के आसपास संथाल ट्राइबल मरे थे। महोदय, मैं बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूं कि सीधो कानो और चांद भैरव का किसी भी किताब में कोई जिक्र नहीं है। यहा तक कि पार्लियामेंट के किसी भी कोने में उनकी कोई तस्वीर नहीं है। इसलिए यदि प्रेजिडेंट साहब के भाषण में इस बात का जिक्र आया है, तो उन लोगों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह होगी कि उनके विषय में एनसीईआरटी और दूसरी किताबों में पढ़ाया जाए और पार्लियामेंट में उचित जगह पर उनकी तस्वीर लगायी जाए।

महोदय, यह बात भी कही गयी है कि झारखंड और देश में नक्सल problem घट रही है। महोदय, नक्सल problem के नाम पर क्या किया गया है, इसका उल्लेख मैं सदन में कर चुका हूं। बकोरिया में 15 निर्दोष आदिवासी लोगों को गोली मार दी गयी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बात के लिए सरकार को फटकार लगायी है। अभी उस केस की जांच चल रही है। मैंने यह बात उठायी थी और इसके चलते वहां की विधान सभा एक दिन भी नहीं चली। महोदय, यह पहला मौका होगा कि विधान सभा में बजट बिना बहस के पारित कर लिया गया। महोदय, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, देश में यह पहली घटना होगी कि नेता प्रतिपक्ष को मुख्य मंत्री ने हाउस के फ्लोर पर गंदी गाली दी। यह बात मैंने सदन को बतायी थी और इस बात को सब को बिना हिचक के criticize करना चाहिए। महोदय, यह बात रिकॉर्ड में है। यह बात सब को शर्मसार करती है यदि सदन में नेता, प्रतिपक्ष को मुख्य मंत्री गाली दे।

महोदय, भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। झारखंड के दो पूर्व मुख्य सचिवों को भ्रष्टाचार के आरोप में कानून सज़ा दे चुका है और तीसरा पाइपलाइन में है। अभी प्रधान मंत्री जी के ऑफिस से चिट्ठी गयी है और हो सकता है कि एक-दो दिन में उन्हें निकाला जाए। महोदय, डीजीपी के खिलाफ झूठी मुठभेड़ के चलते मुकदमा चलने की बात चल रही है।

महोदय, यहां बताया गया कि किसानों की इनकम दोगुनी की जाएगी। महोदय, झारखंड में लोग भूख से मर रहे हैं। महोदय, झारखंड के एक नेता बोल रहे थे कि वहां तल-तलकर पकौड़ा खिलाया जा रहा है, लेकिन यह बात नहीं बतायी गयी कि वहां लोग भूख से मर रहे हैं। महोदय, झारखंड में कभी भी किसान आत्महत्या नहीं करता था, अब वहा भी वह आत्महत्या कर रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's okay. Now, sit down. Shri Anand Sharma.

श्री संजीव कुमारः ठीक है, मैं समाप्त करता हूं।

श्री आनन्द शर्माः माननीय उपसभापति महोदय, मान्यवर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में श्री अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मुझे बोलने का समय देने के लिए आप के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद यह माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सबसे नीरस अभिभाषण है। इस अभिभाषण में, उन शब्दों का प्रयोग है,

[श्री आनन्द शर्मा]

जोकि सरकार की और प्रधान मंत्री जी की कार्यशैली बन चुकी है। इस अभिभाषण में नए वायदों की बात है, पुराने वायदों का कोई जिक्र नही है। इसमें सरकार के साढ़े तीन साल का भी कोई हिसाब-किताब नहीं है। हमने इस अभिभाषण में इस तरह की बात देखी है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की सोच यह है कि जो 2014 में कहा था, भारत के लोगों को आश्वासन दिए थे, वायदे किए थे, वे सब पूरे हो गए। यह अभिभाषण जमीनी हकीकत को नकारता है। यदि आप इस अभिभाषण को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके शब्द अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मैंने इसके लिए 'नीरस' शब्द का प्रयोग किया है। यदि आप पुराने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पढ़ेंगे, तो पाएंगे कि सरकार की तरफ से ऐसा भाषण दिया जाता है, जिसके शब्द अच्छे होते हैं और वह भाषण सुनने में भी अच्छा लगता है। इसके साथ ही साथ यह अभिभाषण प्रेरणाजनक भी होता है। यह भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है और इसमें देश के युवाओं व बच्चों के विषय में बात की जाती है, लेकिन इस अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें पुरानी योजनाओं की वही पुरानी तस्वीर है, जो योजनाएं प्रधान मंत्री जी ने आरम्भ की थीं, वे योजनाएं कहां हैं और कब पूरी होंगी, इसका कोई जिक्र नहीं है। हमें 2022 के सपने को देखकर कुछ हैरानी होती है। अभी तक तो संविधान के अनुसार सरकारें पांच सालों के लिए ही चुनकर आती हैं। आपको पांच की गिनती में कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? सन् 2019 में भारत के लोग तय करेंगे कि 2022 में हिसाब कौन देगा? आपने पहले से ही तय कर लिया कि 2022 में आपको ही हिसाब देना है, शायद आपकी यह इच्छा पूरी न हो। ...**(व्यवधान)**.... अभिभाषण को पढ़कर लगता है कि हम वायदे करेंगे और हमने जो वायदे किए थे, आप उनके बारे में मत पूछो कि उनका क्या हुआ। आप हमसे हिसाब मत मांगो, सिर्फ सुनते रहो, क्योंकि अच्छे दिन आ गए हैं और नए भारत के निर्माण की आधारशिला रख दी है। अगर यही अच्छे दिन हैं कि देश का किसान खुश है, जो त्राहि-त्राहि कर रहा है, देश का नौजवान खुश है, जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री और सरकार की सलाह है, आज भी कहा गया है कि हर नौजवान रोजगार नहीं चाहता, बल्कि आज का नौजवान स्टार्ट-अप चाहता है। वह खुद ही रोजगार पैदा करेगा, तो यही दो करोड़ की बात थी, अब तक तो सात करोड़ का हिसाब था। आज देश की सुरक्षा के क्या हालात हैं, इस अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। यह पहला अभिभाषण है, जिसमें भारत की विदेश नीति, कूट नीति के ऊपर एक शब्द भी नहीं है। इसमें केवल एक ही बात कही गई है, जो सोच और मानसिकता बन चुकी है कि पहली बार भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ी है। यह कैसे बढ़ी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जज जीत कर आ गए। यह भारत के लिए खुशी की बात है कि वे जीत कर आ गए। यह कहा गया कि बड़ी कशमकश के बाद पूरे देश को मुबारक है, लेकिन यह नहीं बताया कि वे री-इलेक्ट हुए हैं। उनके लिए बिना झगड़े के, बिना कशमकश के सभी देशों ने समर्थन दिया था। जब प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी थे, वही जज चुनकर गए थे, यह नहीं मालूम। इस अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है कि आज हमारे देश की सीमाओं पर क्या परिस्थितियां हैं। वे इस अभिभाषण के जरिए देश को बताते कि चीन के साथ क्या बात हुई, डोकलाम की जो समस्या या चुनौती थी, वह सुधर गई। वहां इसके बाद भी क्यों परमानेन्ट स्ट्रक्चर बना दिए गए? इस अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। नेपाल के साथ क्या हमारे संबंध ठीक हैं? देश चारों तरफ से घिर रहा है, मालदीव में क्या हो रहा है? इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है, सुरक्षित है, तो क्या माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि सरकार भारत

के लोगों के विवेक को, उनकी समझ को, वास्तविकता को पहचानने की उनकी क्षमता को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रही है। अभी अमित शाह जी ने पहला भाषण दिया था। उन्होंने अच्छा भाषण दिया, लंबा दिया। ...**(व्यवधान)**...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): अच्छा था।

श्री आनन्द शर्मा: क्या हमने बुराई की? आप क्यों ऐसे परेशान होते हैं? इन्होंने कई बातें कहीं। हमें बड़ा दुख लगा, जब सत्ताधारी दल के अध्यक्ष यह कह रहे थे कि आपको विरासत में क्या मिला? इस देश की तिजोरी खाली और गड्ढे में गिरा भारत मिला। यदि धन्यवाद प्रस्ताव में यह कहा जाए कि आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान में जो पार्टी 55 साल तक सरकार में रही, उसने क्या किया, तो मुझे हैरानी हुई कि ये किस देश की बात कर रहे हैं? हम एक ही देश में तो रहते हैं। क्या 2014 में किसी नये देश से आए थे? ऐसा नहीं है। इसी देश में उपलब्धियां हुई हैं और इसी देश ने चुनौतियों का सामना किया है। अच्छा होता कि इस मानसिकता को त्याग कर प्रधान मंत्री और आज की सरकार यह स्वीकार करे कि इनसे पहले के प्रधान मंत्रियों ने भी राष्ट्र निर्माण का काम किया है। ...**(व्यवधान)**... देश में इससे पहले भी उपलब्धियां हुई हैं। ...**(व्यवधान)**... उसको स्वीकार न करना, भारत के उन तमाम लोगों को, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और उसके बाद उसका निर्माण किया, जिन्होंने देश में महान उपलब्धियां अर्जित कीं, चाहे वे हमारे वैज्ञानिक हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, उनके लिए भी अच्छा होगा कि आप उन लोगों की उपलब्धियों का अपमान न करें, उसे स्वीकार करें। सरकार से इसी विनम्रता की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि यहां पर बातें कही गई हैं, इसलिए मैं आवश्यक समझता हूं, आपको बताता हूं कि इस देश में अच्छी संस्थाएँ बनीं, शिक्षा के संस्थान बने। यहां साइंस के, तकनीक के, परमाणु साइंस के, विद्या के, अंतिरक्ष विज्ञान के संस्थान बने। अगर मैं आईआईटीज़ अर्थात् Indian Institutes of Technologies के लिए कहूं तो आधुनिक भारत के निर्माता और स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक पंडित जवाहरलाल नेहरु, जिन्होंने 1951 में पहले आईआईटी की स्थापना की थी, यह उनकी सोच थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ...**(व्यवधान)**... जरा सुनें कि पंडित जवाहरलाल नेहरु के समय में पांच Indian Institutes of Technologies बन चुके थे। ...**(व्यवधान)**... देश में पंडित नेहरु के समय में यह हो गया था। ...**(व्यवधान)**... जैसा मैंने कहा, यह सबसे पहले 1951 में खड़गपुर में बना था। माननीय अमित शाह जी, क्योंकि आपने यह बात कही थी, उस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि आपका जन्म अक्तूबर, 1964 में हुआ था, पर जवाहरलाल नेहरु जी ने आपके अहमदाबाद में 1961 में आईआईएम बना दिया था। शायद यह भी बताना जरूरी होगा कि 1961 में, अभी हाल ही में 2008-09 तक हिंदुस्तान का पहला और एकमात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरु ने अहमदाबाद में बनाया था। इस देश में जिस पं. जवाहरलाल नेहरु का नाम, उनकी जन्म शताब्दी, उनके जन्म के 125वें साल का जिक्र करने में आज तकलीफ होती है, उन्होंने 1954 में Department of Atomic Energy बनाया था, जिसको हम Bhabha Atomic Research Centre कहते हैं, उसकी स्थापना पहले 1954 में हुई थी। उसको AEET कहा जाता था, यानी Atomic Energy Establishment Trombay. वह 1957 से है। उसको डॉ. होमी भाभा के नाम पर, 1967 में भाभा का नाम दिया गया। शायद जिस भारत में कुछ नहीं हुआ था, उसके लिए यह भी बताना जरूरी होगा कि जो स्पेस सैंटर बनाया गया था, वह स्पेस एप्लिकेशन सैंटर, अहमदाबाद में 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनवाया था। वह इंदिरा गाधी जी ने अहमदाबाद में 1966 में बनवाया।

[श्री आनन्द शर्मा]

क्या आज हम इंदिरा जी का नाम न लें? उनकी जन्म-शताब्दी आए, क्या उनका नाम न लें? अभिभाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तुलना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से करें, आपके नेता होंगे, आप करें, लेकिन इतिहास उसे स्वीकार नहीं करता, न ही यह देश स्वीकार कर सकता है। इंदिरा जी के सौ साल हुए, क्या हो रहा है? हम नहीं सोचते कि वाजपेयी जी के समय में ऐसा हो सकता था। उन्होंने तो 1971 में इंदिरा जी की प्रशंसा की थी, जो उनकी उपलब्धियां थीं, उनकी तारीफ की थी। यह देश सब का है, सबने मिल कर देश बनाया है। अगर यह सोच होगी कि देश के मालिक आप हैं, बाकी दूसरों का इस देश पर अधिकार नहीं है, देश को आजाद कराने वालों का अधिकार नहीं है, देश को बनाने वालों का अधिकार नहीं है, तो इससे बढ़ कर दुख की बात भारत के लिए नहीं हो सकती। आपने कहा कि आपको पिछले शासन ने विरासत में क्या दिया? मैंने तो अभी पंडित नेहरु जी का जिक्र किया, मैंने तो इंदिरा जी के समय का थोड़ा सा जिक्र किया, शायद आपको यह भी याद कराना होगा, क्योंकि आपने जिक्र किया, अच्छी बात है, करना चाहिए, भारत को परमाणु शक्ति बनाने की बुनियाद तो बता दी पंडित नेहरु जी की, लेकिन 1974 में पोखरण में पहली बार परमाणु विस्फोट करके इंदिरा गांधी जी ने दुनिया को संदेश दिया। उसके साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम रखा, आर्यभट्ट जो लांच हुआ, वह भी 1974 में हुआ। दोनों ही समय भारत की प्रधान मंत्री देश की महान नेता और देश की शहीद इंदिरा गांधी जी थीं। यूपीए के शासन काल में कांग्रेस से डा. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, देश में आठ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टैक्नोलॉजी बने। मेरे पास पूरी सूची है, पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए पूरी सूची भिजवा दूंगा, अगर आप चाहें तो पढ़ भी दूंगा। सात नए इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट बने, चार नए इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस बने, चंद्रायण 2008 में चंद्रमा ग्रह पर चला गया और मंगलयान को 2013 में हमने रवाना कर दिया। अब अगर कहीं यह सोच हो कि सारी उपलब्धियां 2014 का इंतजार कर रही थीं, तो आपकी सोच है, मगर देश में एक निरंतरता होती है। अगर आपके समय में अच्छा काम होगा, तो हमारे अंदर इतना बड़प्पन है कि हम उसे स्वीकार करेंगे कि आपने यह किया है, बधाई हो, देश को बधाई हो।

श्री नरेश अग्रवालः क्या अब तक नहीं हुआ?

श्री आनन्द शर्माः इसलिए जिस देश की इतनी उपलब्धियां हैं, उसके लिए यह सोचना कि कुछ नहीं हुआ, यह कहना कि कुछ नहीं हुआ, यह इतिहास का अपमान है, सभी संस्थाओं का अपमान है, सभी वैज्ञानिकों का अपमान है, देश का अपमान है। क्या आपको 2014 में कमजोर भारत मिला था, दिशाहीन हिंदुस्तान मिला था? मैंने आपको बताया कि कई उपलब्धियां हैं और यूपीए के दस साल के शासन में 7.9 प्रतिशत जीडीपी की दर थी। यह पुरानी सीरिज थी, यह नई सीरिज नहीं थी, नई सीरिज अगर लेते, तो निरंतर चार साल डबल डिजिट में जीडीपी की दर बढ़ती थी। जब विश्व में 2008 में वित्तीय संकट आया, तो विश्व ने उस समय भारत के प्रधान मंत्री से पूछा। मुझे याद है, जब अप्रैल, 2009 को जी-20 की लंदन में मीटिंग हुई, तो विश्व के नेताओं ने, जिसका पुष्टिकरण अभी अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति मि. बराक ओबामा करके गए हैं, सब विश्व के नेताओं ने जी-20 की आपात बैठक बुला कर के डा. मनमोहन सिंह जी से पूछा कि इस संकट के लिए हम सब को मिल क्या करना चाहिए? यह मैं नहीं कह रहा, यह उन देशों के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री कह रहे हैं और आप कहते हैं कि कुछ नहीं मिला। जिस

भारत को इन्होंने 2004 में ग्रहण किया था, उस हिन्दुस्तान की 480 बिलियन डॉलर की GDP थी। जब दुनिया के अन्दर पहली औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहा जाता है, उसको अपनी GDP को दोगुना करने में 12 वर्ष लग गए थे। दूसरी औद्योगिक क्रांति आई थी, जब अमेरिका के अन्दर mass production lines बनी थीं, 1940 के दशक में, तब अमेरिका को अपनी GDP को दोगुना करने में 12 साल लगे। अगर दुनिया में कोई पहला देश था, जिसने इतिहास में एक दशक के अन्दर, 10 साल के भीतर अपनी GDP को दोगुना किया, तो वह जापान है। दूसरा देश साउथ कोरिया बना। एक दशक में GDP को तिगुना किया चीन ने और अगर एक दशक के अन्दर किसी देश ने GDP को चार गुना किया, तो हिन्दुस्तान ने, भारत ने, यूपीए के शासन काल में। यह गड्ढे में पड़ा हुआ हिन्दुस्तान था! 2.3 ट्रिलियन डॉलर की economy हवा में नहीं बनी। यह मेहनत से बनी है। इसलिए कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आपके आने से पहले भारत की पहचान नहीं थी, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, देश दिशाहीन था, देश में निराशा थी, आशा की किरण नहीं थी। आप आशा की मशाल लेकर आए, वायदों की एक सुनामी ले कर आए, जो वायदे गलत साबित हुए। आज यही कारण है कि सवाल पूछे जा रहे हैं।

इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही। यह ऐतिहासिक सत्य है। अब आप उसको नहीं बदल सकते हैं, हालांकि काफी चीजें बदली जा रही हैं। नया इतिहास भी बनाया जा रहा है, जैसे 'नया इंडिया' बनेगा, नया इतिहास भी है। कई-कई नई बातें हमें सुनने को मिलती हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने यह काम भी किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस', 'International Yoga Day' मनवाया। अच्छी बात हुई। हमारे समय में भी भारत की तरफ से प्रस्ताव लाकर एक दिन एक International Day मनाया गया था। वह था महात्मा गांधी की जयंती, 2 अक्टूबर को 'International Day of Non-violence'. जून, 2007 में हमारी सरकार के समय unanimously संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे घोषित किया था। उसका ज़िक्र कभी नहीं आता। चूँकि योग की बात काफी होती है और मैंने इतिहास की बात की, कुछ तथ्यों की बात की, क्या महारथ है प्रधान मंत्री जी की और सरकार की कि देश के इतिहास का, देश के तथ्यों का, देश की विरासत का, देश की अर्थव्यवस्था का, सबका शीर्षासन करा दिया। ऐसी तस्वीर पेश की, जो बिल्कुल विपरीत है। अब अच्छा है, शीर्षासन करके क्या सही तस्वीर दिखी या नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपका भी और देश का भी। आपकी एक सोच रही, हम समझ सकते हैं। वंशवाद क्या होता है? अगर यह ज़िक्र है, एक परिवार, जो आजादी की लड़ाई से संघर्षरत रहा, चार पीढ़ियों का संघर्ष और कुर्बानी, बलिदान। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय अंग्रेजों की जेल में रहे थे, 14 वर्ष। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए थे। हमको तो नाज़ है उनकी कुर्बानी, उनके संघर्ष और उनके बलिदान पर। भारत को उस पर फ़ख्र है। आपको नहीं हो, पर यह देश और यह इतिहास, सम्मान से हमेशा उसको याद रखेगा।

यह सही है कि राजनीति में आलोचना होती है, विरोध होता है, वाद-विवाद होता है, संवाद होता है। अब संवाद नहीं होता। वाद-विवाद, वह भी स्वीकार्य है, आलोचना भी स्वीकार्य है, पर प्रजातंत्र में, माननीय उपसभापति महोदय, पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों अनिवार्य हैं। हम देश में क्या सुन रहे हैं? कहा जा रहा है– कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे भाई! कांग्रेस मुक्त तो आप गुजरात

[श्री आनन्द शर्मा]

को भी नहीं बना सके, तो भारत को कैसे बनाओगे? यह कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता। यह जो मानसिकता है, यह अस्वस्थ मानसिकता है, जो चिंता की बात है। मेरा आग्रह होगा कि आप इस मानसिकता पर थोड़ा पुनर्विचार करें, क्योंकि यह होने वाला नहीं है। यह 133 साल पुराना संगठन है, जिसका बड़ा गौरवमय इतिहास रहा है। इधर भी करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जो संघर्ष भी करना जानते हैं और जवाब भी देना जानते हैं। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अहमद भाई ने बताया कि पहले क्या हुआ, पर मैं उसमें नहीं जाता कि कितनी सीटें कहां आईं। उन्होंने कहा तो ज़रूर मैं अनुमोदन करता हूं, लेकिन जो यूपी, बिहार वाले उप-चुनाव या bypolls रह गए हैं, ज़रा वे भी करवा लीजिए, ताकि थोड़ी बात तो आगे बढ़े।

महोदय, मैं एक चीज़ कहूंगा, हम आपसे, आपकी सरकार से या माननीय प्रधान मंत्री जी से कोई प्रमाणपत्र नहीं चाहते हैं। पुरानी सरकारों को, पुराने प्रधान मंत्रियों को या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को न तो किसी प्रमाणपत्र की जरूरत है और न ही हमने मांगा है, लेकिन आज मैं आपसे एक चीज़ कहूंगा कि हमारे अंदर वह संस्कृति है, संस्कार हैं और सोच है कि हम कभी यह बात नहीं कहेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत बनाओ। आप भी इसी देश के संगठन हैं, आप भी यहीं की विचारधारा के हैं। आपका और हमारा वैचारिक विरोध है और वह रहेगा, वह निरंतर है, किन्तु यह सोच सही नहीं है। यह सोच कि दूसरे राजनैतिक दल की सोच को या उसको हटा दो, यह प्रजातांत्रिक सोच नहीं है। यह सोच प्रजातंत्र पर सीधी चोट पहुंचाती है, आघात पहुंचाती है और देश की जनता यह होने नहीं देगी। यह बात सिर्फ हमारे लिए नहीं है, तमाम विपक्षी दलों के लिए है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि तीस के तीस राज्यों में आपकी सरकार बने, पूरे देश में आपकी सरकार बने, बाकी कोई न हो और आप सबको कहें कि यह हमारा नया मॉडल है, नया इंडिया है, न्यू डेमोक्रेसी है। यह नहीं होगा। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं।

मैंने कई बातें कह दी हैं, पर जो जरूरी बातें हैं, उनको कुछ शब्दों में कहूंगा। आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर कहा कि हमारी बड़ी प्रभावशाली आर्थिक प्रगति हो रही है, लेकिन वह दिखता नहीं है, क्योंकि सारे जो पैरामीटर्स हैं, वे गिरे पड़े हैं। जहां हमारे समय में निवेश की दर 34 प्रतिशत थी, आज वह 26.9 प्रतिशत है, यानी 7 प्रतिशत गिर गई है। उद्योग जो कर्जा लेता है, वह कोई एक दो साल का नहीं, 63 साल का सबसे कम कर्जा है। नये उद्योग नहीं लग रहे हैं, निर्माण नहीं हो रहा है, मेन्युफेक्चरिंग नहीं हो रही है। 'Make in India' के advertisement पर ज्यादा खर्चा हो रहा है। रक्षा मंत्री बैठी हुई हैं। FDI की नीति आई, जो हमारे समय में भी थी, वह बदल दी गई। कहा गया कि रक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी निवेश आएगा। यह बहुत संवेदनशील विषय होता है हमारी FDI नीति में Cabinet Committee on Security के लिए कहा गया कि वह उसको एप्रूव करेगी। आगे कहा गया high end technology आएगी, उसका देश में assimilation होगा, मिश्रण होगा और देश में ही निर्माण होगा। यहां यह जिक्र करना जरूरी है, जहां आप पूर्ण सुरक्षा की तैयारी या defence preparedness की बात करते हैं, लेकिन मैं यह देख कर चौंक गया कि आपके शासनकाल के अंदर FDI in Defence 1 करोड़ 13 लाख है। ऐसी कई चीज़ें और हैं, लेकिन चाहे निर्यात की बात हो या अर्थव्यवस्था की बात हो, मैं तो यही कहूंगा कि हम जहां 34 प्रतिशत पर निवेश दर छोड़ कर गए थे, जहां 320 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट छोड़ कर गए थे, आप अपना कार्यकाल पूरा होने तक अगर भारत को वहां तक भी पहुंचा देंगे, तो इस

देश पर बड़ी कृपा होगी। उपसभापति महोदय, जहां तक रक्षा की बात है, अभिभाषण में कहा गया कि private sector की participation है और उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपने कहा कि आपकी सरकार में पारदर्शिता है, जो नहीं है। आपने कहा कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम पर आरोप लगाए। मैं खुद सोच रहा था कि मैं ठीक सुन रहा हूं या नहीं, कभी 6 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की बात आपकी तरफ से कही गई, फिर दूसरी बार 12 लाख करोड़ रुपए का भी घोटाला हो गया। अब इन आरोपों की सवारी कर के आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन वह हमेशा नहीं रह सकता, क्योंकि आरोप में सत्यता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला दिखाया, उसे तो आपने पद्मभूषण, बैंकिंग बोर्ड चेयरमैन और न जाने क्या-क्या नहीं दिया।

खेल जगत से आपका भी संबंध रहा है। अध्यक्ष जी ने प्रस्तावना में कहा और खेल की बात कही, 'खेलो इंडिया' की बात कही। आपका भी क्रिकेट के खेल से संबंध है। हम भी क्रिकेट खेलते थे। आपने तो क्रिकेट का भी हैड उन्हीं को बना दिया, क्योंकि उनके स्टेटमेंट से आपको फायदा हुआ था। बड़ा फायदा हुआ था, लेकिन अदालत ने बता दिया कि कितना सच था और कितना गलत।

महोदय, आज एक सवाल है और वह Rafale deal का या Rafale jet की खरीद का। वर्ष 2005 से हमारी बातचीत चल रही थी और इस संबंध में global tender जारी किया गया था। सात साल लग गए थे। तीन कंपनियों के तीन जहाज shortlist हुए थे। उनमें एक Rafale jet fighter था, दूसरा Eurofighter Typhoon और तीसरा, जो Swedan की Saab कंपनी है उसका Gripen जहाज था। ये तीन shortlist हुए थे। अमरीका का जहाज बाहर हो गया था और रूस का जहाज भी बाहर हो गया था। मैं याददाश्त के आधार पर ये बाते कह रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां पारदर्शिता नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा से समझौता हुआ है। आप कहते हैं कि कोई scam नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और मैं इस संबंध में कागज रखूंगा कि Rafale jet सबसे बड़ा scam है। मैं संसद में लम्बे समय से रहा हूं। मैंने बिना जिम्मेदारी के कोई बात नहीं कही। मैंने कभी आरोप की राजनीति में विश्वास नहीं किया, आपने भले ही किया हो। प्रश्न यह है कि हमारे समय में 126 fighter jet खरीदने के लिए global tender किया गया था। वर्ष 2012 में सारी बातचीत तय हो गई थी, सिर्फ प्राइस की बात रह गई थी। उस समय यह भी तय हो गया था कि 18 fighter jet finished state में आएंगे, यानी बने बनाए आएंगे और 108 भारत में बनेंगे तथा भारत में H.A.L. यानी Hindustan Aeronautics Limited उन्हें बनाएगा। वह कंपनी public sector की है। इस बारे में सभी जानते हैं। उसमें transfer of technology होगी। पूरी technology, H.A.L. Defence PSU को मिलेगी और उसके साथ 36 हजार करोड़ रुपए का offset भी HAL को मिलेगा, यह करार था। आपको अच्छा नहीं लगा, वर्ष 2015 में बात बदली गई। यह कहना जरूरी होगा कि हमने जो तय किया था, उसे बदल दिया गया। एक Rafale jet की कीमत 526 करोड़ रुपए तय हुई थी, जिसे Dassault Company बनाती है। इस संबंध में H.A.L. और Dassault में 108 जहाज बनाने और offset के agreement पर हस्ताक्षर हो गए थे। अब उसके बाद आपकी सरकार ने यह सोचा कि यह सही नहीं है। दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को देश के प्रधान मंत्री जी ने पेरिस और फ्रांस जाने का तय किया। उस समय के विदेश सचिव ने एक प्रेस कांफ्रेस की और जब उनसे पूछा गया कि क्या Rafale jet का समझौता या agreement

[श्री आनन्द शर्मा]

फाइनल होगा, तो जवाब मिला कि भारत के प्रधान मंत्री जब बाहर जाते हैं, तो रक्षा सौदों की खरीद-फरोख्त के कोई एग्रीमेंट नहीं करते। The Prime Minister of India does not go on State visit to negotiate defence deals or to sign defence agreements. सारे देश ने कहा कि ठीक बात है। 10 अप्रैल को उसको बदल दिया गया। प्रधान मंत्री जी ने, सारे देश ने देखा, कोई बुरी बात नहीं है, मेज़बान अपना देश घुमाते हैं, उनकी जो नदी है, अच्छी रिवर है, Seine river, उसमें उनको किश्ती में लेकर गये। उसके बाद उन्होंने वहां तुरन्त घोषणा कर दी कि हम 36 जहाज खरीदेंगे। पुराना सौदा गया, पुरानी बात गयी, Make in India हो गया, transfer of technology हो गयी। इसमें क्या कीमत तय हुई- 1,570 करोड़। 526 करोड़ से 1,570 करोड़! यह 2015 का है। HAL का क्या हुआ, जिसने 108 जहाज बनाने थे- HAL बाहर और कहा कि हम निजी क्षेत्र को लायेंगे। जरूर लायें, but not at the cost of the nation and the defence PSU, परन्तु आप लाये। जो निजी क्षेत्र आप लाये हैं, वही उद्योगपति प्रधान मंत्री के साथ उस दौरे में गये थे। वे वही थे और वे जो 108 HAL को मिलने थे, वे उनके पास गये। HAL को जो 36,000 करोड़ का offset मिलना था, वह भी उस निजी कम्पनी को दिया गया।

एक और बात है कि 2017 में, नवम्बर महीने में, क़तर एक छोटा मुल्क है, क़तर ने 12 राफेल जेट खरीदे और एक जेट की कीमत 694 दी और हमने 2015 में 1,570 करोड़ दिये! तो इस पर सवाल न करें, तो क्या करें? क्या देश इस पर चुप रहेगा? यह सवाल तो उठेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। परन्तु देश को यह कहा गया कि emergency purchase की वजह से हुआ। ...**(व्यवधान)**... देश को यह कहा गया कि emergency purchase थी, जरूरत थी, इसलिए यह फैसला माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया कि 126 जहाजों की बात ठीक नहीं थी, 108 जहाज HAL को नहीं बनाने थे, 526 करोड़ कीमत ठीक नहीं थी, 1,570 करोड़ में सीधा 36 जहाज खरीदो और बाकी प्राइवेट सेक्टर अलग से बनाये। देश को यह कहा गया। अगर emergency purchase थी, तो defence acquisition नियमों का उल्लंघन क्यों किया? The Cabinet Committee on Security से पहले पुराना जो टेन्डर था, उसको रद्द करने की अनुमति होनी चाहिए थी। माननीय प्रधान मंत्री जी, आपके पेरिस से आने के बाद, *post-facto* approval Cabinet Committee on Security की हुई है। इसमें मैं कोई गलत बात कहूँ, तो मुझे कृपया बतायें कि मैं गलत कह रहा हूँ। तो आप रक्षा मंत्री को साथ न ले जायें, CCS का अप्रूवल न लें, defence acquisition rule बदल दें, तीन गुना कीमत बढ़ जाये ...**(समय की घंटी)**... HAL को बाहर कर दें, तो ये सवाल उठेंगे। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. ...(*Interruptions*)... Your time is over. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप कहते हैं ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः अगर आप कहते हैं कि पारदर्शिता हो, तो इस सवाल का जवाब हम चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anand Sharmaji, please conclude. ...(*Interruptions*)... Your time is over. ...(*Interruptions*)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, we still have time. ...(*Interruptions*)... There are 45 minutes. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Look at the board. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I will complete my speech. ...(*Interruptions*)...

एक माननीय सदस्यः सर, अभी 45 मिनट्स हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री आनन्द शर्माः सर, अच्छी बात हो रही है। कभी कहीं तो पूछने दीजिए! पहले तो आप यह तय कर दें कि अभी जब हम बोल रहे हैं, वह राज्य सभा टीवी में चल रहा है या कोई और कार्यक्रम दिखा रहे हैं? **...(व्यवधान)...** चल रहा है, तो ठीक है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Your time is over. That is my problem. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: My time is not over. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः प्रधान मंत्री जी भी कहेंगे, अभी तो हमें जीना है। अभी कहां जायेंगे? **...(व्यवधान)...** अभी तो मेरा टाइम है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. The time allotted to you. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः सर, मैं 2022 तक मेम्बर हूँ। **...(व्यवधान)...** अभी नहीं। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am saying, the time allotted to you for this discussion. That is all. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः आपने मंत्री जी को चार गुना टाइम दे दिया। मेरे साथ अन्याय मत करिए, टाइम बढ़ा दीजिए।

सर, आज मुझे कहना होगा कि जो भ्रष्टाचार की बात है, तो क्या भ्रष्टाचार के लिए दो कानून हैं? क्या भ्रष्टाचार की दो परिभाषाएँ हैं? एक परिभाषा वह, जब कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना हो और एक दूसरी परिभाषा आपके लिए! एक कानून कांग्रेस के लोगों के लिए, कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों के लिए, कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्रियों के लिए और एक कानून आपके मुख्य मंत्रियों के लिए, आपकी सरकारों के लिए! आज विपक्ष के मुख्य मंत्रियों पर, विपक्ष की सरकारों पर एक दुर्भावना से निशाना बनाया जा रहा है। आपके यहां देश में शासन तंत्र का और प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, एक बदले की भावना से काम हो रहे हैं, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। देश में यह नहीं होना चाहिए। यह टकराव अच्छा नहीं है। अगर यह कहा जाए कि हमारे मुख्य मंत्रियों ने जमीनें दीं, उन पर एफआईआर कर दो, तो आपके मुख्य मंत्रियों ने खानें दे दीं, लाखों एकड़ जमीनें दे दीं, छत्तीसगढ़ दे दिया। माननीय मुख्य मंत्री निर्णय करते हैं, निर्णय किए

[श्री आनन्द शर्मा]

जाते हैं, आपने भी निर्णय किए होंगे, माननीय प्रधान मंत्री जी, आप 12 साल मुख्य मंत्री रहे। मुझे बताया गया कि 6 लाख एकड़ जमीन दी गई, तो फिर उसकी भी जांच करा लीजिए, फिर यह क्यों होता है कि हमारे मुख्य मंत्री ने दे दी, लेकिन आपका छत्तीसगढ़ भी ठीक है, मध्य प्रदेश भी ठीक है, आपके राजस्थान की खानें दे दीं, वह भी ठीक है, आपका गुजरात भी ठीक है। ये दो निज़ाम कैसे होंगे? दो कानून कैसे होंगे? दो परिभाषाएं कैसे होंगी? न्याय होना चाहिए। आप सत्ता में हैं, आप अभिभावक हैं, आप पूरे देश के प्रधान मंत्री हैं, आपको देश को न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

श्री आनन्द शर्माः आपको देश को न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए, बदले की भावना से अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करना, प्रताड़ित करना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस मानसिकता को त्यागें। आज इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है, भय का वातावरण है, आतंक का वातावरण है, टेलीफोन टैप कर दो, सीबीआई, ईडी को लगा दो, हर किसी को धमकी दो, यह क्या प्रजातंत्र है? ...**(समय की घंटी)**... क्या यह आपका नया भारत है? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anand Sharmaji, please. The Congress Party's time is over. Please, please, please. ..(*Interruptions*)..

श्री आनन्द शर्माः जब हमारे बारे में कहा जाता है, क्योंकि पहले से जवाहरलाल नेहरू ने तो प्रजातंत्र नहीं दिया और उस विचारधारा के जो लोग वारिस हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और अंग्रेजों का साथ दिया, आज वे हमें राष्ट्रभक्ति की बात बता रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... यह ऐतिहासिक सत्य है। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please, please. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः महोदय, मुझे एक और प्रश्न करना है और वह मैं आपके माध्यम से प्रश्न करूंगा। ...**(व्यवधान)**... ठीक है, यह इतिहास का एक सत्य है। मैंने तो योगा के बारे में कहा, मैंने तो उसको लाइटर वे में कहा कि सब लोग करें। माननीय प्रधान मंत्री जी तो नहीं थे, थोड़ा-बहुत योगा मैं भी करता था, थोड़ा सीखा भी था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से मेरा कोई विरोध नहीं है, यह अच्छा काम है, पर आपके आने से पहले मैंने यही कहा था कि इतिहास का, तथ्यों का, जमीनी हकीकत का शीर्षासन बंद करा दीजिए, सही काम हो, आपने जो वायदे किए थे, उनके बारे में बता दें, जो नहीं हुए, उनके बारे में बता दें कि वे क्यों नहीं हुए? देश में ये नए सपने और आरोप बंद हों। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now you conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः अगर आप चाहते हैं ...**(व्यवधान)**... अभी हमारा समय है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you can stop. Anand Sharmaji, now you conclude. ...(*Interruptions*)... Please stop. ...(*Interruptions*)... You need not repeat.

...(*Interruptions*)... Please, ...(*Interruptions*)... Anand Sharmaji, please conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः सर, आप मुझे conclude करने का समय भी देंगे न?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please stop. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः ऐसे कैसे?...**(व्यवधान)**... ऐसे कैसे हो सकता है? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anand Sharmaji, whatever you have spoken in the House, the hon. Prime Minister has heard it in his office. Therefore, you need not repeat it. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः सर, मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ कि मुझे भी आपके संरक्षण की जरूरत है। हम तो प्रतिपक्ष के हैं, खूब सुनते हैं, यही तो एक समय है, जब हम अपने प्रश्न कर लें, वरना कहा? न तो टेलीविजन हमको दिखाता है, न अखबार छापता है, हालात खराब हैं। हजारों करोड़ के विज्ञापन इनके पास हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ सुनते रहते हैं। हम क्या करेंगे, किससे आग्रह करेंगे? यह सबसे बड़ा मंदिर है। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयलः सर, इसके बाद हमें बजट पर भी चर्चा शुरू करनी है।...**(व्यवधान)**... यह कोई तरीका नहीं हुआ।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anand Sharmaji, please conclude. ...(*Interruptions*)... Anand Sharmaji, please conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः सर, मुझे दो चीजें कहनी है। मुझे तो इतना नहीं, जितना कि कई साथियों ने अच्छी-अच्छी शेरो-शायरी की, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि याद रखिए सम्मान के साथ उनको, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, राष्ट्र की उपलब्धियों का सम्मान कीजिए, अपने से पूर्व सरकारों का अपमान मत करें, पहली बार भारत की पहचान दुनिया में नहीं हुई, यह सोच गलत है। आज जो सवाल आपसे है, हालांकि इस बात को पहले कह दिया गया है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है कि–

'हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती।' ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः बस हो गया। ...**(व्यवधान)**... बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्माः अब मेरा अंतिम प्रश्न है और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अपनी बात को विराम देने से पहले कहना चाहता हूं कि–

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

'न इधर उधर की बात कर, बता लुटा क्यूं काफिला,
हमें राहजनों से गरज़ नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।'

धन्यवाद।

4.00 P.M.

श्री सभापतिः आनन्द शर्मा जी, धन्यवाद। Now, hon. Prime Minister will reply to the debate.

प्रधान मंत्री (श्री नरेंद्र मोदी): आदरणीय सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा इस सदन में हुई है और करीब 38 माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां रखे। अपनी मेडन स्पीच के साथ, श्री अमितभाई शाह ने यह प्रस्ताव सदन में रखा था, जिसका विनय पी. सहस्त्रबुद्धे जी ने समर्थन किया। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद जी, डी.पी. त्रिपाठी जी, प्रमोद तिवारी जी, सरदार बलविंदर सिंह भुंडर जी, नरेश अग्रवाल जी, नवनीतकृष्णन जी, दिलीप कुमार तिर्की जी, संजय राउत जी, आनन्द शर्मा जी, देरेक ओब्राईन जी, डी. राजा जी, संजय सिंह जी, सुखेन्दु शेखर राय जी, टी.के. रंगराजन जी, टी.जी. वेंकटेश जी सहित अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे। चाहे वह रोज़गार का मामला हो, भ्रष्टाचार का हो, किसानों की आमदनी की बात हो, विदेश नीति का सवाल हो, सुरक्षा व्यवस्था का सवाल हो, 'आयुष्मान भारत योजना' हो – ऐसे अनेक विषयों पर सभी ने अपने विचार सदन में रखे हैं। गुलाम नबी जी को तो मैंने यहीं बैठकर सुना था, बाकी माननीय सदस्यों को अपने कमरे में बैठकर सुना, इस बहाने मुझे उनकी body language देखने का अवसर भी मिला। जब वे वंशवाद पर चर्चा कर रहे थे और एक परिवार को बचाने के लिए काफी कुछ कह रहे थे, उस समय उनकी मासूमियत अच्छी लग रही थी। अभी मैं आनन्द शर्मा जी को भी सुन रहा था। गुलाम नबी जी से लेकर आनन्द शर्मा जी तक ज्यादातर माननीय सदस्य अपनी पुरानी सरकार की बातें बताने का मौका ले रहे थे। बाहर तो कोई सुनता नहीं है, इसलिए यहां तो कहना ही पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... खैर, कांग्रेस पार्टी या किस राजनैतिक पार्टी को क्या करना चाहिए, उस पर मुझे कुछ कहने का हक नहीं बनता और न मुझे कुछ कहना है। आपने यहां 'आयुष्मान भारत योजना' की चर्चा की, लेकिन उदाहरण दिया अमेरिका और ब्रिटेन का – अमेरिका के मॉडल, ब्रिटेन के मॉडल और भारत की सामाजिक स्थिति में ज़मीन-आसमान का अंतर है। कोई चीज़ वहां सफल हो, जरूरी नहीं कि वह हमारे यहां भी सफल हो। कुछ चीज़ें वहां विफल हो सकती हैं लेकिन हमारे यहां भी बेकार हों – ऐसा तर्क ठीक नहीं है। हमें अपने देश की दृष्टि से सोचना चाहिए। यह इसलिए होता है क्योंकि उनका करीब 50-55 साल सत्ता में रहना और फिर ज़मीन से कट जाना – ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। उसके कारण मन में इस प्रकार का विचार आना भी बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि इनमें से कोई इस बात से असहमत होगा कि हमारे देश में आरोग्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, it does not mean कि गुलाम नबी जी जब हेल्थ मिनिस्टर थे, तब कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ तो किया ही होगा, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए हम चर्चा की इस बात को भी समझें कि देश की आशा-अपेक्षाओं के अनुरूप हम कुछ बातों को कैसे कर सकते हैं।

अब यह ठीक है कि हम "आयुष्मान भारत योजना" लेकर आए हैं, हो सकता है उसमें कमियां हों, लेकिन आखिरकार यह योजना देश के लिए है, किसी दल के लिए तो है नहीं। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के मित्र भी एक टास्क फोर्स बनाएँ, और दलों के लोग भी अपनी-अपनी टास्क फोर्स बनाएँ और "आयुष्मान भारत योजना" की स्टडी करें। अगर उसमें कुछ कमियां हैं, तो मैं खुद कुछ समय दूँगा। उसका अल्टिमेट उद्देश्य क्या है? उसका अल्टिमेट उद्देश्य है, देश में गरीब

और निम्न-मध्यम वर्ग का परिवार। अगर बीमारी उसके घर में आती है, तो जो कुछ भी उसने किया-कराया है, वह सब ज़ीरो पर आकर अटक जाता है, नेगेटिव चला जाता है। कभी उसको सूदखोरों से ब्याज पर पैसे लेकर उपचार कराना पड़ता है। कभी वह सोचता है कि बेटों को कर्ज में डुबाना नहीं है, बीमारी झेल लो, जिन्दगी कम हो जाए, तो हो जाए। यह psyche बनी हुई है। किसने किया, किसने नहीं किया, 70 सालों में क्यों नहीं हुआ, ये सारे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन मेरी चर्चा का विषय वह नहीं है। क्या हमें ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सरकार जो सोचती है, आप जैसी हमारी सोच नहीं है कि भगवान ने सब कुछ हमें ही दिया है। हम मानते हैं कि यहां सदन में हमसे भी कई गुना विद्वान और अनुभवी लोग हैं। उनकी विद्वता, उनका अनुभव हमारे सामने है। यहां के बाहर भी इस देश में बहुत विद्वान और अनुभवी लोग हैं। हम मिल-बैठकर यह सोचें कि क्या हम "आयुष्मान भारत योजना" को देश के 40-50 करोड़ लोगों तक पहुँचाकर उनमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक विश्वास पैदा कर सकते हैं? यह एक इंश्योरेंस स्कीम है। हम जानते हैं कि इंश्योरेंस में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसलिए बजट के प्रोविज़न वगैरह की चर्चा करके अटकने की आवश्यकता नहीं है, उस पहलू से हम भली-भांति परिचित हैं, लेकिन देश के गरीब को इसका लाभ मिले, मैं मानता हूँ कि यहां किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हां, योजना लागू करने के बाद कुछ कमियां आई हों और उन पर ध्यान नहीं गया हो और तब आलोचना होती है, तो वह ठीक है। यह अभी सुझाव के पीरियड में है। अभी एक योजना का प्राथमिक विचार प्रस्तुत हुआ है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम मिलकर उसको और अच्छा कैसे बनाएँ। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि अच्छे सुझाव आने चाहिए। जो लोग मेरे आज के भाषण को टीवी पर सुनते होंगे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अगर आप इसमें कुछ अच्छी परफेक्ट चीज़ें दे सकते हैं, तो दीजिए। यह देश के गरीब के लिए करना है। इसमें कोई दल नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि हम सब मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएँगे।

यह बात सही है कि अगर मैं यहां बैठकर अंग्रेज़ी में 9 लिखता हूँ, तो मैं नहीं मानता हूँ कि यहां बैठा कोई व्यक्ति इस बात से इनकार करेगा कि यह 9 है, लेकिन वहां बैठने वाले को वह 6 दिखेगा। मैं अंग्रेज़ी में यहां 9 लिखूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन अब आपको वह 6 दिखता है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि आप वहां बैठे हैं। अब कोई मुझे यह बताए कि अगर हिन्दुस्तान की 'Ease of Doing Business' रैंकिंग में कुछ सुधार होता है, तो हमें दुःख क्यों होना चाहिए? क्या इस देश के हर नागरिक को गर्व नहीं होना चाहिए कि 'Ease of Doing Business' हुआ, दुनिया में हमारी एक छवि बनी? देश के लिए यह एक अच्छी बात बनी है। अब हमने किया, आपने किया, वह मुद्दा जब हम चुनाव में जाएँगे, तब खेल लेंगे, लेकिन जब देश की बात होती है, तो अच्छा है। हम यहां तक चले जाते हैं कि जब हम किसी रेटिंग एजेंसी को यह दें, तो हम पर हमला बोलना कभी संभव नहीं होता है, तो उस रेटिंग एजेंसी पर ही हमला बोल देते हैं। दुनिया में शायद ऐसा कहीं नहीं होता होगा। कभी-कभी तो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आपको भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करनी चाहिए, जमकर के करनी चाहिए, आपका हक है। मोदी की आलोचना करनी चाहिए, जमकर के करनी चाहिए, बाल नोंच लेने चाहिए। डेमोक्रेसी में आपका पूरा हक है, लेकिन भाजपा की बुराइयां करते-करते आप भूल जाते हैं और भारत की बुराई करने लग जाते हैं। आप फिसल जाते हैं। आप मोदी पर हमला बोलते-बोलते हिन्दुस्तान पर जाकर हमला बोल देते हैं। जहां तक भाजपा और मोदी की बुराई करने की बात है, राजनीति में आपका हक है और आपको करना भी चाहिए, लेकिन इसके कारण आप मर्यादा लांघ देते हैं

[श्री नरेंद्र मोदी]

और उसके कारण देश का बहुत नुकसान होता है। यह ठीक है कि आप यह कभी नहीं स्वीकार कर पाएँगे कि यहां हमारे जैसे लोग बैठे हों। कैसे स्वीकारेंगे? आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, लेकिन मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए कि देश को नुकसान हो, देश की दुनिया में बदनामी हो।

अब यहां पर एक विषय आया। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में न्यू इंडिया की कल्पना की है। स्वामी विवेकानन्द ने भी नये भारत की चर्चा की थी, महात्मा गांधी भी यंग इंडिया की बात करते थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी, जब वे पद पर थे, तब उन्होंने भी नये भारत की संकल्पना की बात कही थी। मुझे पता नहीं इन्हें क्या परेशानी है कि ये कहते हैं कि हमें न्यू इंडिया नहीं चाहिए। हमें तो हमारा वह भारत चाहिए, हमें पुराना भारत चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... I would request all the Members not to make loose commentary while sitting. If any Member has ...(*Interruptions*)... They can raise their hands. I will recognize them and call them. Please don't disturb when the Prime Minister is addressing the House and also participating in a debate. We must show 'maryada'.

श्री नरेंद्र मोदीः हमें गांधी वाला भारत चाहिए, मुझे भी गांधी वाला भारत चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिल चुकी है, अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। यह कांग्रेस मुक्त भारत मोदी का विचार नहीं, यह गांधी का है। हम तो उन पदचिन्हों पर चलने के प्रयास में हैं। अब आपको वह भारत चाहिए, आप कहते हैं कि हमें तो वह वाला भारत चाहिए, क्या सेना के जीप घोटाले वाला भारत, क्या पनडुप्पी घोटाले वाला भारत, क्या बोफार्स घोटाले वाला भारत, क्या हेलिकॉप्टर घोटाले वाला भारत? आपको न्यू इंडिया नहीं चाहिए, आपको वह भारत चाहिए? आपको इमरजेंसी वाला, आपातकाल वाला, देश को जेलखाना बना देने वाला, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई देसाई जैसे लोगों को जेल में बंद करने वाला, देश में लाखों लोगों को जेल में बंद करने वाला इमरजेंसी वाला भारत चाहिए? आपको ऐसा भारत चाहिए? लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेना, देश के अखबारों पर ताले लगा देना, यह भारत आपको चाहिए। आपको कौन सा भारत चाहिए, वह भारत कि बड़ा पेड़ गिरने के बाद हजारों निर्दोष सिखों का कत्लेआम हो जाए, आपको यह भारत चाहिए? आपको "न्यू इंडिया" नहीं चाहिए, आपको भारत चाहिए। आपको वह भारत चाहिए ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र)ः गोधरा को याद करिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

श्री नरेंद्र मोदीः आपको वह भारत चाहिए, जब तंदूर कांड होता हो और रसूखदार लोगों के सामने प्रशासन घुटने टेकता हो? ...**(व्यवधान)**... आपको वह भारत चाहिए? हज़ारों लोगों की मौत के गुनहगार को विमान में बिठाकर उसे देश के बाहर ले जाया जाए, आपको वह भारत चाहिए? ...**(व्यवधान)**... दाओस में आप भी गए थे, दाओस में हम भी गए थे, लेकिन आप किसी की चिट्ठी लेकर के किसी को भेजते हैं - आपको वह भारत चाहिए? ...**(व्यवधान)**... आपको "न्यू इंडिया" नहीं चाहिए? ...**(व्यवधान)**... यहां पर राष्ट्रपति जी ने "जन-धन योजना" का उल्लेख

किया है। आपने "जन-धन योजना" की भी आलोचना की थी। आपने कहा कि यह तो कुछ नहीं है, पहले हुआ था। मैं चाहूंगा कि कम से कम तथ्यों को हम स्वीकार करें, पोलिटिकली जो बोलना है, बोलते रहें। जो हम 31 करोड़ जन-धन अकाउंट्स की बात करते हैं, वे सारे के सारे 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद जो खुले हैं, उन्हीं के हैं। इस record को कोई बदल नहीं सकता है, यह record उपलब्ध है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तथ्यों को ज़रा ठीक कर लें तो अच्छा होगा। आपने यह भी कहा कि हम तो name changer हैं, game changer नहीं हैं। अगर आप हमारे कार्यकलापों को देखेंगे और सच्चाई से कहना होगा तो आप कहेंगे कि हम तो aim chaser हैं। हम लक्ष्य का पीछा करने वाले लोग हैं और लक्ष्य प्राप्त करके रहते हैं। इसलिए हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे समय सीमा में पार करने के लिए रोडमैप तैयार करते हैं, resources को mobilize करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि देश को मुसीबतों से मुक्ति दिलाने की दिशा में हम भी कुछ योगदान करें। महोदय, कांग्रेस का तरसना बहुत स्वाभाविक है कि हमारी जय-जयकार करो, हमें बार-बार याद करो, हर जगह पर हमें याद करो – आपकी यह इच्छा रहना बहुत स्वाभाविक है। यह सुनते-सुनते आपको आदत हो गयी है कि इसके सिवाय कोई चीज़ अंदर फिट ही नहीं होती है। मुझे खुशी होगी – आप record चेक कर लीजिए कि 15 अगस्त को लालकिले पर आपके जितने प्रधान मंत्री हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्री, जो इस देश के प्रधान मंत्री हुए हैं, उनके भाषण में किसी और सरकार का, किसी और राज्य सरकार का, जिसके द्वारा इस देश की भलाई के लिए कोई काम हुआ हो, उसका उल्लेख किया हो। मैं हूं, जो लालकिले की प्राचीर से कहता हूं कि देश आज जहां पहुंचा है, अब तक की सभी सरकारों का उसमें योगदान है, सभी राज्य सरकारों का योगदान है। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... हम इस बात के लिए तड़पते नहीं हैं कि आप अटल जी का नाम याद करो। हम तड़पते नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**... आप मजबूरी में कह रहे होंगे तो ठीक है। आपको जो नाम ठीक लगे, आप दीजिए। आपने यह भी कह दिया कि 2014 से पहले जो कुछ भी हुआ, सब आपके खाते में। क्रेडिट लेने की बड़ी इच्छा हो रही है। आपके नियम भी बड़े कमाल के हैं। जब हम छोटे थे, गांव में क्रिकेट खेलने वालों को देखते थे, तो छोटे-छोटे बच्चे खेलते थे और बाद में हम देखते थे end में झगड़ा होता था तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि क्यों अभी तो खेल रहे थे और अब लड़ रहे हैं। फिर देखा कि उनका एक नियम होता था जिसके हाथ में बैट होता था, वह बैटिंग करता था और जैसे ही वह आउट होता था, वह बोलता था कि मैं चलता हूं। आप लोग भी यही हैं आगे चल कर बैटिंग आपको ही मिलेगी क्या? और अब बैटिंग नहीं मिली तो बोला कि हम लोग जाते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः यह पद्धित नहीं है। What is happening? What is happening to the people? You are all hon. Members. You are supposed to listen to the other side. And, afterwards, if you want to say something, you will get an opportunity.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, we expected something better than this.

MR. CHAIRMAN: That is your expectation.

श्री नरेंद्र मोदीः अब आधार की बात आती है, तो आप कहते हैं कि काम हमारा है और क्रेडिट आप ले रहे हो, अगर आप यह कहते हैं तो अच्छा है। लेकिन आपको यह याद रहना

[श्री नरेंद्र मोदी]

चाहिए कि 7 जुलाई, 1998 को इसी सदन में, और सभापति जी उस समय इसी सदन के सदस्य थे, तो 7 जुलाई, 1998 को उन्होंने इसी सदन में as a Member एक सवाल पूछा था और तब के गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसी सदन में जवाब दिया था और उस जवाब में उन्होंने कहा था, "Multipurpose National Identity Cards will also be used for issuing Passports, Driving Licences, Ration Cards, healthcare, admission in educational institutions, employment in public and private sector, life and general insurance, as also for maintenance of land records and urban property-holdings." आधार का बीज यहां है। 20 साल पहले ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Some people have got ...Pradhan Mantriji, one minute. I would like to tell everyone ...(*Interruptions*)... What happened to you, Renukaji? ...(*Interruptions*)...If you have some problem, go to a doctor, please. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Sit down, Smt. Renuka Chowdhury. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... This is not the way. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I cannot resist... ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: I have to name you. ...(*Interruptions*)... Please, don't do that. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेंद्र मोदीः सभापति जी, आप आज रेणुका जी को कुछ मत कहिए...

MR. CHAIRMAN: I am suggesting to the Secretariat and also media not to report such loose talk and unruly behavior. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेंद्र मोदीः सभापति जी मेरी आपसे प्रार्थना है आप आज रेणुका जी को कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You control your Members, please. ...(*Interruptions*)... I have to control everybody. ...(*Interruptions*)... Mr. Anand Sharma, this is not the way. This unruly behaviour cannot be appreciated. The entire country is watching us. ...(*Interruptions*)... We should not become a laughing stock before the country. ...(*Interruptions*)...

श्री आनन्द शर्माः ये हंसे तो बुरा, वो हंसे तो अच्छा ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः कोई हंसे तो अच्छा नहीं है। हंसना नहीं है ...**(व्यवधान)**... हमको देखकर लोग हंस रहे हैं ...**(व्यवधान)**... Nothing will go on record.

श्रीमती रेणुका चौधरीः *

वस्त्र मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)ः *

---

*Not recorded.

श्री नरेंद्र मोदीः 20 साल पहले यह vision अटल बिहारी वाजपेयी का था लेकिन कांग्रेस कहती है कि आधार उसने शुरू किया तो भी हमें आपको क्रेडिट देने में तकलीफ नहीं है। आधार आपका। हमने दल से आगे देश को रखा है और हमारे निर्णय का आधार देशहित रहता है। आज क्रेडिट लेने के लिए आप बेताब हैं, बहुत स्वाभाविक है। SIT बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, आपने तीन साल तक उसका निर्णय नहीं किया, यह क्रेडिट आप ही को जाना चाहिए। हमने पहली SIT का गठन किया, लेकिन आप कह सकते हैं कि हमारे सामने ऐसा विषय आया था। काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने का क्रेडिट भी कांग्रेस स्वीकार कर ले। कांग्रेस ने 28 साल तक बेनामी सम्पत्ति कानून को लागू नहीं किया, उसकी क्रेडिट भी आप ले लीजिए।

श्री आनन्द शर्माः लोकपाल का किसको देंगे?

श्री नरेंद्र मोदीः अब तक 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा सम्पत्ति – आपको पता होना चाहिए, माननीय आनन्द जी, आप लम्बे अरसे तक यहां बैठे हैं और बोलने की आपकी विशेष स्टाइल भी है और आप तो बर्फ का छुरा बनाकर भी घोंप सकते, जिसका पता भी नहीं चले, लेकिन यह बेनामी सम्पत्ति का कानून 28 साल पहले पारित हो चुका है, दोनों सदनों में पारित हो चुका था, लेकिन उसके रूल्स नहीं बनाये, नोटिफाई नहीं किया और वह अटका हुआ था। इसके लिए इनको किसने रोका, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं था, यह जानकारी के लिए है। मुझे अच्छा लगा कि आप जैसे नेताओं को भी कुछ...। अब तक 3500 करोड़ रुपये की बेनामी सम्पत्ति जब्त की है। अब आपके कार्यकाल में इतनी बेनामी सम्पत्ति बनी, तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए। आपके लिए ही सारा क्रेडिट है। सारी दुनिया बदली है, मैं नहीं मानता हूं कि आपको Insolvency and Bankruptcy Code का ज्ञान नहीं था। लेकिन आपको क्रेडिट जाना चाहिए कि बहुत लोगों के लाभार्थ आपने इसको नहीं लगाया, क्रेडिट आपको जाना चाहिए ।

देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ग्लोबल कम्युनिटी को भारत के प्रति विश्वास पैदा हो, भारत के नियमों और कानूनों के प्रति विश्वास पैदा हो, हमने इसके लिए निर्णय किए। वन रैंक, वन पेंशन के लिए चार दशक तक देश की आंख में धूल झोंकते रहे और 500 करोड़ का बजट लेकर के चुनाव में चले गए, क्योंकि हवा बन चुकी थी कि अब क्या करें? जब हम आए, तो हमने देखा कि रिकॉर्ड तक नहीं थे, इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखा और जब हमने इसको लागू किया, तो 11,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ी। आप 500 करोड़ में इसे कैसे देते, तो अब ये सारा क्रेडिट आपको ही जाएगा।

GST के लिए मध्य रात्रि को समारोह हुआ, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। सभी दल आए और आपको यह लगा कि कहीं इसका हमारे को क्रेडिट मिल जाएगा और आप मानो या न मानो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, GST के संबंध में इसकी जितनी भी निगेटिविटी है, वह आपके खाते में जमा हो रही है और होती रहेगी और देश के दिमाग में फिट हो जाएगा। आप लोग सोचिए – इसका क्रेडिट लेने की चिंता और खुद को क्रेडिट मिलता रहे।

अब नीम कोटिंग की बात आयी। आपकी तरफ से कहा गया कि इसको हमने शुरू किया था। जिस चीज़ को आप आधी-अधूरी छोड़ दें और आप इस पर कैप लगा दें कि इससे आगे नहीं जाना है, तब उस योजना का लाभ होने के मुकाबले नुकसान ज्यादा होता है। आखिरकार नीम कोटिंग के पीछे दो विषय थे, जिनका आपको भी ज्ञान था। एक, यूरिया की ताकत में वृद्धि होती

[श्री नरेंद्र मोदी]

है, इसलिए किसान का कम यूरिया से काम चल सकता है। दूसरा, क्वालिटेटिव चेंज आता है, ताकि उत्पादन में वृद्धि होती है, यह मानी हुई बात थी। यूरिया किसानों के पास जाने के बजाय, यह कारखानों में चला जाता था, बिल किसान के नाम पर कटता था, सब्सिडी किसान के नाम पर कटती थी और यह कारखानों में चला जाता था। अगर हंड्रेड परसेंट नीम कोटिंग होती है, तो यह यूरिया किसी कारखाने में काम नहीं आएगा, यह आपको भी पता था। इसको 35 प्रतिशत करने के बाद 65 प्रतिशत का दरवाजा किसके लिए खुला रखा, यह क्रेडिट मैं किसको दूं और इसलिए मैं समझता हूं कि हंड्रेड परसेंट के पीछे हम लगे, इतना ही नहीं, जो इम्पोर्टेड यूरिया आता है, उसकी भी आने से पहले नीम कोटिंग होती है। उसकी भी आने से पहले नीम कोटिंग होती है और उसी का परिणाम है कि आज यूरिया की कोई किल्लत नहीं होती वरना मैं जब मुख्य मंत्री था तो मुझे हर वर्ष दो-तीन चिट्ठियां प्रधान मंत्री जी को यूरिया के लिए लिखनी पड़ती थीं। मैं जब यहां आया, तो सभी चीफ मिनिस्टर्स से यूरिया के बारे में चिट्ठी आती थी। आज एक चिट्ठी नहीं आती है और न कभी लाठीचार्ज होता है क्योंकि यूरिया लोगों को मिल रहा है। तो कुछ चीजें बदली जा सकती हैं।

मैं यह बताना चाहूंगा, कभी-कभी राजनीति बहुत हावी होती है, बार-बार चुनाव का यह नतीजा है कि योजना पूरी बनी हो या न बनी हो, हम पत्थर जड़ देते हैं, फीता काट देते हैं, तख्ती लगा देते हैं। फिर उस का परिणाम क्या हुआ? आप देखें हमें रेलवे के बजट में घोषणाएं बंद करनी पड़ीं। ऐसा क्यों हुआ? मैंने देखा कि पुरानी सरकारों ने 1500 से ज्यादा ऐसी रेलवे की योजनाएं घोषित कर दी थीं, जिन्हें बाद में कोई देखने वाला ही न था। एक दिन हाउस में तालियां बज गयीं, किसी अखबार में छप गया, उस एमपी ने क्षेत्र में जाकर मालाएं पहन लीं और बात पूरी हो गयी। इस culture से देश का बहुत नुकसान हुआ है। आप हैरान होंगे, मैंने प्रगति में technology का उपयोग करते हुए सारे रुके प्रोजेक्ट्स के बारे में initiative लेकर उनका review किया। आज सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज़ ऑन लाइन होते हैं, भारत सरकार के सभी सचिव होते हैं और मैं ऑनलाइन सब के साथ बैठता हूं। आप हैरान होंगे हमारे सामने ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जोकि 30-40 साल पहले तय हुए, शिलान्यास हो गया, लेकिन बाद में कागज पर उनकी लकीर भी दिखायी नहीं दी, ऐसे ही पड़े रहे। मैं एक-एक प्रोजेक्ट का review करने लगा और मैंने यह नहीं कहा कि यह तो पुरानी सरकार का है, इस में मेरी क्या जिम्मेदारी है? आखिर यह देश एक continuity है, सरकारें आएं, जाएं, आप बैठें, दूसरा बैठे, तीसरा बैठे, हम इसे रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र है, लेकिन सरकार में हैं तो यह नहीं चलता कि यह तो जयराम रमेश जी के टाइम में हुआ था, इसे मारो ताला। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप हैरान होंगे 9 लाख करोड़ से ज्यादा के ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने अब तक clear किए हैं। मैंने सारी मिनिस्ट्रीज को बिठाया और कहा कि जो भी हो, इन्हें करो भले ही ये 30-40 साल पुराने हैं। अब यही अगर उस समय हो गया होता तो शायद ये कुछ हजार करोड़ों में हो जाते, लेकिन आज 9-10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स बन गए। इसलिए ये काम हम कर रहे हैं। आपने भी सरकार चलायी है, हम भी चला रहे हैं और जो भी सरकार बनाता है, उसे वह चलानी होती है क्योंकि वह उस की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से चलाते हैं। आज सब जगह पर पत्थर लगे हैं, आप लोगों के नाम हैं। अब तो शायद लोग पत्थर की चोरी भी कर के गए हैं, लेकिन क्रेडिट सब आप को जाता है। ये योजनाएं आपकी रहीं।

अब यहां हमारे आज़ाद साहब ने Food Security Bill की बात की और वे date के साथ बोले। आप से यह कोई भी पूछेगा कि आप ने जो date दी, लेकिन हम तो आप के बाद आए, एक साल बाद आए। आप ने एक साल में इसे लागू क्यों नहीं किया? आपने यह भी कहा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। आप को पता होना चाहिए कि केरल, जहां आप की सरकार थी, उस ने इसे स्वीकार नहीं किया था और सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा था, लेकिन अब आप वह भी हमारे सिर डाल देते हैं। वह आप को करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि जो हम निर्णय करें, उसे पूरा करने की तैयारी के साथ उसे करना चाहिए। अब फर्टिलाइज़र के कारखाने खोलने के बारे में तो आप कह रहे हैं कि हमारे समय में हुआ, लेकिन बंद भी तो आप के समय में हुए, हजारों लोग बेरोजगार भी तो आपके समय में हुए। उसके लिए भी तो क्रेडिट लीजिए। इसलिए आज हम इसे लागू कर रहे हैं और नीतिगत बदलाव कर के कर रहे हैं। आप देखें, आज यूपी में गोरखपुर, बिहार में बरौनी, झारखंड में सिंदरी में यूरिया के जो कारखाने बंद पड़े थे, उन्हें हम तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जगदीशपुर हल्दिया पाइप लाइन को उसके साथ जोड़ा है। यह नीतिगत बदलाव किया है ताकि उन्हें गैस मिल जाए और उस कारखाने को चलाने में सुविधा हो जाएगी। अब यह देश का वह इलाका है, जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था से पूर्व भारत के विकास की संभावना बढ़ जाएगी। ये वे स्टेट्स नहीं हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा है। देश के लिए यह जरूरी है कि पूर्व भारत के राज्यों का विकास होना चाहिए, देश का संतुलित विकास होना चाहिए। हम बिल्कुल सीधी-साधी डेवलेपमेंट की थ्योरी के आधार पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप इन चीजों को appreciate करेंगे।

हमारे माननीय सदस्य श्री अमित शाह का भाषण हुआ और मुझे अच्छा लगा कि आज़ाद साहब ने उसमें से यह खोजकर निकाला कि आपने इतना लम्बा भाषण दिया, सरदार पटेल के बारे में क्यों नहीं बोले? मुझे अच्छा लगा कि आपने सरदार साहब को याद किया। ...**(व्यवधान)**... अभी कुछ ही दिन हुए गुजरात में चुनाव हुए थे। हमारे बाहुबली यहां पर बैठे हुए हैं। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हर लिट्रेचर में सरदार साहब थे। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि चलो, बहुत सालों के बाद यह दिन भी आया, मैं सोचता था कि यह परम्परा बनी रहेगी, लेकिन गुजरात का चुनाव समाप्त हुआ और यहां आपकी पार्टी का एक कार्यक्रम था। अभी भी आप पुराने चित्र देख सकते हैं, बैकड्रॉप पर कहीं पर भी सरदार साहब का चित्र नहीं है। उस समय अखबारों ने लिखा कि एक सप्ताह के बाद ही आपके यहां कार्यक्रम हो रहा है और सरदार साहब गायब हैं। हम सरदार साहब का नाम दे रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने उल्लेख नहीं किया। आपने उसका उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन आप यह भी याद करें कि सरदार साहब और बाबा साहेब अम्बेडकर को 'भारत रत्न' कब मिला? इतना समय बीच में क्यों चला गया? आप चर्चा करें, आप आरोप लगाएं, यह तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाहर का विषय था, लेकिन फिर भी आपने उठाया, तो अच्छी बात है। जब आप ऐसे विषय उठाते हैं, तो चार उंगलियां खुद की तरफ होती हैं, आप यह न भूलें, यही मेरा कहना है।

आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे देश में इस प्रकार से काम हुए हैं। हो सकता है कि आपकी कार्यशैली में इस प्रकार की बारीकियों में जाने का शायद स्वभाव नहीं होगा। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं बहुत लम्बे अर्से तक मुख्य मंत्री रहा हूं। आज़ाद साहब भी मुख्य मंत्री रहे हैं, इसलिए इनको पता है कि बहुत बारीकियों में जाना पड़ता है। शरद जी भी बहुत लम्बे अर्से तक

[श्री नरेंद्र मोदी]

मुख्य मंत्री रहे हैं, इनको पता है कि बहुत बारीकियों में जाना पड़ता है। मुख्य मंत्री इधर-उधर नहीं जा सकता है। हम सब जो यहां पर मुख्य मंत्री रहे हैं, सबको पता है कि यहां पर मुख्य मंत्री तो बहुत कम आते हैं, यदि आते हैं, तो छोटा सा डिपार्टमेंट लेकर रहते हैं। मेरे जिम्मे एक बड़ा काम आ गया है, इसलिए वहीं की वह आदत भी काम आ रही है। हमारे देश में पिछले वर्षों में जो सिंचाई के प्रोजेक्ट तैयार हुए, तो डैम बन गया होगा, लेकिन यह पानी क्यों है? यह पानी खेती के लिए है। हमने 40-40, 50-50 साल तक केनाल नेटवर्क ही नहीं बनाया। यानी कोई कल्पना कर सकता है वह छः मंजिला मकान बनाए और उसमें स्टेयरकेस और लिफ्ट भी न हो, तो ऐसे-ऐसे काम हुए । मैंने उनमें से 99 को आइडेंटिफाई किया, हजारों, करोड़ों रुपए की योजना से काम चालू किया। किसानों के पास पानी पहुंचे, इस दिशा में काम किया है। आज 50 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी की योजनाएं जल्दी से पूरी हों, इस दिशा में काम चल रहा है। सवाल है, आपने बनाया, अच्छा बनाया। अच्छा काम किया, अच्छा है, लेकिन सोच अधूरी, काम अधूरा और रुपए गए तथा परिणाम भी नहीं मिला। अच्छा होता अगर कॉम्प्रिहेंसिव होता, इंटिग्रेटेड एप्रोच होती, होलिस्टिक भी होती, तो आप ही के समय जो काम हुए हैं, उसमें भी अगर वे पूरे किए होते, तो देश का भला होता। आपने नहीं किया, यह मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ करने जैसे काम कैसे करने चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई। जिन-जिनको शासन करने का अवसर मिला है, उन लोगों का यह दायित्व बनता है, इसलिए आपने देखा होगा कि हमने सत्ता में आकर एक बड़ा बदलाव किया है। हमारे देश में ज्यादातर बजट एलोकेशन होने को ही ज्यादा संतोषजनक माना जाता है। ताली बज जाती है, वह एलोकेट हो गया। आउटले की तरफ देखने वाली संख्या बहुत कम है, आउटपुट पर देखने वाली संख्या उससे भी कम है और आउटकम की तो चर्चा ही नहीं होती थी। हमने पूरा वर्क कल्चर ऐसा बना दिया। इस सरकार ने आग्रह रखा है और पार्लियामेंट में आउटकम रिपोर्ट रखते हैं, ताकि पता चल सके कि जिस काम के लिए रुपया निकला था, वह उसी काम में गया कि नहीं गया? इसीलिए हमारा प्रयास आउटकम पर बल देने की दिशा में रहना चाहिए।

महोदय, किसानों की आमदनी बढ़ाने के विषय की यहां चर्चा हुई है। मैं हैरान हूं कि किसान की आमदनी डबल होने पर किसको एतराज़ हो सकता है? इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उसके साथ कोई राजनीति है, बल्कि यह बात यहां बैठे हर व्यक्ति के दिल में है कि यह एक ऐसा काम है जो हमें करना चाहिए। यह कैसे होगा? ज़मीन के टुकड़े बढ़ते जा रहे हैं। परिवार की संख्या बढ़ती है – अगर उसकी दस बीघा ज़मीन है, वह बच्चों में बंट जाती है, तो दो बीघा, एक बीघा हिस्से में आ जाता है। यह कठिनाई है। हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, एग्रो टेक्नीक पर जाना ही पड़ेगा, हमें modernize होना ही पड़ेगा। अगर हम यह करते हैं तो बदलाव होगा।

महोदय, Soil health card एक प्रयास है। Per drop-More drop, micro irrigation एक प्रयास है।

महोदय, स्प्रिंकलर – एक जमाना था, जब हमारे देश में किसान सोचते थे कि flood irrigation के बिना शुगरकेन हो ही नहीं सकता। वह इस कन्विक्शन वाला था। वह यही मानता था कि गन्ने की खेती के लिए खेत पानी से लबालब भरा होना चाहिए। लेकिन अनुभव से – मैं तो गुजरात

में था, मेरा तो कम्पल्सरी नियम था, अब स्प्रिंकलर से शुगरकेन हो रही है और शुगर कंटेट का लेवल बहुत ऊंचा आया है। अब यह धीरे-धीरे देश भर में हो रहा है। अब पानी बचेगा। ऐसे कई प्रयोग हैं। पहले जो होता था, वह हम सबको मालूम है कि जो केले की खेती करते थे, केले की खेती करने वाले वे लोग, केले का फल मिलने के बाद, उसका जो तना खड़ा रहता है, उसको निकालने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता था, जोकि एक एकड़ पर 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये का खर्च आता था। हमारे यहां एग्रीकल्वरल युनिवर्सिटी ने जो परिणाम दिया है, उसके अनुसार उन्होंने केले के तने में से फ्रैब्रिक बनाया, कपड़े बनाए और अब बहुत बढ़िया क्वालिटी के कपड़े बन रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां सूखी भूमि है, यदि उसको वहां काटकर डाल दिया जाए तो वहां 90 दिनों तक पेड़-पौधे बिना पानी के आगे बढ़ सकते हैं। अब जो वेस्टेज था, वह वेल्थ में क्रिएट हुआ है और आज उसको लेने के लिए लोग आते हैं। अब वे 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये पर एकड़ दे रहे हैं। हमारे देश में एग्रीकल्वर का जो वेस्ट है, यदि हम उसी पर बल दें तो भी हम उनकी और देश की इनकम होने में मदद कर सकते हैं। हमारे देश में यदि यहां शुगर ज्यादा हो जाए, तो भी किसान मरेगा, कम हो जाए, तो भी किसान मरेगा। शुगर की ज्यादातर फैक्टरियां किसानों के द्वारा चलाई हुई हैं। हमने पेट्रोल में ethanol blending 10 परसेंट कर दिया, इस कारण से, जिस समय शुगर की मार्किट पर जब यह प्रेशर आएगा, क्योंकि इस पर ग्लोबल इम्पैक्ट रहता है, तब ethanol पर डायवर्ट करेंगे। इससे किसान की सुरक्षा की संभावना होगी।

हमने "किसान संपदा योजना" दी। हमें मालूम है कि हमारे लाखों, करोड़ों रुपये इसलिए बरबाद हो रहे हैं क्योंकि खेत से लेकर मार्किट तक की चेन में कई वीक प्वाइंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के वीक प्वाइंट्स हैं। जब हमारी बीज से बाजार तक की एक पूरी comprehensive approach होगी, तब जाकर प्रयास होगा और इसलिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि चाहे "ईनाम योजना" हो – "ईनाम योजना" अभी प्रारंभ हुई है। कई राज्य हैं, जिनको अपने एटीएम सेट में जो बदलाव करना चाहिए था, वह अभी भी नहीं किया है। करीब-करीब 36 हज़ार करोड़ रुपये का कारोबार है। यह किसानों ने "ईनाम योजना" पर ऑनलाइन बिक्री करके किया है। 36 हज़ार करोड़ का कारोबार अपने आप में बड़ा होता है और यह एक शुभ शुरुआत है। मैं समझता हूं कि यह काफी आगे जाएगा। हमें वैल्यू एडिशन पर जाना पड़ेगा। अगर किसान हरी मिर्च बेचता है, तो उसको उसका बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन अगर मिर्च लाल होती है, लाल होकर पाउडर बनती है, पाउडर बनाकर उसकी पैंकिंग होती है, अगर वह पैकिंग अच्छी तरह से ब्रांडिंग होती है, तो किसान की आय बढ़ती है। हमें वैल्यू एडिशन पर जाना होगा। हमारे किसान की allied equity - आज खेत के अंदर सोलर एनर्जी का फार्म जोड़ा जा सकता है। यह किसान की आय बढ़ा सकता है। सोलर पंप उसकी बिजली भी पैदा कर सकता है। यह सोलर पंप चला सकता है, डीज़ल का खर्च कम कर सकता है, बिजली का खर्च कम कर सकता है और वह बिजली राज्य सरकारें खरीद भी सकती हैं। उससे उनके खर्च में एक बहुत बड़ी कमी होगी। बांस, बैम्बू का 90 साल से, आपका दोष नहीं है, 90 साल से कानून बना दिया कि यह तो ट्री है, इसे काट नहीं सकते, जब कि सारी दुनिया में बैम्बू ग्रास है। अब आपको यह करना चाहिए था, तो क्रेडिट आपको जाता। हमने सोचा, आज हमने बैम्बू को ग्रास की कैटेगरी में रखा है। आज किसान अपने खेत के बाहर, बॉर्डर पर बैम्बू की खेती कर सकता है। बैम्बू की खेती से उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं है, वह अतिरिक्त है। आज हिंदुस्तान हजारों करोड़ रुपए का बैम्बू इम्पोर्ट करता है। हम दियासलाई के लिए बैम्बू बाहर से लाते हैं, पतंग के लिए बैम्बू

[श्री नरेंद्र मोदी]

बाहर से लाते हैं, अगरबत्ती के लिए बैम्बू बाहर से लाते हैं। यह एक छोटा सा दायरा है, जो किसान की आय बढ़ाने की ताकत रखा है।

मधुमक्खी, अब मैं हैरान हूँ, मधुमक्खी के क्षेत्र में कितना काम हो सकता था, हम उसको नहीं कर पाए। मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं कर पाए? इन दिनों हमने चार वर्षों में 11 Integrated Bee-keeping Development Centres खड़े किए हैं। आज शहद के उत्पादन में 38 परसेंट इंक्रीज हुआ है और यह शहद दुनिया के बाजारों में जाने लगा है। सबसे बड़ी बात, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, आज दुनिया holistic health care की तरफ चली है, दुनिया eco-friendly life की तरफ कांशस हुई है और उसके कारण chemical wax की बजाय bee wax की मांग बढ़ रही है। हमारा यह honey bee का काम इतनी अधिक मात्रा में bee wax को बल दे सकता है, जिसके कारण आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा global market capture कर सकते हैं। हमारा किसान साइड में एक पेड़ के नीचे बैठकर यह काम कर सकता है। पशुपालन, fisheries, poultries, value addition, ऐसी कई चीजें हैं, जिनको अगर हम एक साथ जोड़ कर किसानों के घर तक पहुंचाएंगे, तो मैं यह नहीं मानता हूँ कि किसानों की आमदनी दुगुनी करने में कोई दिक्कत हो सकती है। किसान की हालत सुधर सकती है। हम सब को प्रयास करने होंगे और हम सब प्रयास करेंगे, तो परिणाम जरूर मिलेगा। हमारा उस दिशा में प्रयास रहना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, only *bhasan*; no action. We are staging a walk out.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, only *bhasan*; we are not getting any answer. ...(*Interruptions*)... No action; only *bhasan*. ...(*Interruptions*)... We have made a non-political speech. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Only walk out; no talk out. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: We want serious answers. ...(*Interruptions*)... No action; only *bhasan*. ...(*Interruptions*)...

(*At this stage some hon. Members left the Chamber*)

श्री नरेंद्र मोदीः आज हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान का मजाक उड़ाया जा रहा है, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, जनधन योजना का मजाक उड़ाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मजाक उड़ाया जा रहा है, काले धन पर हो रही कार्यवाही का मजाक उड़ाया जा रहा है, ...**(व्यवधान)**... सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ...**(व्यवधान)**... लेकिन आप मुझे बताइए, ओबीसी कमीशन को संविधान का दर्जा मिले, इसका क्यों विरोध करना चाहिए? इतने सालों से इसकी मांग थी, आपकी कोई मजबूरियां होंगी, आप नहीं लाए। इस सदन में इस कमेटी में डालो, उस कमेटी में डालो, लटका पड़ा है। क्या हम इस काम को नहीं कर सकते हैं?

श्री बी. के. हरिप्रसादः हमने बोला है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः बैठिए, प्लीज़।

श्री बी. के. हरिप्रसादः *

MR. CHAIRMAN: This is not the way. ...(*Interruptions*)... Mr. Hariprasad, sit down. ...(*Interruptions*)... This is not going on record. ...(*Interruptions*)..

श्री नरेंद्र मोदीः यह तरीका, ...**(व्यवधान)**... वह आपको अमित भाई ने जवाब दे दिया है। ...**(व्यवधान)**... यह जब पूरा विरोध करने की हिम्मत नहीं होती है, जनता-जनार्दन को फेस करने की ताकत नहीं होती है, ...**(व्यवधान)**... आज जो ओबीसी समाज में एस्पिरेशंस जगे हैं, आज जो ओबीसी समाज जागरूक हुआ है, ओबीसी अपने हकों के लिए मैदान में आया है ...**(व्यवधान)**... आपकी राजनीति खुलेआम बात करने की हिम्मत नहीं करती है, इसलिए बहानेबाजी करते हो, लेकिन इस देश का ओबीसी समाज देश को देने वालों में से है। वह अगर अपना हक मांगता है, तो मैं आग्रह करूंगा कि राजनीति छोड़ करके और नई-नई चीजें जोड़ने के नाम पर इसे रोकने का प्रयास करने के बजाय इसको पारित करें। तीन तलाक, अगर आपको लगता है कि तीन तलाक के विषय पर आप जिस प्रकार का कानून चाहते हैं, किसने रोका था आपको? 30 साल पहले यह मामला आपके हाथों में आया था। आपको जैसा कानून चाहिए था, वैसा बनाना था। करना तो था, लेकिन आपकी राजनीति, आप ही के एक मंत्री का हाउस में भाषण था कि तीन तलाक क्यों जाना चाहिए, लेकिन जब चारों तरफ से आवाज उठी, राजनीति आई, वोट बैंक खतरे में पड़ गया, तो अचानक से उस मंत्री को भी जाना पड़ा और उस मिशन को भी जाना पड़ा। जो कारण दिया जा रहा है, वह हिन्दुस्तान के हर क्रिमिनल कानून के अन्दर जहां सजा है, ये जो logic दे रहे हैं, लागू हो सकता है। अगर किसी ने किसी की हत्या की, वह घर का इकलौता बेटा है, 30 साल की उम्र है, बूढ़े मां-बाप हैं, अब उसके जेल जाने का कानून क्यों बनाया, बूढ़े मां-बाप क्या खाएँगे? एक हिन्दू दो शादी करे, वह जेल चला जाए, उसके लिए सजा हो, तब आपको यह विचार नहीं आया कि उसके परिवार के लोग क्या खाएँगे। सजा है! इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी इसका अध्ययन करेगा, तो उसको आश्चर्य होगा कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। कभी-कभी मुझे लगता है, शायद हमारे नरेश जी ने बड़ी हमदर्दी दिखाई थी, वे चीरहरण कर रहे थे, यह कहना तो कठिन है, लेकिन वे बहुत कुछ कह रहे थे। भय! जेल! हम तो भुक्तभोगी हैं। तुलसी जी यहां बैठे हैं। 15 साल तक हमने क्या कुछ झेला है, हमें मालूम है, लेकिन कानून कानून का काम करे कि न करे! और आप यहां कहें कि किसी के बेटे को फँसाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, और क्या कुछ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि क्या इस प्रकार की बातें कर के हम कानून का उपहास कर रहे हैं या नहीं? यह कानून तय करेगा कि क्या होगा। इसीलिए जब आप कहते हैं कि मदद करो, ऐसे समय में मदद करो, तो किव दुष्यंत कुमार की कविता के शब्द हैं,

"उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें,
चाकू की पसलियों से गुज़ारिश तो देखिए।"

महिलाओं पर अत्याचार। मैं नहीं मानता हूँ कि महिलाओं पर अत्याचार, यह कांग्रेस, बीजेपी, इस पार्टी या फलानी पार्टी का विषय है। हो ही नहीं सकता। जो चिंता आपने जताई है, वह चिंता

*Not recorded.

[श्री नरेंद्र मोदी]

बहुत स्वाभाविक है, जो आज़ाद साहब ने बताई। इसलिए मैंने लाल किले से यह कहने की हिम्मत की थी कि बेटियों के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन कोई तो पूछो कि बेटा शाम को देर से घर क्यों आता है, कोई तो पूछो कि बेटा कहां जाता है, किसको मिलता है, कोई तो चिंता करे कि बेटों को भी संस्कार देने की जरूरत है। क्या हम सब एक स्वर से उन माताओं को झकझोर नहीं सकते, उन पिताओं को झकझोर नहीं सकते, उन शिक्षकों को झकझोर नहीं सकते? आखिर वह किसी न किसी का तो बेटा है, जो किसी बेटी के ऊपर अत्याचार कर रहा है। वह किसी न किसी का तो बेटा है। क्या हम सब एक स्वर में इस विषय पर नहीं बोल सकते हैं? आखिरकार यह एक सामाजिक दूषण है और उसमें जितना ज्यादा हम मिल कर काम करेंगे, उतना अच्छा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें इन सारी चीजों में मिल कर चलना चाहिए। 'उज्ज्वला योजना' महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन हमें भी यह सोचना होगा और मैं तो चाहूँगा और इस सदन के माध्यम से स्टार्टअप वालों से खास आग्रह करूँगा कि हमें देश में clean cooking का काम मिशन मोड में करना चाहिए। हो सके तो सोलर ऊर्जा आधारित ऐसे नये चूल्हों का इनोवेशन हो, ताकि गरीब को खाना पकाने के लिए एक नया पैसा खर्च न हो और गैस ट्रांसपोर्टेशन के खर्च भी बच जाएं, अपने ही घर में सोलर चूल्हों की व्यवस्था हो। आधुनिक इनोवेशन से ऐसे चूल्हे बन सकते हैं। क्लीन कुकिंग, हमारे सामाजिक जीवन के लिए, एनवायर्नमेंट के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये कोई राजनीतिक एजेंडा के कार्यक्रम नहीं हैं, ये देशहित के काम हैं। हम मिल-बैठ करके इनको आगे बढ़ाएं।

अब चर्चा हुई कि स्वच्छ भारत के एडवर्टाइज़मेंट पर इतना खर्चा हुआ। मैं ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहता हूं, जो किसी को बुरी लगे, लेकिन आप भी सरकार में रहे हैं और आप सार्वजनिक जीवन में जीते हैं। शौचालय या स्वच्छता ऐसे विषय हैं, जो जितनी मात्रा में infrastructural issues हैं, उससे ज्यादा behavioural issues हैं। यह आदत का विषय है, दुनिया में इस विषय पर अध्ययन करने वाले हर व्यक्ति ने यह कहा है। जब आप सरकार में थे, तब आपका भी इसी पर फोकस था कि जब तक behavioural changes नहीं आते हैं, तब तक इसमें breakthrough नहीं हो सकता है। इसके लिए जो एडवर्टाइज़मेंट दिखाए जाते हैं, वे सरकार के कार्यक्रमों की जगमगाहट नहीं हैं, उनके माध्यम से behavioral change के लिए छोटी-छोटी घटनाओं को दिखा करके, लोगों को शिक्षित करने का काम हो रहा है। यह बात कहने से पहले हम यह न भूलें कि गरीब आदमी के पैसों से खजाने में आए हुए धन से परिवार के कुछ लोगों के जन्मदिन पर अखबारों में एक-एक पेज के एडवर्टाइज़मेंट्स छपवा करके दिए गए थे। उसमें देश के कितने रुपये खर्च हुए, ज़रा इसका हिसाब भी लगा लीजिए। एक ही परिवार के लोगों के जन्मदिन के एडवर्टाइज़मेंट पर कितने रुपये खर्च हुए होंगे, आप उसको सुनकर चौंक जाएंगे। लेकिन यह जो खर्चा हुआ है, यह behavioral change लाने के लिए है, जिसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। जहां पर आपकी राज्य सरकारें हैं, आप उनको भी कहिए कि behavioural change के लिए बजट एलॉट करें। लोगों को शिक्षित करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्माः आपने जो हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... ठीक है, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... This is not going on record.

श्री आनन्द शर्माः *

MR. CHAIRMAN: Why are you wasting your energy? ...(*Interruptions*)... Why are you setting a bad precedent? ...(*Interruptions*)... When nothing is going on record, why should you waste your energy and set a bad precedent? ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: It is not a bad precedent. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: It is a bad precedent. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेंद्र मोदीः सभापति जी, हमारे राष्ट्रपति जी ने **...(व्यवधान)...**

SHRI ANAND SHARMA: I am following your ruling. ...(*Interruptions*)... I am following your direction. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: It is a bad precedent. ...(*Interruptions*)... Hundred per cent, it is a bad precedent. ...(*Interruptions*)... You are disturbing a speaker and suddenly standing up without the permission of the Chair. It is a bad precedent. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: You had said that if we want to ask something, we should stand up.

MR. CHAIRMAN: Yes, afterwards. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: You did not say 'afterwards'. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेंद्र मोदीः सभापति जी, यहां पर हमारे माननीय आज़ाद साहब ने बोफोर्स के मुद्दे को बड़े विस्तार से कहा और बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की। **...(व्यवधान)...** मैं कुछ क्वोट्स पढ़ना चाहता हूं। ये क्वोट्स कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री और बाद में निर्विवादित चुने गए राष्ट्रपति, श्रीमान् आर. वेंकटरमण जी की आत्मकथा का हिस्सा हैं। उनकी आत्मकथा है – "जब मैं राष्ट्रपति था"। जब उनकी मुलाकात जे.आर.डी. टाटा से हुई, उस मुलाकात का ब्यौरा उन्होंने इस किताब में लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है, "टाटा ने कहा तोप और दूसरे रक्षा सौदों में राजीव गांधी या उनके परिवार को लाभ हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन इसको नकारना मुकिश्ल होगा कि कांग्रेस पार्टी को कोई कमीशन नहीं मिला।" यह मैं वेंकटरमण जी की किताब पढ़ रहा हूं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। आगे उन्होंने लिखा है, "उन्हें लगता था कि 1980 के बाद से उद्योगपतियों से चंदा नहीं मांगा गया है और पार्टी का खर्चा ऐसे सौदों पर मिलने वाले कमीशन से चलता है।" सभापति महोदय, यह तो आर. वेंकटरमन जी ने कहा था। वे आपके बड़े वरिष्ठ नेता और राष्ट्रपति रहे थे। यहां पर किसी परिवारवाद की बात आई, तो बड़ा दुख हुआ और गुस्सा भी आता है। यह तो बड़ी स्वाभाविक बात है और मैं भी नहीं चाहता हूं कि आपमें से किसी की राजनीति को चोट पहुंचे। यह मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन आप ही के एक महाशय, जिनकी मीडिया में रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने क्या कहा-"Sultanate gone, but we behave like Sultans." सुल्तानी तो गई, लेकिन हम अभी भी सुल्तान की तरह behave कर रहे हैं। मैं जयराम रमेश जी के इस खुलेपन के लिए तो उन्हें बधाई देता हूं।

---

*Not recorded.

[श्री नरेंद्र मोदी]

5.00 P.M.

महोदय, देश में निम्न-मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग पर महंगाई का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। पहले महंगाई कहां तक पहुंची थी, वह आप सब जानते हैं। हमने कोशिश की है कि महंगाई 2 से 6 प्रतिशत के बीच नियंत्रित रहे। जिस तेजी से और जिस क्रम से महंगाई बढ़ रही थी, अगर उसी क्रम और तेजी से बढ़ती रहती, तो आज मध्यम वर्ग और निम्न-मध्यम वर्ग का जीना कितना मुश्किल हो जाता। इसकी आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। इन कदमों को उठाकर मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गों के परिवारों की सुरक्षा करने और उन्हें बचाने का काम हमने किया है।

महोदय, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार यदि अपने मकान बनाना चाहते हैं, तो बैंक की ब्याज दर में कटौती कर के और उसे सब्सिडी देकर उसे प्रोत्साहित करने का बड़ा और महत्वपूर्ण काम इस सरकार ने किया है। "प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी" में हमने नई कैटेगरीज निर्माण की हैं और घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज में 4 प्रतिशत की छूट ब्याज में दी है। मध्यम वर्गों की एस्पिरेशन होती है कि वह अपना घर बनाए, उसकी उस एस्पिरेशन को पूरा करने का काम हुआ है। यदि 12 लाख रुपए तक का मकान है, तो ब्याज में 3 प्रतिशत रियायत देने का काम किया है। इसी प्रकार से गांवों के अंदर जिनके पुराने घर हैं, अब चूंकि परिवार बड़ा हो गया है, पुराने घर का विस्तार करना है या उसमें एक कमरा बनाना है या दो कमरे बनाने हैं, तो 2 लाख रुपए तक कर्ज में हमने 3 प्रतिशत रियायत दी है। ये सारी चीजें मध्यम वर्ग और निम्न-मध्य वर्ग को अपनी एस्पिरेशन्स को पूरा करने में बहुत काम आने वाले विषय हैं।

महोदय, उसी प्रकार से रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट यानी 'रेरा' बनाया गया है। मध्यम वर्ग जो अपना मकान बनाने के लिए चिन्तित रहता था, उसे इसके माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई है। हमने उसमें कई संशोधन किए हैं, जिनका लाभ सामान्य वर्ग को मिलेगा। हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और उसमें कंज्यूमर एम्पावरमेंट पर भी बल दिया है। लोगों को सस्ती दवा मिलें, इसके लिए भारतीय जन औषधि केंद्रों की स्थापना की है और 800 से ज्यादा दवाएं बहुत सस्ते में दी हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग इन दवाओं का सेवन कर रहे हैं, उनका दवाओं पर अब 60 से 70 परसेंट तक कम खर्चा हो रहा है। हमने 'नी इम्प्लांट्स' का खर्च कम किया है। हमने स्टेंट का खर्च कम किया।

महोदय, हमारे देश में इन दिनों किडनी की समस्या बहुत ज्यादा हुई है। हमारे यहां रूटीन व्यवस्था में डायलिसिस के लिए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर या बड़े शहर में जाना पड़ता था। हमने एक मिशन मोड में काम किया। करीब 500 से अधिक जिलों में बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर यह डायलिसिस का मूवमेंट चलाया है। अब वहां तक हम पहुँचे हैं, अब तक की मेरी जानकारी है कि करीब 22 लाख से ज्यादा डायलिसिस के सेशंस हुए। ये सारे मानवता की दृष्टि से करने वाले काम हैं, जिन पर हमने बल दिया है। एलईडी बल्ब के कारण क्या लाभ हो रहा है, यह आप भली-भांति जान रहे हैं। हजारों करोड़ रुपये मध्यम वर्ग की जेब में बच रहे हैं, करीब-करीब 15 हजार करोड़ रुपये बच रहे हैं।

राष्ट्रपति जी ने एक विषय अपने भाषण में कहा है और उस विषय में मेरा मत है कि यह कोई सरकार का काम नहीं है और न ही यह किसी दल का काम है, बल्कि देश की जिनको चिन्ता है, ऐसे सभी लोगों का यह काम है और इस सदन में बैठे हुए हर किसी का काम है तथा

सबका बराबर काम है। वह विषय राष्ट्रपति जी ने स्पर्श किया। पहले जब प्रणब दा राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने भी उल्लेख किया था और इससे पहले भी कई लोगों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। वह है – लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव साथ करवाना। यह ठीक है कि राज्य सभा में जो आते हैं, उनको यह चुनाव की आपा-धापी क्या होती है ...**(व्यवधान)**... जो लोक सभा और राज्य सभा दोनों में आये हैं, उनको पता है। कुछ लोग पराजित होकर बाद में राज्य सभा में पहुँचते हैं, उनको भी यह अनुभव है कि क्या कठिनाई रहती है, लेकिन कभी सोचना होगा ...**(व्यवधान)**... कभी सोचना होगा कि एक स्वस्थ परम्परा हो, क्योंकि भारत का लोकतंत्र काफी मैच्योर हुआ है। क्या हम सब हिम्मत करके एक स्वस्थ परम्परा की दिशा में जा सकते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि 1967 तक यह चला है। लोक सभा और विधान सभा चुनाव साथ हुए हैं। यह लगभग 1967 तक चला है। उसमें शायद एक-दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन यह चला है। उस समय किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन बाद में किसी न किसी राजनीतिक कारणों से असंतुलन पैदा हुआ और आज हम देखते हैं कि एक चुनाव आया, वह पूरा हुआ तो दूसरे की तैयारी हो जाती है, दूसरा पूरा होता है, तो तीसरा..। अब इसका दबाव केंद्र सरकार पर और राज्य सरकारों पर रहता है। फेडरल स्ट्रक्चर के अन्दर एक सुखद एट्मॉस्फेयर होना चाहिए। चुनाव के चार-छः महीने हम समझ सकते हैं कि तू-तू, मैं-मैं चल जाए, लेकिन चार-साढ़े चार साल तो कम से कम हम मिल-बैठ कर देश के लिए काम कर सकें, हमारी पूरी शक्ति काम में लगे, उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस दिशा में एक व्यापक चर्चा हो। आप देखेंगे कि अब जब लोक सभा का चुनाव होगा, तो चार राज्य उसके साथ हैं—आंध्र, तेलंगाना, अरुणाचल और ओडिशा। कठिनाइयां क्या हैं, वह हम भली-भांति जानते हैं। 2009 में लोक सभा के चुनाव में करीब-करीब 1,000 करोड़ खर्च हुए। 2014 में यह करीब-करीब 4,000 करोड़ पर पहुँचा। यानी यह 1,000 से 4,000 हो गया। इतना ही नहीं, 2014 के बाद एसेम्बली के जो चुनाव हुए हैं, उनमें अब तक करीब-करीब 3,000 करोड़ खर्च हुए। अब हम यह कल्पना कर सकते हैं कि भारत जैसा देश, जहां गरीबों के लिए बहुत कुछ पहुँचाना अभी हमारी जिम्मेवारी है, हमारे यहां चुनावों के अन्दर 9,30,000 पोलिंग स्टेशंस पर एक करोड़ से ज्यादा लोगों की ड्यूटी लगती है, बहुत बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेज़ चुनाव प्रबंधन में ही लगी रहती हैं, सिक्योरिटी के मसले में नये-नये चैलेंजेज़ उभरते जाते हैं और हमारी फोर्स बस उसी काम में लगी रहती है। यह पक्ष-विपक्ष से परे का विषय है। देशहित के विषय में, हो सकता है कि इसमें मतभेद भी हो, लेकिन तर्क की चर्चा तू-तू, मैं-मैं से न हो, एक प्रामाणिक पवित्रता से हम बहस करें, मिल-बैठ कर कोई रास्ता खोजें। मुझे लगता है कि हम इसे आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। हमने ऐसे बहुत से निर्णय किये हैं, जिनसे दुनिया के देशों को बहुत अजूबा लगता है कि जहां इतनी पार्टियां हों, वहां ऐसा निर्णय हो सकता है! लेकिन इसी सदन में बैठे हुए लोगों ने भूतकाल में किये हैं। श्रेष्ठ निर्णय किए हैं, आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाने वाले निर्णय किए हैं। मैं समझता हूँ कि फिर एक बार दोनों सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों के सामने एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इसको करें। माननीय सभापति जी, सभी महानुभावों ने कई विषय उठाए हैं। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अपने आपमें पूर्ण अभिभाषण है। दिशा क्या है, गति क्या है, इरादे क्या हैं और सामान्य मानवी के हितों की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जितनी समय सीमा रहती है, उसमें उसका एक खाका रख सकते हैं, वह रखने का उन्होंने प्रयास किया है। हम सब सर्वसम्मति से आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को स्वीकृति दें और धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें। इसी एक अपेक्षा के साथ अपना समर्थन देते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद, प्रधान मंत्री जी। अन्तोनी जी।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

SHRI A.K. ANTONY (Kerala): I am sorry to say that the statement of the Prime Minister that your Government has taken a decision on *One Rank, One Pension* is factually wrong. The decision on *One Rank, One Pension* was taken by the UPA Government headed by Dr. Manmohan Singh. My colleague, Shri P. Chidambaram, in his Budget Speech in February 2014 announced that our Government's agreeing to the long-pending demand of service personnel of *One Rank, One Pension* and that it would be implemented from 1.4.2014 onwards. After that, within a few days, I took a meeting with all the three Vice-Chiefs of the armed forces and Defence Secretary and Secretary, Defence Finance, and we had clarified what means *One Rank, One Pension*. *One Rank, One Pension* means the service personnel, who served in the Armed Forces, of the same rank with the same length of service, whichever may be their date of retirement, they will get the same pension. It was our decision, and in the same meeting, we took a decision. We directed the Secretary, Defence Finance, to seek more funds from the Finance Ministry because we needed substantial increase. ...(*Interruptions*)... That decision was taken by our Government and we had also taken steps to implement that decision.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOEY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, these clarifications are not allowed. ...(*Interruptions*)...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, how can this be allowed? ...(*Interruptions*)... It was ₹ 11,000 crore...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments to vote. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: It was not a regular Budget. ...(*Interruptions*)... The Budget had to come after...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendments, which had been moved, to vote. ...(*Interruptions*)... Amendment (Nos.1 to 75) and Amendment (Nos.78 to 81 had been moved by Shri Vishambhar Prasad Nishad. Are you withdrawing the Amendments?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, हमने जो संशोधन रखे थे, वे बहुत महत्वपूर्ण थे। वे बुंदेलखंड की समस्या के बारे में थे, क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बुंदेलखंड को छोड़ दिया गया है, जब कि वहां लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, वहां बहुत विकट समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। इन तमाम समस्याओं को लेकर हमने ये संशोधन रखे थे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you pressing or withdrawing the Amendments? ...(*Interruptions*)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः महोदय, हम यह उम्मीद करते थे कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी अपना उत्तर देंगे, तब वे बुंदेलखंड के बारे में कहेंगे, लेकिन बुंदेलखंड के लोग हताश और निराश हो गए, बुंदेलखंड का किसान ठगा रह गया। आज वहां का किसान बरबाद हो गया है।

श्री उपसभापतिः अब तो प्राइम मिनिस्टर का reply हो गया, इसलिए मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप withdraw करते हैं या नहीं करते हैं?

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः महोदय, चलिए हम withdraw करते हैं।

The Amendment (Nos. 1 to 75 and 78 to 81) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendment (Nos. 91 to 95) by Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the mike is not working.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just check it.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I will proceed. Sir, consequent on bifurcation of the State of Andhra Pradesh, whatever injustice has been meted out to the people of Andhra Pradesh can be remedied by only one person in this country who is none other than the Prime Minister of this country – the hon. Prime Minister Shri Narendra Modi.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you pressing or withdrawing?

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I request the hon. Prime Minister to kindly grant special category status to the residuary State of Andhra Pradesh so that justice can be done to the people of Andhra Pradesh. Yes, I press my Amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. I shall now put Amendment (Nos. 91 to 95) by Shri V. Vijaysai Reddy to vote. The question is:–

91. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the grant of Special Category Status to the residuary State of Andhra Pradesh inspite of the assurance given by the then Prime Minister on the floor of Parliament on 20th February, 2014 and the then Union Cabinet decision on 3rd March, 2014."

92. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the Government's commitments made in Schedule 10 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act,

2014 including establishing a Railway Zone headquartered at Visakhapatnam, an Integrated Steel Plant at YSR District, a port at Duggirajapatnam etc., in Andhra Pradesh."

93. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the Government's commitment to bear the complete costs of the Polavaram National Project at the current, post-2014, price levels."

94. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the address does not mention about fulfillment of the assurance given to the successor State of Andhra Pradesh that package for backward districts of Rayalaseema and North Andhra region would be given on the lines of Bundelkhand in UP and MP and KBK districts in Odisha, as mentioned in the Andhra Pradesh Reorganisation Act 2014."

95. That at the *end* of the motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention that the Government is committed to greater political participation of women by securing passage of the Constitutional Amendment Bill for the reservation of seats for women in Parliament and State Legislatures at the earliest."

The Amendment (Nos. 91 to 95) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Amendment (Nos. 96 to 107) by Shri Naresh Agrawal.

श्री नरेश अग्रवालः उपसभापति जी, सदन में माननीय अमित शाह जी और अरुण जेटली जी बैठे हुए हैं। इस देश के निर्माण में खाली एक दल की भूमिका नहीं रही है। ...**(व्यवधान)**... प्रधान मंत्री जी एक ही दल को सारा क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैंने किसी के बेटे को फंसाने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा कि जो कानून बनाते हैं, जब उनके बेटे फंसते हैं तो वे दायें-बायें देखने लगते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैंने किसी के बेटे को फंसाने के लिए बात नहीं कही थी। मैं अपने अमेंडमेंट्स वापस कर रहा हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

The Amendment (Nos. 96 to 107) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Amendment (Nos. 108 to 188) by Dr. T. Subbarami Reddy.

DR. T. SUBBARAMI REDDDY (Andhra Pradesh): Sir, I want to draw the attention of the President of BJP, Shri Amit Shah. The Telugu people are very, very unhappy and also upset and angry with BJP, and as President of BJP, you must

solve their problem. Now, a new capital has to be built. Till today, you have not given sufficient funds. Every time the Finance Minister says that he is giving; the Finance Secretary is coming for discussion. But, that is not sufficient. We have seen that every day, there are agitations in the House by all political parties for giving more funds.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you pressing or not?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I have a chance to speak on this occasion. I have 80 Amendments, not one or two. Therefore, I would like to draw the attention of the Finance Minister also to see that justice is done to the six crore people of Andhra Pradesh. Otherwise, Amit Shahji, आपका नुकसान हो जाएगा, तेलुगु लोगों के मन में बीजेपी का नाम खराब हो जाएगा। आप ऐसा मत करिए। I Do justice. I am not pressing the Amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

The Amendment (Nos. 108 to 188) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Amendment (Nos. 194 to 217) by Shri Kiranmay Nanda.

श्री किरनमय नन्दा (उत्तर प्रदेश): मैंने जो अमेंडमेंट्स दिए थे, प्रधान मंत्री जी के जवाब में, उनमें से किसी का कुछ रिप्लाई नहीं मिला। तब भी परम्परा के अनुसार, मैं अपने अमेंडमेंट्स withdraw करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

Amendment (Nos. 194 to 217) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Amendment (Nos. 218 to 231) by Shri T.K. Rangarajan.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I press Amendment (No. 228).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, the other Amendments you are withdrawing!

SHRI T. K. RANGARAJAN: Other Amendments I am withdrawing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Therefore, let me first do that. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, in this regard ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not your Amendment. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: I have an Amendment (No. 245) ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will come to you. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, Amendment (No. 245) is a similar Amendment. ...(*Interruptions*)... It is the same Amendment. I will read out. "but regret that the Address does not mention about the delay in passing the legislation..."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rajaji, let us not confuse. ...(*Interruptions*)... I will come to your Amendment. At that time, you say that.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, it is the same Amendment. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: At that time, you can say, 'similar Amendment is withdrawn.' That is enough. ...(*Interruptions*)... Now, let me do with it. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: We are asking for the voting together. ...(*Interruptions*)... Amendments are the same. So, why do you not put it together? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, No. ...(*Interruptions*)... Are you also pressing? ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Yes, he is also pressing. ...(*Interruptions*)... Amendments are same. ...(*Interruptions*)... Why do you not club these together and have voting together? ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, it is Amendment (No. 245). That is what I am saying. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to see Amendment (No. 245). ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: I can read that out for the benefit of the House. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: This Government is much worried about women. Just now, the Prime Minister also spoke about women. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, it is Amendment (No. 245). ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: My point is this. It is a long pending demand. ...(*Interruptions*)... This House had already passed it and because the other House did not pass it, it lapsed. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One second. ...(*Interruptions*)... Let me see. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: All the BJP Members had supported it. ...(*Interruptions*)... Now, let me see. I am pressing the Amendment (No. 228). ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Mr. Rangarajan. ...(*Interruptions*)... There is no problem. ...(*Interruptions*)... You can press. Let me do my job. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, Amendment (No. 245). ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ...(*Interruptions*)... His Amendment (No. 228) is, "That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

> "but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to pass Women Reservation Bill." It is Amendment (No. 228). And yours is?

SHRI D. RAJA: Sir, it is Amendment (No. 245).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment (No. 245). ...(*Interruptions*)... Let me see whether it same. ...(*Interruptions*)... Let me see. Amendment (No. 245) is, "That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

> "but regret that the Address does not mention about the delay in passing the legislation on Reservation for women in the Parliament and State Assemblies." Let me see, one second. No, both are not same.

SHRI D. RAJA: It is the same' Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, you see. ...(*Interruptions*)... One is, "but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to pass..." The other is, "but regret that the Address does not mention about the delay in passing..." Both are materially different. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: No, Sir. ...(*Interruptions*)... The idea is the same. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Both are materially different. ...(*Interruptions*)...

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, my Amendment is also the same. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: The idea is the same. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What about you? ...(*Interruptions*)... I will get your case. ...(*Interruptions*)... Mr. Raja, I will call your name. Then, you deal with that. ...(*Interruptions*)...

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, my Amendment is also the same. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, what is the number of your Amendment? ...(*Interruptions*)...

SHRI HUSAIN DALWAI: Amendment (No. 302). ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: '302' is a very dangerous number. ...(*Interruptions*)... Amendment (No. 302) is, "but regret that the Address does not mention about the lack of interest of the Government to introduce the Women's Reservation Bill..." That is also different. That is about introduction. ...(*Interruptions*)... You cannot club like that. You can only club if both are substantially and materially the same. These three are different. One is about intention of introducing. The other is about the delay, so I will have to take them separately. So, let me come to Amendment (Nos. 218 to 231) by Shri Rangarajan, out of which he is only pressing Amendment (No. 228). Therefore, let me first.....(*Interruptions*)... Are you withdrawing? ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: No, I am pressing. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Except Amendment (No. 228), the remaining you are withdrawing! ...(*Interruptions*)... Therefore, you say that. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: I am pressing for Amendment (No. 228).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But you have to say that you are withdrawing others. ...(*Interruptions*)... No, No. ...(*Interruptions*)... You have to say that you are withdrawing the other Amendments. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I am withdrawing others but pressing for Amendment (No. 228).

SHRI ARUN JAITLEY: I do not think, in principle, Members of the House have any difficulty accepting the suggestion. Therefore, let me assure my learned friends who have moved this, since all three are different, we will again try and call meeting with all political parties and try and evolve a consensus to see that if it is possible on this issue. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, do you agree? ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: No, Sir. We have sufficiently waited. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has given an assurance. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, we have sufficiently waited. ...(*Interruptions*)... Only after putting this Amendment, the Government says that it will create a consensus. I am pressing this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, all right. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, please. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, nobody else can speak. ...(*Interruptions*)...

No, no, I can't allow that. ...(*Interruptions*)... Then, I will have to again allow others also. ...(*Interruptions*)... No please, don't do that. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, this is a matter of collective understanding. The thing is, the problem with this Women's Reservation Bill is to arrive at a consensus for different reasons. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, now, has he the leave of the House to withdraw Amendment Nos. (218 to 231) except Amendment No. 228? I hope the House agrees. Therefore, Amendments Nos. (218 to 231) except Amendment (No. 228) are withdrawn. Okay.

The Amendment (Nos. 218 to 231) except Amendment (No. 228) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I am putting Amendment (No. 228) to vote. The question is:

228. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to pass Women Reservation Bill."

SHRI T. K. RANGARAJAN: I demand division. ...(*Interruptions*)... Sir, those who wanted it the last time, now they say, 'No'. Let the world see this. ...(*Interruptions*)... Sir, I want division. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Mr. Chairman, Sir... ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, when I already assured my friend that in spirit we all agree with what he is saying. ...(*Interruptions*)... Ordinarily, we don't amend the President's Address. ...(*Interruptions*)... That is all. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I want division. ...(*Interruptions*)... I want division. ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: Ordinarily, we don't have voting on the President's Address. ...(*Interruptions*)... Therefore, please don't press it. But, in principle, we accept it and we will make an effort. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, last year also we had voted. ...(*Interruptions*)... Sir, I want division. ...(*Interruptions*)... I think this Government will not bring that. I want division. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rangarajanji, I am only saying one point. ...(*Interruptions*)... Let me say. ...(*Interruptions*)... It is with regard to the Address

[Mr. Deputy Chairman]
of the President and it is unusual to have an Amendment, especially, when the Government is giving an assurance. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवालः माननीय उपसभापति जी, जब इस सदन ने एक बिल को पास कर दिया, अब इस सदन का तो कोई अधिकार है नहीं, क्यों खामख्वाह यहां वोटिंग होगी, किसलिए, किसलिए वोटिंग करें? यह तो जबर्दस्ती पोलिटिकल फायदे के लिए राजनीतिक रंग देना चाहते हैं कुछ लोग, जिन्होंने देश बरबाद कर दिया, वे राजनीतिक रंग दे रहे हैं इसके लिए। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। इस पर वोटिंग होती नहीं है, परम्परा रही है। किसलिए वोटिंग हो? जबकि यह सदन पास कर चुका है। **...(व्यवधान)...**

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Last time on this, we had voting here in this House on this issue. ...(*Interruptions*)... So, it is not that कि परम्परा नहीं है। And on subject I differ with Naresh *Bhai*. वह अलग बात है। That the House will decide. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; only this much. ...(*Interruptions*)... The Member has the right to press, I have no problem. ...(*Interruptions*)... But I am only saying that it is quite unusual to have Amendment to the President's Address. ...(*Interruptions*)... That is number one. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Two times in the past, we had moved an Amendment and the Amendment was carried out. ...(*Interruptions*)... I think, one of the Amendments was my Amendment. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But, here, the Government is giving an assurance that they will.... ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, we have passed this Bill in this House and, in spite of that, they have not taken any step to pass it. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: With a huge majority in that House, they were not prepared to pass it. ...(*Interruptions*)... What prevented them from passing it? ...(*Interruptions*)...

SHRI ARUN JAITLEY: I want the LoP to know that after it was passed in this House, we supported it. And, for three years, you were still in power and did nothing. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: On this, we didn't have the majority and you have the majority. We were running a coalition Government and some partners of coalition Government did not want it. ...(*Interruptions*)... We brought that Bill but some coalition partners did not want it because we didn't have the majority in the other House. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My suggestion is... ...(*Interruptions*)... My suggestion is... ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: One second, Sir. This House passed the Bill on Women Reservation. It is true that the Rajya Sabha passed it and it has to be taken up in Lok Sabha and passed by the Lok Sabha. ...(*Interruptions*)... Why is the delay? ...(*Interruptions*)... Why is the delay? I am asking all the political parties. The Leader of the House is correct that there is a common understanding but why it is delayed. ...(*Interruptions*)... Why is it not being taken up? That is what my Amendment says. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; it is time for voting. ...(*Interruptions*)... Now, you sit down. ...(*Interruptions*)... It is time for voting. Now, the point is, I am only requesting that instead of this kind of an argument, let us all try to pass that Bill, the Women's Reservation Bill. All of you should sit together ...(*Interruptions*)..

SHRI T. K. RANGARAJAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, I want division on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you sticking to that?

SHRI T. K. RANGARAJAN: Yes; definitely.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am putting it to vote. I shall now put the Amendment to vote. Amendment is already read out. You all know the Amendment. I shall now put the Amendment to vote. Do you want division?

SHRI T. K. RANGARAJAN: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; let the lobbies be cleared.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, since the Government has given assurance to bring the Bill in Lok Sabha, we are supporting.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What to do? It is not my job. What can I do? I requested them. What more can I do? I have to go by the rules. I can only request; otherwise, I have to go by the rules. You can pursue the Member. Mr. Navaneethakrishnan, you can pursue the Member even now.

SHRI T. K. RANGARAJAN: No, Sir. I want division.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I did not talk to you. Okay, have the lobbies been cleared? ..(*Interruptions*).. Please go to your seats. ...(*Interruptions*)... Please go to your seats. Are Lobbies cleared? ...(*Interruptions*)... The Secretary-General will explain the voting procedure ...(*Interruptions*)... Order, please. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Order, please. ...(*Interruptions*)... Order, please ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I put the Amendment No.228 moved by Shri T.K. Rangarajan to vote.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: You are all anti-women. Thank you!

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Why did you not do it when you were in power?... (*Interruptions*)... The whole country has witnessed you...(*Interruptions*)... You had no courage to do it when you were in power...(*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am a failure before the shouting of women Members. We are seeing women empowerment in India. Now, the question is:

228. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the Government's failure to pass Women Reservation Bill."

The House divided

Ayes : 57

Noes : 86

AYES : 57

Abraham, Shri Joy

Anand Sharma, Shri

Azad, Shri Ghulam Nabi

Babbar, Shri Raj

Bajwa, Shri Partap Singh

Banerjee, Shri Ritabrata

Batra, Shri Shadi Lal

Bora, Shri Ripun

Budania, Shri Narendra

Chavan, Shrimati Vandana

Chidambaram, Shri P.

Chowdhury, Shrimati Renuka

Dalwai, Shri Husain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Elangovan, Shri T. K. S.

Fernandes, Shri Oscar

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Gupta, Shri Sushil Kumar

Hariprasad, Shri B. K.

Kalita, Shri Bhubaneswar

Khan, Shri K. Rahman

Kujur, Shri Santiuse

Mahra, Shri Mahendra Singh

Memon, Shri Majeed

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Mukut Mithi, Shri

Narayanan, Shri C. P.

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patil, Shrimati Rajani

Pawar, Shri Sharad

Punia, Shri P. L.

Ragesh, Shri K. K.

Raja, Shri D.

Rajaram, Shri

Ramamurthy, Shri K. C.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T. K.

Ravi, Shri Vayalar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Selja, Kumari

Sen, Shri Tapan Kumar

Shukla, Shri Rajeev

Singh, Shri Sanjay

Sinh, Dr. Sanjay

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shrimati Ambika

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Shrimati Viplove

Tirkey, Shri Dilip Kumar

Tiwari, Shri Pramod

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tulsi, Shri K. T. S.

Verma, Shrimati Chhaya

NOES-86

Agrawal, Shri Naresh

Arjunan, Shri K. R.

Athawale, Shri Ramdas

Bharti, Shrimati Misha

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Dasgupta, Shri Swapan

Desai, Shri Anil

Dhindsa, Sardar Sukhdev Singh

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Fayaz, Mir Mohammad

Ganesan, Shri La.

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawar Chand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Goyal, Shri Piyush

Harivansh, Shri

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jain, Shri Meghraj

Jaitley, Shri Arun

Jangde, Dr. Bhushan Lal

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Judev, Shri Ranvijay Singh

Katiyar, Shri Vinay

Khan, Shri Javed Ali

Lakshmanan, Dr. R.

Laway, Shri Nazir Ahmed

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Maitreyan, Dr. V.

Malik, Shri Shwait

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mathur, Shri Om Prakash

Muthukaruppan, Shri S.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Navaneethakrishnan, Shri A.

Netam, Shri Ram Vichar

Sitharaman, Shrimati Nirmala

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

Panchariya, Shri Narayan Lal

Patil, Shri Basawaraj

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Ramesh, Shri C. M.

Rangasayee Ramakrishna, Shri

Rao, Shri Garikapati Mohan

Sable, Shri Amar Shankar

Sahani, Dr. Anil Kumar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Sancheti, Shri Ajay

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Seth, Shri Sanjay

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Sinha, Shri R. K.

Suresh Gopi, Shri

Thakur, Dr. C. P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tiwari, Shri Alok

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vegad, Shri Shankarbhai N.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shri Ravi Prakash

Vijila Sathyananth, Shrimati

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

The Amendment (No. 228) was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up Amendment (Nos. 232 to 259) by Shri D. Raja. Shri D. Raja, are you pressing your Amendments?

SHRI D. RAJA: Sir, among my Amendments, the Amendment (No. 245) was similar to the Amendment which we voted upon. But, among other Amendments, I thought the Prime Minister will squarely respond to certain issues, that is, the increasing attack on the ideals of our Constitution. The Prime Minister did not respond at all. He did not touch upon that point at all, So, I have no other option but to press these Amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, I am going to put it to vote. Now, I am putting Amendment Nos. (232 to 259) by Shri D. Raja to vote. The question is:–

232. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not reiterating India's commitment to pursue an independent foreign policy."

233. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not refer to the continuous attack on the ideals enshrined in the Constitution of the country."

234. That at the end of the Motion, the following be added, namely:–

"but regret that the Address does not refer to the increasing attack on the constitutional and democratic rights of the citizens."

235. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not refer to the issue of judicial accountability and to the prevailing crisis in judiciary in general and higher judiciary in particular."

236. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not express its serious concern over the increasing incidents of atrocities on people of Dalit communities in the country."

237. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the need to repeal the archaic sedition law which is not needed in the democratic India."

238. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take note of attempt to take away the land rights of tribals given under the Forest Rights Act to facilitate coal mining in certain tribal villages."

239. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the need to enact a central legislation for the welfare and security of the agricultural workers in the country."

240. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take note of the attempts to curtail trade union rights of the workers in the name of ease of doing business."

241. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take note of the prevailing crisis in the agriculture sector and increasing incidents of farmers committing suicide in the country."

242. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the abnormal increase in the Non-Performing Assets (NPAs) of the public sector banks and the need to take stringent measures to recover the defaulted loans from the wilful defaulters particularly in the corporate sector."

243. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take note of the continuous slow down in the growth rate of economy."

244. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take note to attract the continuous decline in India's export during the last few years."

245. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the delay in passing the legislation on Reservation for Women in the Parliament and State Assemblies."

246. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take note of the deteriorating quality of education, particularly at the higher level in the country."

247. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the increasing commercialization of education sector making it impossible to get quality education for the common people."

248. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take note of the deteriorating condition of the public health facilities in the country compelling the poor patients to avail medical treatment from costly private medical institutions."

249. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the increasing incidents of crime against women and children in the country."

250. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to solve the problem of unemployment particularly of the educated youth in the country."

251. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the need to recognize the 'scheme workers' numbering a crore in the country mostly women working under various schemes of the Government of India, as workers, as per the recommendations of the 45th Indian Labour Conference making them eligible for PF, ESI and other social security benefits."

252. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take note of the increasing attacks on the tribal people in the country, particularly in Chhattisgarh."

253. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take note of the fact decision of demonetization of currency notes of ₹ 500 and ₹ 1000 denominations pushed the economy as well as the common people into a distressful condition."

254. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take note of the fact that certain right wing forces in the country are trying to destroy the secular-democratic fabric of the country by attacking the Universities, all educational and cultural institutions, freedom of speech, right to dissent, minorities, dalits, tribals and progressive activists."

255. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the diversion of allocations made for sub-plans for Tribals and SC/ST."

256. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the increasing number of derailments in Railways due to deterioration of safety standards and ignoring the recommendations of various reports on accidents in the Railways."

257. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the continued protest of the Ex-service men demanding full implementation of the One-Rank-One-Pension (OROP)."

258. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the thousands of villages still remain without electricity in the country."

259. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the disinvestment of the public sector undertakings thereby weakening the fundamentals of the economy."

The Amendment (Nos. 232 to 259) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up Amendment Nos. (261 to 268) by Shri K. Rahman Khan. Mr. Khan, are you pressing these Amendments?

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Sir, I move my Amendment regarding the statement of the President to Parliament that for decades, the dignity of the Muslim women has remained a captive, political cost benefit. Now, the nation has an opportunity to emancipate them ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, order please.

SHRI K. RAHMAN KHAN: *

because 1400 years back, this Islam had given dignity for women. Today, don't make it a political issue. You have not studied Islam. We are not in favour of triple talaq. Nowhere, was there triple talaq. It was a convention remaining. After the Supreme Court's decision, it became illegal, unconstitutional. Purposely, deliberately,

*Expunged as ordered by the Chair.

this Government has brought this Bill. There was no need for this Bill because she remains your wife. Even if you pronounce three talaqs, she remains your wife. Then, we had not opposed the Bill. We only wanted discussion. Just now, the hon. Finance Minister and Leader of the House said, 'We will consult on the Women's Bill; we will have a consultation.' Why not on this Bill? Why are you adamant? We are saying that there are many lacunae. It is legislation and please take care. Then we will legislate it. We want this Bill. We did not say that we don't want this Bill. What we said is that there is a need. It is insulting the community and insulting Islam. Under the Constitutional mechanism, you have to consult; but you have not consulted the Muslim community. You have not consulted the other political parties. You are insisting that...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, are you pressing?

SHRI K. RAHMAN KHAN: I am pressing for my Amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (Nos. 261 to 268) by Shri K. Rahman Khan to vote. So, the question is:–

261. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address fails to mention about the dignity and pride that a Muslim woman enjoys under Shariah Law and has therefore, undermined the status of Muslim women."

262. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the condition of the 85% women from religions other Muslim in the country, who are facing daily harassment and are fighting legal battles after their husbands have deserted them for years without any maintenance and without even giving divorce, and the Government's policy about such women."

263. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address fails to mention that the relaxation given to the women above 45 years of age to perform Haj Pilgrimage in a group of four is as per the new guidelines and exemptions given by the Saudi Government from the ensuing Haj season and that the Indian Government has adopted the new Saudi policy."

264. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take notice of the plight of the Muslim women who are socially and educationally backward and have negligible representation in Government Services."

265. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address fails to mention the reasons as to why subsidy on Haj had to be abolished with immediate effect and the amount of subsidy Government was paying."

266. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not take notice of the increased incidents of Communal violence's in the country."

267. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the alarming financial health of the Indian Banks due to increase in NPA's of the Public and Private sector Banks which according to Finance Ministry stands at ₹ 7,73,974 crore and ₹ 1,02,808 crore, respectively as on 30.09.2017."

268. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address fails to mention the reasons as to why the Petrol and Diesel prices were not reduced proportionately in spite of a huge fall in the oil prices at the international market."

The Amendment (Nos. 261 to 268) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Amendment (Nos. 269 to 272) moved by Shri K.K. Ragesh. Mr. Ragesh, are you pressing?

SHRI K. K. RAGESH: Sir, I am really concerned about the growing attacks on the freedom of speech and expression. We have seen assault on democracy in our country. Gauri Lankesh, Kalburgi and others have been killed. Media persons are also being killed. Sir, I am pressing for the Amendments.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (Nos. 269 to 272) by Shri K. K. Ragesh to vote. So, the question is:–

269. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the growing attack on freedom of speech and expression as manifested in the henious killings of Gauri Lankesh, Kalburgi, Narender Dhabolkar, Govind Pansare, etc."

270. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the drastic cut in subsidies including fertilizers, LPG, Diesel etc."

271. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the growing NPA in public sector banks and the Government's decision to write off the NPA as book adjustment."

272. That at the end of the Motion, the following be added, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the injustice by State Bank of India in imposing fine on poor account holders who are unable to maintain monthly average balance."

The Amendment (Nos. 269 to 272) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Amendment (Nos. 273 to 297) by Shri Motilal Vora. He is not present. He has already moved the Amendments. Therefore, I am putting those Amendments to vote.

The Amendments (Nos. 273 to 297) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Amendment (Nos. 298 to 324) by Shri Husain Dalwai. Mr. Dalwai, are you pressing?

श्री हुसैन दलवईः सर, गौहत्या के नाम पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और दलितों के ऊपर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। मैं यहां पर ये बातें रखना चाहता हूं। आज रोड्ज़ के ऊपर बड़े पैमाने पर एक्सिडेंट्स हो रहे हैं, खासकर मुम्बई, गोवा में एक्सिडेंट्स हो रहे हैं। मैं यह अमेंडमेंट प्रेस कर रहा हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (Nos. 298 to 324) by Shri Husain Dalwai to vote. The question is:–

298. That at the *end* of the Motion the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about rising intolerence in the form of attacks on minority communities by vigilante groups and failure of Government to protect these communities."

299. That at the *end* of the Motion the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about attacks on Dalits in states like Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh."

300. That at the *end* of the Motion the following be *added*, namely:–

"but regret that there is no mention in the Address about the inability of the Government to ensure protection of women from sexual and physical abuse, to utilise the Nirbhaya Fund and to criminalise marital rape."

301. That the *end* of the Motion the following be *added*, namely:–

"but at regret that there is no mention in the Address about the failure of the Government in addressing concerns of the transgender community in the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016 and extending reservation benefits to them."

302. That at the *end* of the Motion the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the lack of interest of the Government to introduce the Women's Reservation Bill on a priority basis."

303. That at the *end* of the Motion the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the rising Non-Performing Assets (NPAs), failure of Public Sector Banks to recover these NPAs even though banks go about collecting charges from account holders who are unable to maintain minimum balance."

304. That at the *end* of the Motion the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not condemn the inability of the Government to take adequate steps for welfare of unorganized sector workers."

305. That at the *end* of the Motion the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention the need to reduce dependence of farmers on informal sources of capital and instead increase access to formal institutionalized source of capital and the need to encourage organised retail to prevent market dominance as well as allow easy access to land through leasing and contract farming models."

306. That at the *end* of the Motion the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the fall in prices of crops as well as climate change induced temperature and rainfall ariability affecting farmer's earnings leading to rise in farmer suicides."

307. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about rising income inequality in India."

308. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention the failure of the Government to adequately address the issue of manual scavenging despite the enactment of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation act."

309. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention the issue of low adoption rate of technology, in rural areas due to lack of technology enablers, which is making schemes related to e-health, e-governance, e-education and e-commerce ineffective."

310. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the problem of malnutrition faced by India, which ranks 100 out of 119 countries on the Global Hunger Index."

311. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention that while providing Constitutional status to the National Commission of Backward Classes, there are apprehensions over diluting the existing powers of the Commission."

312. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention the attempts being made to dilute the protection provided to tribals under the Forest Rights Act, through several measures, for instance by delay for the formulation of rules under the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016."

313. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not condemn the mistreatment of activists protesting against increasing height of Sardar Sarovar Dam and displacement of several people without adoption of adequate rehabilitation measures."

314. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about attacks on free speech and the inability of the Government to protect journalists, RTI activists, whistleblowers who stand for free speech."

315. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address fails to mention that the introduction of electoral funds will adversely affect transparency in election funding and strengthen the business political nexus.

316. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the lack of steps taken to ensure preparedness and build capacity to deal with natural disasters of many States suffered immense loss of life and property due to Cyclone Ockhi, one of the most intense cyclones in the country, due to their unpreparedness."

317. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to stabilize the situation in Jammu and Kashmir and the lack of clarity with respect to the role of representative of the Indian Government appointed to conduct talks with different stakeholders."

318. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention that India is one of the four worst performing countries (ranked 177 out of 180 countries) in the Environmental Performance Index 2018."

319. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention the increasing number of road accidents and inadequate measures to upgrade quality of roads and incomplete and slow construction work on NH-66, connecting Mumbai to Goa, which has caused several road accidents killing many people every year."

320. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention that anganwadi workers are not receiving timely payment of wages."

321. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention the issues faced due to linkage of Aadhaar, including security issues like bank frauds, authentication failures leading to exclusion deaths and disruptions in availability of entitlements under various welfare schemes."

322. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention the increasing train accidents, poor railway infrastructure and inadequate investment is safety as in a short period of 1 August and 30 November, 2017, 30 train accidents killed 35 people and injured more than 180 people resulting in the highest death toll from train derailments in 2016-17."

323. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention about high rates of GST on basic necessities like sanitary napkins and assistance devices for persons with disabilities."

324. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:–

"but regret that the Address does not mention the insufficient investment in welfare of fishermen to create necessary infrastructure and protect their rights and interests."

The Amendment (Nos. 298 to 324) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now I shall put the Motion to vote.

The question is:–

"That an Address be presented to the President in the following terms–

'That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 29, 2018'."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the lobbies be cleared.

STATUTORY RESOLUTION

Increasing the rate of Basic Customs Duty (BCD) on chana (chickpeas)

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I move that:

"In pursuance of Section 8A (1) of the Customs Tariff Act, 1975, read with sub-section (3) of Section 7 of the said Act, this House hereby approves of Notification No.25/2018-Customs, dated 6th February, 2018 which seeks to increase the rate of Basic Customs Duty (BCD) on chana (chickpeas) falling under tariff item 0713 20 00, of the Customs Tariff Act from 30% to 40%."

The questions were proposed.

WITHDRAWAL OF MEMBER — *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Along with the Budget, you can speak about the Resolution also. Now, we will take up discussion on the Union Budget 2018-19 and Resolution also you can discuss. ...(*Interruptions*)... Hon. Shri P. Chidambaram. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... That was only assured. ...(*Interruptions*)... What is your problem? ...(*Interruptions*).. Order, please. ...(*Interruptions*).. You please